सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

10 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 10 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 21 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, 6 साल की बच्ची के साथ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री जिवेश कुमार ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, शून्यकाल में बोलियेगा ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–9, श्री जिवेश कुमार (क्षेत्र सं0–87, जाले)

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : 1– आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प वन्यप्राणी–02/2002–369(ई0), दिनांक– 19.07.2024 के माध्यम से चिन्हित जंगली जानवरों द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं संपत्ति को हुई क्षति के लिए सहायता राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है।

2–स्वीकारात्मक ।

3–आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक–1213, दिनांक 24.03.2022 से राज्य में सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को राज्य आपदा रिस्पौन्स कोष/राष्ट्रीय आपदा रिस्पौन्स कोष से अनुग्रह अनुदान के भुगतान का प्रावधान किया गया है। राशि का भुगतान आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, द्वारा किया जाता है। इसलिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के स्तर से सर्पदंश के मामलों में सहाय्य राशि भुगतान के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बुलवायेंगे । सरकार संज्ञान ले ली है । सबलोगों को समय पर बोलने के लिए मौका दिया जाएगा । अभी सबलोग बैठिये ।

श्री संदीप सौरभ : सरकार से जवाब दिलवाइये, महोदय ।

अध्यक्ष : जवाब मिलेगा ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, पूरे बिहार में घटनाएं हो रही है और सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : जिवेश जी आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : सरकार का उत्तर प्राप्त है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि सांप जो है,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप सभी लोग बैठ जाइये । शून्यकाल में अपनी बात बोलियेगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका दिया जाएगा । आपको शून्यकाल में प्रश्न पूछने का मौका दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार : वो पालतू है या फालतू है या जंगली जानवर है ? माननीय मंत्री जी इतना हमको बताएं कि सांप जो है वो जंगली जानवर है कि पालतू जानवर है? इतना बताएं फिर अगला प्रश्न है मेरा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सांप जंगली जानवर की श्रेणी में आता है। लेकिन वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी वन्यप्राणी 02/2002–369(ई0), दिनांक– 19.07.2024 के माध्यम से चिन्हित जंगली जानवर द्वारा मानव जीवन, पशुधन, फसल एवं संपत्ति की हुई क्षति पर सहायता राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, मैं केवल इतना पूछा हूं कि सांप जंगली जानवर है कि पालतू?

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : जंगली जानवर है। सांप जंगली जानवर है।

श्री जिवेश कुमार : माननीय मंत्री जी ने कहा सांप जंगली जानवर है। हुजूर, बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है, यह 02/2002–369(ई0), दिनांक– 19.07.2024 का बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है। इसमें सर्पदंश से मरने वाले लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी इसको आपदा में डालकर गरीब आदमी, जिसके परिवार का प्रमुख व्यक्ति चला गया हो...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपने कार्यस्थगन दिया है उसको समय पर उठाइयेगा । हम आपको शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे ।

श्री जिवेश कुमार : उसको केवल 4 लाख रुपया दिया जाता है हुजूर। ये सरकार अभी सुनिश्चित करे कि अगर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, सरकार ने जवाब दिया जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर के लिए जो सरकार का नोटिफिकेशन है कि 10 लाख रुपया मुआवजा जंगली जानवर से मरने वाले

व्यक्ति/मृतक के परिजन को सरकार देगी। परंतु सांप को आपदा प्रबंधन के द्वारा केवल सांप के मृतक पर 4 लाख रुपया दिया जाता है। मैं सरकार से चाहता हूं कि सरकार आज सदन में घोषणा करे कि 2024 के नोटिफिकेशन के हिसाब से, जिस प्रकार बाघ, जंगली सुअर के कारण मरने वाले को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलता है, वैसे ही सांप के मृतक, जो वन्य प्राणी सांप है, उसके सर्पदंश से भी मरने वाले को सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा क्या देगी ?

(व्यवधान जारी)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, ये सांप को इससे अलग रखा गया है, वह जंगली जानवर है लेकिन इसको अलग रखा गया है। जंगली जानवर, वन्य प्राणी में जैसे बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सुअर...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी माइक पर बोलिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : लक्कड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ एवं घड़ियाल ऐसे जानवरों से यदि मानव की क्षति होती है, उसके लिए सरकार 10 लाख रुपये की सहायता राशि देती है। सांप इससे अलग है, सांप जंगली जानवर है, जंगली जानवर में, अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे जीव हैं लेकिन सब जीव के लिए मानव क्षति पर सहायता राशि नहीं मिलती है।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : मार्शल जहां भी हों पोस्टर हटवाइए। मार्शल पोस्टर हटवाइए। सदन में तख्ती लेकर आना प्रतिबंध है। इनके पोस्टर हटाइए। हमने कहा है, शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे। शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे, अभी बैठ जाइए। मेरा आग्रह मानिए और बैठिए, शून्यकाल में बोलने का आपको मौका देंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण जो विपक्षी दल के हैं लगातार सदन में नारे लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जवाब दें और जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ सारा मंत्री परिषद यहां मौजूद है । विपक्षी साथी सवाल पूछे और सवाल पूछने की प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित है । अनेक तरह के प्रस्ताव है गंभीर से गंभीर, संवेदनशील से संवेदनशील विषयों को भी उठाने का तरीका नियमावली में प्रावधानित है । ये उसके तहत सवाल उठाए, सरकार हमेशा तैयार है जवाब देने के लिए ।

अध्यक्ष : बिल्कुल । अब बैठ जाइये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है ।

अध्यक्ष : सरकार जवाब देगी, पहले बैठिये । आपको शून्यकाल में बोलने का मौका दिया जाएगा । अभी बैठ जाइये, मेरा आपसे आग्रह हैं । प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर बैठ गए)

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जंगली जानवर सांप है लेकिन सांप के सर्पदंश के लिए सरकार ने अलग व्यवस्था बनायी है, किस नोटिफिकेशन से अलग व्यवस्था बनायी है । माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : हम आपको शून्यकाल में बोलने का मौका देंगे । हम आपको जीरो ऑवर में बोलने का मौका देंगे तब बोलियेगा ।

श्री जिवेश कुमार : माननीय मंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि सांप को वन्य प्राणी से अलग रखा गया है, मुआवजा में अलग रखा गया है, उसका नोटिफिकेशन कहां है, एक मिनट आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

जबकि मैं प्रमाण के साथ सदन में 2024 का बिहार सरकार का नोटिफिकेशन है ।

अध्यक्ष : अब हो गया । बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : सर, एक ओर बात मैं आपको जानकारी के लिए सदन में देना चाहता हूं कि इसके पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने...

श्री भाई वीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है....

अध्यक्ष : आपका मामला गंभीर है । हम जान रहे हैं ।

(व्यवधान)

आप गंभीरता खत्म कर रहे हैं । आप अपने स्थान पर बैठ जाइये । आप गंभीरता खत्म मत कीजिए । शून्यकाल में आपको बोलने का अवसर दिया जाएगा, तब आप जरूर बोलियेगा ।

(व्यवधान)

मेरा आलोक जी से आग्रह है कि शून्यकाल में प्रश्न उठायेंगे, सरकार उस पर जवाब देगी । अभी बैठ जाइये ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, माननीय मंत्री जी के और पुराने माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में 3 मार्च, 2020 को जवाब दिया था....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिए ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : ठीक है ।

श्री जिवेश कुमार : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष : ठीक है, आपका विषय आ गया है ।

(व्यवधान)

श्री जिवेश कुमार : महोदय, उप मुख्यमंत्री की बात और तत्कालीन पयार्वरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने माना है कि सांप को वन्य प्राणी में रखकर वन्य प्राणी के बराबर मुआवजा मिलेगा । यह सदन का बयान है हुजूर।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी दिखवा लीजिएगा ।

श्री जिवेश कुमार : हुजूर, उनका सदन में बयान है ।

अध्यक्ष : आपकी बात संज्ञान में माननीय मंत्री जी के आ गयी है । माननीय मंत्री जी निश्चित तौर इस पर विचार करेंगे ।

माननीय सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अल्पसूचित प्रश्न सं0–10, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र सं0–23, रीगा)

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, पूछता हूं । उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शिक्षा विभाग । जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : बिलकुल सरकार विचार करेगी, प्लीज बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी को कहा गया सरकार विचार करेगी । बैठिये ।

श्री जिवेश कुमार : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आपने सारी बातों को रख दिया है । अब बात आगे बढ़ गये हैं । बैठ जाइये। आपको इतना समय दिया गया है ।

(व्यवधान)

बिलकुल सही समय दिया गया । अब बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी जवाब पढ़ दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक ।

विभागीय पत्रांक 247सी, दिनांक 16.08.2023...

अध्यक्ष : एक मिनट रूक जाइये मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी या विपक्षी दल कुछ भ्रमित या उलझन की स्थिति में हैं। क्योंकि अभी आपने देखा, वो किसी प्रश्न को उठाकर सरकार की तरफ से जवाब चाह रहे थे। वेल में आ गए, सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित करने लगे। आपने अनुरोध किया, फिर सरकार की तरफ से, संसदीय कार्य विभाग की तरफ से हमने अनुरोध किया कि सदन की कार्यवाही चलने दीजिए और गंभीर से गंभीर विषयों को भी उठाने का तरीका नियमावली में प्रावधानित है। उसके तहत उठाइये और सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए हर समय तैयार है । यह सुने, फिर आपके अनुरोध पर जाकर वे अपने स्थान पर बैठ भी गए। कई मिनटों तक बैठे रहने के बाद, फिर पता नहीं क्या आफ्टर थॉट मतलब क्या उसके पश्चात् सोच आई ।

(क्रमशः)

टर्न–2 / हेमन्त / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : बाद में क्या सूझा कि अचानक से उठकर चले गये। पता नहीं आप समझ पाये कि नहीं, हम लोग तो नहीं समझ पाये कि जब बैठ गये, तो फिर क्यों अचानक से उठकर चले गये। इसलिए लगता है कि कुछ उलझन में हैं और उसी उलझन का प्रदर्शन इस तरह की अव्यवस्थित उनके आचरण में होता है। महोदय, हम सिर्फ यही आसन के संज्ञान में लाना चाह रहे थे।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–10, श्री बैद्यनाथ प्रसाद (क्षेत्र सं0–23, रीगा)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमने अपलोड कर दिया है।

1– स्वीकारात्मक ।

विभागीय पत्रांक 247सी, दिनांक 16.08.2023 एवं पत्रांक 262सी, दिनांक 18.09.2023 के द्वारा सभी सरकारी विद्यालयों में साफ–सफाई एवं रख–रखाव का कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से भिन्न–भिन्न एजेंसियों को कार्य का दायित्व सौंपा गया है ।

2– अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय ज्ञापांक–ब0आ0–1459 / 2 / 2023–sec-5-EDU DEPT C No.-277153-02, दिनांक–04.04.2025 में निहित निदेशानुसार सीतामढ़ी के सभी प्रखंडों के सरकारी विद्यालयों में साफ–सफाई एवं रख–रखाव का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है । विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा साफ–सफाई एवं रख–रखाव से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं है ।

3– इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त कंडिका में सन्निहित है ।

महोदय, फिर भी अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो हम मुख्यालय से भी टीम भेजकर उनकी जो भी शिकायते हैं पुनः उनको दिखवा लेंगे, ताकि इसमें कोई त्रुटि न रह जाय।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, इसी में एक पूरक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जो एजेंसियां सफाई का काम करती हैं, उनके भुगतान का दायित्व किनको सौंपा गया है, पहला। दूसरा, जानकारी के लिए सरकार को मैंने विद्यालय समिति के अध्यक्ष के नाते एक दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण किया, फोटो खींचकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया। तब भी, अगर अधिकारियों ने उत्तर दिया है कि सफाई गुणवत्तापूर्ण हो रही है, तो इसका मतलब है कि नीचे के अधिकारी सरकार को वस्तु स्थिति और तथ्य से अनभिज्ञ रख रहे हैं। इसलिए मेरा इस पर सवाल है कि क्या सदन में मेरे द्वारा बताए गए इस आधार पर कि गुणवत्तापूर्ण सफाई नहीं है, सरकार ऐसे विद्यालयों में काम करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध और उत्तर देने

वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अंत में हमने स्वयं कहा कि माननीय सदस्य अगर इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो मुख्यालय से हम लोग टीम भेजकर इसको जरूर पुनः निरीक्षण करा लेंगे, अगर उनकी बात सही हुई। अगर बात सही है,..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार का जवाब हो रहा है। प्लीज, बैठ जाइये।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : तो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : पूर्व में भी एजेंसियों को हटाया गया, अगर कार्य संतुष्ट नहीं है, तो इसको वरीय पदाधिकारी से हम लोग देख लेंगे और जरूरत पड़ी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए, उनको हटाने का भी काम करेंगे और अगर किसी ने गलत रिपोर्ट दी है, तो उस पर भी कार्रवाई, पूर्व में भी हुई, हम लोग करेंगे।

अध्यक्ष : श्री मिथिलेश तिवारी।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार वरीय अधिकारी से कार्रवाई करायेगी।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, भुगतान का क्या हुआ ? भुगतान किनके द्वारा किया जाता है ?

अध्यक्ष : सरकार के संज्ञान में आ गया है। माननीय मंत्री जी, निश्चित तौर पर दिखवा लीजिएगा। पूरे राज्य का मामला है, एक बार आप समीक्षा कर लेंगे।

(व्यवधान)

क्वेश्चन आ गया है। बैठ जाइये।

एक आग्रह आप सबों से है कि जहां भी आप लोग शिकायत देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी को लिखकर दे देंगे। निश्चित रूप से सरकार जांच करायेगी। लिखकर दे दीजिए, पूरे बिहार का मामला है तो।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–11, श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र सं0–99, बैकुण्ठपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के ज्ञापांक–711, दिनांक–05.02.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ऐमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया पर रिट याचिका (सिविल) संख्या–93/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चल रही कार्यवाही के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा महिला विश्व कप कबड्डी चैम्पियनशिप–2025 के आयोजन को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विभाग से उत्तर प्राप्त है, लेकिन उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री मिथिलेश तिवारी : माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इसी के आलोक में महिला वर्ल्ड कप जो बिहार में होने वाला था, जिसकी मेजबानी बिहार को मिली थी और उसको रद्द कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह मामला फाइल हुआ 21 जनवरी 2025 को, सुनवाई हुई 31 जनवरी को, यह केस रजिस्टर हुआ जिसमें अगली डेट 17 फरवरी को है। इसमें मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 4 फरवरी को एक ऑर्डर आता है और उसके बाद भी 4 फरवरी को ऑर्डर आता है, तो इंटरपोल को, सीबीआई को, सबको उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवाइज करती है और उसके बावजूद मेरे पास यह कैबिनेट का नोट है। अध्यक्ष महोदय, यह कैबिनेट को गुमराह किया गया, विभागीय अधिकारियों ने इस बात को इतने हल्के में लिया कि 4 फरवरी को कैबिनेट के एजेंडा नंबर 47 पर इसको कैबिनेट से स्वीकृत करा दिया गया, उसके बाद 12 अप्रैल 2025 को एमओयू साइन हो जाता है और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि कुछ अधिकारियों ने सरकार की इमेज को खराब करने का प्रयास किया है। जब यह मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन था, तो कैबिनेट के एजेंडे से इसको पास नहीं कराना चाहिए था, इस पर एमओयू साइन नहीं करना चाहिए था और उसके बाद इसको स्थगित कर दिया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारी जो इतनी लापरवाही से इस काम को किए हैं, सरकार उन पर क्या कार्रवाई करना चाहती है?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में सिर्फ एक कबड्डी नहीं, बल्कि आज के समय में सेपैक टकरॉ से लेकर रगबी और हॉकी जैसे खेलों की भी अंतर्राष्ट्रीय मेजबानी कम्पीटीशन्स का कर चुका है। कबड्डी का कम्पीटीशन भी निश्चित रूप से इसी आधार पर बिहार में होना था। हां, अगर किसी फेडरेशन के ऊपर, भारतीय फेडरेशन के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई स्टे ऑर्डर या ऑर्डर पास किया है उनके फाइनेंशियल डिस्क्रीपेंसी के ऊपर, तो निश्चित रूप से यह मामला गंभीर है। एमओयू साइन होने के बावजूद इसको केंसिल करने का मतलब यही था कि हम लोग नहीं चाहते ऐसे किसी भी फेडरेशन के साथ अपनी बिहार सरकार के नाम को जोड़ने का, तो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो निश्चित रूप से अगर यह मामला सॉर्ट आउट हो जाता

है और मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगी कि इतना गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि भारत के किसी भी राज्य ने इस कंपीटीशन को होस्ट करने की स्वीकृति नहीं दी। अंत में यह कंपीटीशन किसी दूसरे राष्ट्र में किया गया, जो वर्ल्ड कबड्डी फेडरेशन है उन्होंने खुद से इसका आयोजन किया। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, तो वहां पर बिहार सरकार या बिहार सरकार का कोई भी अंग, तो खेल प्राधिकरण का सवाल उठ रहा है, उसके साथ संलिप्त नहीं होगा।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, विषय मेरा दूसरा है। माननीय मंत्री जी खुद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हैं। मेरा विषय सिर्फ इतना ही है कि फेडरेशन पर आरोप है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, उसके बाद कैसे अधिकारियों ने केबिनेट से पास करा दिया ?

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : महोदय, जब बात सुप्रीम कोर्ट की आयी है।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय मंत्री। पूरी बात सुन लीजिए आप, बैठिये। पहले मेम्बर की पूरी बात सुन लीजिए, तब अपनी बात बोलिये। बैठ जाइये।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी चीजों को घुमा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा–सीधा सवाल है कि जब 31 जनवरी, 2025 को यह मामला रजिस्टर्ड होता है और इसकी सुनवाई 4 फरवरी को होती है और उसमें स्पष्ट आर्डर है इंटरपोल, सीबीआई इतने तक का इसमें जिक्र है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद यह केबिनेट से पास हो जाता है और इसके बाद इसके लिए एमओयू साइन कैसे हो गया ? बाद में स्थगित किया गया। यह दो कार्रवाई करने वाले अधिकारी, क्या उन्होंने इस विषय की गंभीरता को नहीं समझा ? बस मेरा कहना यह है। उन पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 फरवरी, माननीय सदस्य खुद ही यह तारीख बता रहे हैं। 4 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आता है, 4 फरवरी को ही केबिनेट की बैठक भी होती है, तो निश्चित रूप से एक ही दिन पर तुरंत हम लोगों के पास यह आदेश हो जाय और केबिनेट से उसको हटा दिया जाय, यह तो संभव नहीं है। जब मामला संज्ञान में आया, तो निश्चित रूप से जो एग्सिस्टिंग एमओयू था उसको केंसिल किया गया और बिहार सरकार ने किसी ऐसे संघ या व्यक्ति के साथ कोई एसोसिएशन रखना उचित नहीं समझा।

टर्न–3 / संगीता / 10.02.2026

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर, श्री राणा रणधीर ।

(व्यवधान)

जब अनुमति देंगे तब बोलिएगा । प्लीज बैठिए ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब कैबिनेट हुआ तो सॉलिसिटर जेनरल जिस केस में अपीयर हो रहे हैं और उसी दिन कैबिनेट नोट अप्रूव हो रहा है और साथ ही साथ ये अप्रैल महीना में है, उसके दो महीना बाद आखिर ये एम0ओ0यू0 कैसे साइन हो गया?

अध्यक्ष : मंत्री जी, दिखवा लीजिए । देखकर के यदि इस मामले में कहीं गड़बड़ी हुई है तो निश्चित सरकार कार्रवाई करे ।

सुश्री श्रेयीस सिंह, मंत्री : जी अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर, श्री राणा रणधीर ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–419, श्री बशिष्ठ सिंह (क्षेत्र सं0–209, करगहर)</u>

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : खंड–1 अस्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–227, दिनांक–07.05.2025 द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखंड में कुल रु0 205. 92 लाख (दो करोड़ पांच लाख बानवे हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है । जिसका कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

खंड–2 इस खंड का उत्तर कंडिका–01 में सन्निहित है ।

खंड–3 इस खंड का उत्तर कंडिका–01 में सन्निहित है ।

अध्यक्ष : श्री बशिष्ठ सिंह जी उत्तर मिला है ?

श्री बशिष्ठ सिंह : जी उत्तर मिला है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री बशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा क्वेश्चन है महोदय, आपका आदेश होगा तो, करगहर में जगजीवन स्टेडियम मैदान है...

अध्यक्ष : आप अलग से कर लीजिएगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, 30 सेकेंड ।

अध्यक्ष : आप अलग से एक पत्र लिखकर माननीय मंत्री जी को आग्रह कर लीजिएगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : 30 सेकेंड महोदय, माननीय मंत्री खिलाड़ी पहले से रही हैं, अंतराष्ट्रीय खेल खेली हैं हम इनसे आग्रह करेंगे कि जर्जर स्थिति में करगहर का स्टेडियम है उसको भी शीघ्र बनवाने का कष्ट करें चूंकि वहां से जिलाधिकारी ने प्रपोजल भेज दिया है अगर ये स्वीकृति देंगी तो उसमें काम लग जाएगा...

अध्यक्ष : सरकार के संज्ञान में आ गया है, निश्चित रूप से होगा ।

श्री बशिष्ठ सिंह : धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्री मांशरीक मृणाल ।

तारांकित प्रश्न सं0–420, श्री मांशरीक मृणाल (क्षेत्र सं0–132, वारिसनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर में वार्ड–11 में नव सृजित प्राथमिक विद्यालय पुरनाही नहीं है बल्कि नव सृजित प्राथमिक विद्यालय पुरन्दाही है । भवनहीन होने के कारण उक्त विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय धोबियाही में टैग कर संचालित कराया जा रहा है । वर्तमान में उक्त विद्यालय के लिए 10 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध हो गयी है ।

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता, BSEIDC, PATNA को उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पत्र दिया गया है ।

उक्त विद्यालय का भवन निर्माण कार्य BSEIDC, पटना द्वारा स्वीकृति के उपरान्त 08 माह में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : श्री मांशरीक मृणाल जी पूछिए ।

श्री मांशरीक मृणाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अपलोड कर दिया गया है लेकिन अगर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिए । आपको उत्तर मिला है, उत्तर पढ़ लिए हैं न ।

श्री मांशरीक मृणाल : जी उत्तर मिल गया है ।

अध्यक्ष : आप सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए ।

श्री मांशरीक मृणाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए ।

श्री देवेशकान्त सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0–421, श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र सं0–111,गोरेयाकोठी)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उत्तर कंडिका–(1), (2) एवं (3) वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3

के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा डिग्री कॉलेज से अनाच्छादित प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त भूखंड की उपलब्धता से युक्त राजकीय बुनियादी विद्यालयों/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/मॉडल स्कूल/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/अन्य उपयुक्त संस्थान को चिन्हित करते हुए विभाग में उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब दे दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के बजट अभिभाषण एवं सात निश्चय–3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखण्ड, जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

विभागीय पत्रांक–40, दिनांक–14.01.2026 द्वारा डिग्री कॉलेज से अनाच्छादित प्रखंडों में डिग्री कॉलेजों की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना एवं पर्याप्त भूखंड की उपलब्धता से युक्त राजकीय बुनियादी विद्यालयों/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/मॉडल स्कूल/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/अन्य उपयुक्त संस्थानों को चिन्हित करते हुए विभाग में उनकी सूची उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है ।

हमलोगों को आशा है महोदय कि इसी सत्र में यथासंभव सभी जगह जहां 213 प्रखंड आच्छादित नहीं हैं कॉलेजों से, डिग्री कॉलेजों से वहां किसी तरह हमलोग पाठ्यक्रम शुरू करेंगे और साथ ही साथ आधारभूत संरचना की भी कार्रवाई जमीन उपलब्धता और उसको करायेंगे वहां पर ।

श्री देवेशकान्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : ठीक है, पूछ लीजिए ।

श्री देवेशकान्त सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने उपमुख्यमंत्री और बिहार सरकार को धन्यवाद करता हूं कि 17वीं विधान सभा में यह प्रश्न आया था कि क्या हम वैसे प्रखंडों को आच्छादित, तो आपने किया इसके लिए बहुत–बहुत पहले तो आभार और धन्यवाद । मेरा यह विषय था कि पिछली बार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को अपग्रेड करने के क्रम में कुछ स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी हो गयी थी तो हमारा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी से और आग्रह के साथ मशविरा भी है कि जो चयन स्कूलों का हो, वैसे उन्होंने कहा कि इस साल ही शुरू करने का, तो

चयन करने के क्रम में अगर विधायकों की राय ली जाएगी तो उचित चयन हो पाएगा और जहां–जहां जैसे मैंने आपको चर्चा में लिखा है जैसे जनता हाई स्कूल मोसेपुर का, वहां साढ़े सात बीघा जमीन स्कूल को है, उसके पास बिल्डिंग भी बहुत उपलब्ध है और बगल में सरकार की बहुत जमीन है । वैसे अगर राय ली जाएगी तो उचित जगह पर खुल जाएगा तो मेरा आग्रह है कि इसमें विधायकों को सूची कि किस–किस प्रखंड की सूची तो आ गई है कहां खोलने के लिए इनसे हमलोगों से भी संबंधित स्थल पर राय ले ली जाए कि वैसा बाद में दिक्कत नहीं हो कि हमारे यहां एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुला है डेढ़ कट्ठा जमीन में वहां पढ़ाई नहीं हो पा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उपयुक्त स्थान उनके द्वारा जो दिया जाय तो वे विभाग को या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कॉपी हमें देते हुए...

अध्यक्ष : माननीय विधायकों से राय ले लिया जाय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जी, माननीय विधायक संबंधित डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिख दें और एक प्रतिलिपि हॉयर एजुकेशन को भी दे दें तो उसको भी जरूर हमलोग संज्ञान में लेंगे कि आपकी जो राय है सही होगा तो क्यों नहीं उस पर हमलोग कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे ।

अध्यक्ष : श्री अरूण मांझी ।

तारांकित प्रश्न सं0–422, श्री अरूण मांझी (क्षेत्र सं0–189, मसौढ़ी)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : खंड–1 वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय का अपना भूमि कुल रकवा 17 डी0 है, जिसमें पूर्व से एक खंड में तीन वर्गकक्ष, बरामदा के साथ ऊपर करकट का शेड से निर्मित है । दूसरे खंड में भी छतदार दो वर्गकक्ष बरामदा के साथ निर्मित है, जिसमें एक वर्गकक्ष जर्जर एवं एक वर्गकक्ष ठीक है ।

पठन–पाठन का कार्य कराकट शेड के दो कमरे एवं छतदार एक कमरे में किया जाता है ।

उक्त जर्जर भवन को तोड़कर नवनिर्मित भवन निर्माण हेतु जिला कार्यालय के पत्रांक–465, दिनांक–02.02.2026 द्वारा BSEIDC, पटना को पत्र लिखा गया है ।

उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति के उपरान्त BSEIDC पटना द्वारा आठ महीने में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है अरूण बाबू ।

श्री अरूण मांझी : नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड–1 वस्तुस्थिति यह है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय का अपना भूमि कुल रकवा 17 डी0 है, जिसमें पूर्व से एक खंड में तीन वर्गकक्ष, बरामदा के साथ ऊपर करकट का शेड से निर्मित है । दूसरे खंड में भी छतदार दो वर्गकक्ष बरामदा के साथ निर्मित है, जिसमें एक वर्गकक्ष जर्जर एवं एक वर्गकक्ष ठीक है ।

पठन–पाठन का कार्य करकट शेड के दो कमरे एवं छतदार एक कमरे में किया जाता है ।

उक्त जर्जर भवन को तोड़कर नवनिर्मित भवन निर्माण हेतु जिला कार्यालय के पत्रांक–465, दिनांक–02.02.2026 द्वारा BSEIDC, पटना को पत्र लिखा गया है ।

उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति के उपरान्त BSEIDC पटना द्वारा इसी साल इसी वित्तीय वर्ष में हमलोग उसको नए निर्माण को पूरा कर देंगे । धन्यवाद महोदय।

तारांकित प्रश्न सं0–423, श्री शुभानंद मुकेश (क्षेत्र सं0–155, कहलगांव)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बिहार में 5 अप्रैल, 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है तथा इसका कठोरता पूर्वक अनुपालन किया जा रहा है, इसी क्रम में अन्य राज्यों से शराब एवं अन्य मादक पदार्थों के आवाजाही की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा समेकित जांच चौकी/अन्य जांच चौकी का गठन किया गया है । वर्ष 01.04. 2026 से 31.12.2022 तक कुल 15 चेकपोस्ट कार्यरत थे, जिसपर कुल 20,354 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं 8,92,746 ली0 शराब की जब्ती की गयी तथा कुल 2,190 वाहनों को जब्त किया गया ।

विभाग द्वारा मद्यनिषेध नीति के कारगर कार्यान्वयन हेतु 01.01.2023 से 69 अन्य चेकपोस्टों का गठन किया गया, इस प्रकार बिहार राज्य में कुल 84 चेकपोस्ट कार्यरत हैं, जिसमें 67 चेकपोस्ट विभिन्न राज्यों की सीमा एवं नेपाल की सीमा पर कार्यरत हैं । भागलपुर जिला में झारखंड की सीमा पर हनबारा एवं पं0 बंगाल की सीमा पर मिर्जापुर चौकी चेकपोस्ट कार्यरत है।

ज्ञातव्य हो कि दिनांक–01.01.2023 से 31.12.2025 तक सभी चेकपोस्टों से 2,68,133 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है एवं 12,59,375 ली0 शराब जब्त किया गया है तथा साथ ही साथ 11,168 वाहनों की भी जब्ती की गयी है । विदित हो कि ये सभी चेकपोस्ट बिहार राज्य के सीमावर्ती राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, झारखंड, प0 बंगाल तथा नेपाल की सीमा पर कार्यरत हैं ।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, प0 बंगाल के सीमा पर 08, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल की सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं ।

विभाग के द्वारा सभी चेकपोस्टों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा हुआ है एवं ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा 24×7 जांच एवं छापामारी अभियान चलाया जा रहा है । समय–समय पर आवश्यकतानुसार ड्रोन एवं डॉग स्क्वाड से भी जांच अभियान चलाया जाता है । समेकित चेकपोस्ट पर हेण्डहेल्ड स्कैनर से सभी संभावित गाड़ियों की जांच की जाती है । आवश्यकतानुसार अन्य चेकपोस्टों पर भी हेण्डहेल्ड स्कैनर से जांच की जाती है । सभी चेकपोस्टों पर पर्याप्त संख्या में मद्यनिषेध पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है तथा इसके साथ ही साथ सभी चेकपोस्टों पर पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गयी है ।

विभाग के द्वारा राज्य में लागू पूर्ण शराबबंदी कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी संभावित संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है तथा अन्य राज्यों से बिहार में अवैध शराब की तस्करी को रोकने हेतु सभी कठोर कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है, बहुत आंकड़े दिये गए हैं परंतु हमारे क्षेत्र में कुछ व्यावहारिक इशू है, प्रॉब्लम है । मैं पूरक पूछता हूं । इसमें हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं लगभग 25 किलोमीटर का झारखंड और बिहार के साथ है तो वहां पर जो चेकपोस्ट है वह बहुत सर्वसाधारण है, वहां पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आप

ब्रेथ एनालाइजर है या सी0सी0टी0वी0 कैमरा की उपलब्धता है और वहां पर कोई रिस्पांस टीम नहीं है और सदन के माध्यम से चाहूंगा कि आधुनिक इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बने और बिहार के डी0जी0पी0 और झारखंड के डी0जी0पी0 के माध्यम से वहां पर स्पेशल पेट्रोल स्कॉवड रहे क्योंकि...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, आप लिखकर दे दीजिए हम देखेंगे ।

श्री शुभानंद मुकेश : जी ।

अध्यक्ष : श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–424, श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन जी (क्षेत्र सं0–145, साहेबपुर कमाल)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा ने अपने पत्र संख्या–37, दिनांक–02.02.2026 के द्वारा मो0 मुस्ताक अहमद अंसारी, तत्कालीन

प्रभारी प्रधानाध्यापक, +2 उच्च विद्यालय, खुदागंज, इस्लामपुर सम्प्रति प्रधानाध्यापक, गांधी उच्च विद्यालय, सिलाव के विरूद्ध प्रपत्र–क में आरोप गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पत्र संख्या–01, दिनांक–01.01.2026 के भाग–iii के कंडिका–1 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय पत्र संख्या–212 दिनांक–02.02.2026 के द्वारा मो0 अंसारी से बिन्दुवार तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री अंसारी से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन जी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध है लेकिन स्पष्टीकरण का समय सीमा समाप्त हो चुका है तो कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाय, चूंकि सारा साक्ष्य मौजूद है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है और ये जैसे उनकी समीक्षा करके अगर उनकी गलती है और उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तो निलंबन की कार्रवाई निश्चित की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री गोपाल कुमार अग्रवाल ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–425, श्री गोपाल कुमार अग्रवाल (क्षेत्र सं0–53, ठाकुरगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : खंड–1 स्वीकारात्मक ।

खंड–2 वस्तुस्थिति यह है कि नया प्राथमिक विद्यालय झांटीबाड़ी में 12 डिसमिल भूमि उपलब्ध हो गई है । जिला कार्यालय के पत्रांक–174 दिनांक–03.02.2026 द्वारा BSEIDC, पटना को नया विद्यालय भवन, शौचालय, पेयजल एवं रसोईघर के निर्माण हेतु पत्र दिया गया है ।

उक्त निर्माण कार्य BSEIDC, पटना द्वारा स्वीकृति के उपरांत आठ महीने में पूर्ण कराने का लक्ष्य है ।

श्री गोपाल कुमार अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है और मैं जवाब से संतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : श्री सतीश कुमार सिंह यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–426, श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र सं0–203, रामगढ़)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : खंड–1 आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

खंड–2 स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं बिहार पंचायत/नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली 2012 तथा बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 के तहत मध्य विद्यालयों में 2350 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) की नियुक्ति की गयी । साथ ही सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–899/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में विभागीय ज्ञापांक–3907 दिनांक–31.10.2025 द्वारा 239 पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है कि बिहार राज्य के मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में महोदय जो जवाब आया है उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : महोदय, मेरा सवाल यह है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 2009 सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करना है । बिहार में लगभग 29 हजार मध्य विद्यालय हैं और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 9 हजार 307 हैं, कुल 38 हजार उच्च महाविद्यालय हो रहे हैं जबकि जवाब में आया है कि मध्य विद्यालयों में मात्र 2 हजार 350 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है अनुदेशक के रूप में ।

(क्रमशः)

टर्न–4/यानपति/10.02.2026

(क्रमशः)

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, और नई बहाली के रूप में विज्ञापन संख्या–3907 में 239 मात्र की और बहाली होनी है जबकि विद्यालयों की संख्या 38 हजार है, 38 हजार से ऊपर है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : तो मेरा सवाल यह है कि माननीय मंत्री जी कब तक इन विद्यालयों में सारे शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी क्योंकि खेल के प्रति जो है सरकार अगर...

अध्यक्ष : दूसरा पूरक होगा, आप बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पूरे सदन को और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर बी0पी0एस0सी0 के द्वारा टी0आर0ई0–3 के तहत हमलोगों ने सब्जेक्टवाइज नियुक्तियां कीं जो ढाई लाख से ज्यादा हैं और टी0आर0ई0–4 की भी शीघ्र नियुक्ति होनेवाली है जिसमें 30 हजार से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं को सब्जेक्टवाइज हमलोग करेंगे । यह बात सही

है कि न सिर्फ खेल लेकिन म्यूजिक भी ऐसा क्षेत्र है जहां शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है । टी0आर0ई0–4 के बाद हमलोग इसका आकलन कर लेंगे लेकिन वर्तमान में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे फिजिक्स, मैथ इत्यादि । यहां पर तत्काल आवश्यकता है कई स्कूलों में और पूरी तरीके से पूरे नहीं हो पाए तो उनका प्राथमिकता देते हुए सब्जेक्ट की बात थी इसपर भी हमलोग जरूर गंभीरता से विचार करेंगे और आवश्यकतानुसार कार्रवाई हमलोग निश्चित रूप से करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विशाल कुमार ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बहुत स्पष्ट उत्तर है, बैठ जाइये । सारी बात आ गई है । सरकार ने कह है कि हम प्राथमिकता के आधार पर करेंगे । आप बैठ जाइये, आपकी लगभग सारी बात आ गई है । माननीय सदस्य, बैठ जाइये, इतना बढ़िया जवाब आया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–427, श्री विशाल कुमार (क्षेत्र सं0–12, नरकटिया)

(लिखित उत्तर)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में फुलवार से मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहन परिचालन किया जा रहा था। वर्ष 2018 से पूर्व बिना अधिसूचित मार्ग के ही परमिट प्राप्त कर बसों का परिचालन किया जाता था। वर्ष 2018 के पश्चात् विभागीय ज्ञापांक–836 दिनांक–05.02.2018 द्वारा मार्गो को अधिसूचना प्रकाशित की गई। अधिसूचित मार्ग के अनुसार ही परमिट प्राप्त करने की कार्रवाई की जाती है।

फुलवार से मुजफ्फरपुर मार्ग अधिसूचित नहीं रहने के कारण उक्त मार्ग पर वाहन का परिचालन बंद कर दिया गया।

आंशिक स्वीकारात्मक । वर्तमान में छौड़ादानों से मुजफ्फरपुर तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन किया जा रहा है।

वर्तमान में छौडादानों से मुजफ्फरपुर तक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन किया जा रहा है तथा फुलवार एवं बंजरिया से मुख्यालय, पटना तक मार्ग अधिसूचित नहीं है।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो मिला है लेकिन मैं संतुष्ट, संतोषजनक जवाब यह नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री विशाल कुमार : मैंने सवाल किया था कि मेरे विधान सभा में बंजरिया जो ब्लॉक है वह नेपाल से लगा हुआ है बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का वह प्रखंड है और वहां से न तो कोई रेलवे स्टेशन है और वहां से मोतिहारी 40 कि0मी0 दूर है ।

तो कोई बस का परिचालन नहीं हो रहा है । जवाब मैंने मांगा पटना के लिए, जवाब मिल रहा है मुजफ्फरपुर तक के लिए 2018 में परिचालन होता था ।

अध्यक्ष : मिस्टेक हो गया होगा ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, उसमें कहा गया कि अधिसूचना नहीं होने के कारण तो यह हम सरकार से जानना चाहते हैं कि कौन सी यह अधिसूचना है जिसके चलते परिचालन 2018 के बाद से बंद हो गया ।

अध्यक्ष : जरूर–जरूर, बैठ जाइये ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता है कि आवागमन कैसे सुव्यवस्थित किया जाय और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाय । उक्त पथ अभी अधिसूचित नहीं है और बसों का परिचालन नहीं हो रहा है यह बात सही है । तो उस पथ को अधिसूचित करने के लिए हमने निर्देश दिया है और जब पथ की अधिसूचना निकल जायेगी उसके बाद हमारे पास अगर परिवहन निगम की बसें उपलब्ध हो जायेंगी तो परिवहन निगम की बस को चलायेंगे और नहीं तो पी0पी0 मोड पर हम बस को चलाकर नागरिक सुविधा उपलब्ध करवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता देवी ।

श्री विशाल कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : बस चलाया जायेगा, चिंता मत कीजिए, स्पष्ट बताए हैं माननीय मंत्री जी ।

श्री विशाल कुमार : महोदय, परिचालन मुजफ्फरपुर तक के लिए हो रहा है । हम चाहेंगे मंत्री जी से कि उसको पटना तक करवा दीजिए ताकि लोग सीधे पटना से जुड़ सकें । माननीय मुख्यमंत्री जी तीन घंटा में पटना पहुंचा रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है, दिखवा लेंगे । श्रीमती संगीता देवी ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–428, श्रीमती संगीता देवी (क्षेत्र सं0–65, बलरामपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक । उल्लेखनीय है कि कटिहार जिले का बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर एवं बारसोई प्रखंड आते हैं तथा इन दोनों प्रखंडों में संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय संचालित है, जिनमें सह शिक्षा की व्यवस्था है ।

उपरोक्त के आलोक में बलरामपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत महिला महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्रीमती संगीता देवी : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है लेकिन जवाब से मैं असंतुष्ट हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी...

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए । आपको तीन सप्लिमेंट्री तक मौका है ।

श्रीमती संगीता देवी : क्या सरकार को यह जानकारी है कि जिला अंतर्गत बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में किसी भी राजकीय डिग्री महिला कॉलेज की

स्थापना नहीं है जिसके कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता है । इसलिए महिला डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण महिलाओं को दूरस्थ महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए समय–सीमा क्या है ?

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है कि कटिहार जिला के बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर एवं बारसेई प्रखंड आते हैं तथा इन दोनों प्रखंडों में संबद्धता का महाविद्यालय संचालित हैं इसमें सह शिक्षा की व्यवस्था है । तो प्रथम चरण में हमलोगों ने उन प्रखंडों को चिन्हित किया है जहां बिल्कुल शून्य कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है इस वजह से हमलोगों ने प्रथम चरण में इसको टेकअप नहीं किया है और दूसरी बात है कि सरकार का भी एक पॉलिसी डिसीजन है कि जो भी महाविद्यालय जो भी स्कूल खोले जायं सरकारी उसमें को एडुकेशन की व्यवस्था हो । तो भविष्य में इसको हमलोग टेकअप करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–429, श्री मुरानी मोहन झा (क्षेत्र सं0–86, केवटी)

(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक ।

3. खंड–02 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, उत्तर प्राप्त है मगर उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, पूरक है कि बिहार में कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देना एवं बाल विवाह को रोकना था । जबकि अन्य राज्यों में कानूनी उम्र और शिक्षा के आधार पर वित्तीय सहायता जोड़ा गया है । तो मेरा कहना है कि यहां बिहार में मात्र 5 हजार रुपया बी0पी0एल0 धारित परिवारों को दिया जाता है कन्या विवाह योजना में । मेरी मांग है कि इसको 5 हजार से 25 हजार बढ़ाया जाय ताकि अतिपिछड़े लोगों को और गरीब तबके के लोगों को भी इसकी सुविधा प्राप्त हो सके ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कन्या विवाह योजना के तहत अभी हमलोग 5 हजार की राशि देते हैं और इसको बढ़ाने का अभी विभाग के अंतर्गत कोई भी विचार नहीं है, आगे भविष्य में इसको हमलोग देखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज आपलोग इनको पूरक पूछने दीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, कम से कम इसपर बिहार सरकार को विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि विचार किया जायेगा । बैठ जाइये । श्री राहुल कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–430, श्री राहुल कुमार (क्षेत्र सं0–216, जहानाबाद)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–431, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र सं0–213, काराकाट)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–432, श्री विष्णु देव पासवान (क्षेत्र सं0–107, दरौली)

(लिखित उत्तर)

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–24, दिनांक–31.01.2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सिवान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखंड के लोकमान्य तिलक उच्च विद्यालय में पूर्व से स्टेडियम निर्मित है जहां छात्र–छात्राएं नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं।

साथ ही मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत दरौली प्रखंड में 200मी0 ट्रैक युक्त फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण हेतु विभागीय मानक के अनुरूप व विवाद रहित भूमि की खोज की जा रही है ।

भूमि का प्रस्ताव प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

3. इस खंड का उत्तर कंडिका–02 में सन्निहित है ।

श्री विष्णु देव पासवान : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में सरकार की ओर से जो मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है उससे पूर्णतः असंतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री विष्णु देव पासवान : सिवान जिले के गुठनी प्रखंड स्थित लोकमान्य तिलक उच्च विद्यालय परिसर में पूर्व से ही स्टेडियम का निर्माण किया गया है । परंतु किसी भी वास्तविक एवं उपयोगी खेल स्टेडियम के लिए खिलाड़ियों एवं दर्शकों की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शौचालय, चेंजिंग रूम, समुचित प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा संबंधित तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं का होना अनिवार्य है । उन सुविधाओं के अभाव में यह निर्माण मात्र दिखावटी बनकर रह जाता है और स्थानीय खिलाड़ियों को इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी उल्लेखनीय है कि दरौली प्रखंड के संबंधित क्षेत्र में कृषि विभाग के पास पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है । इसके बावजूद यदि स्टेडियम के समुचित निर्माण हेतु भूमि की कमी का तर्क दिया जा रहा है लेकिन यह न केवल

आश्चर्यजनक है बल्कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े करता है ।

अध्यक्ष : आपका स्टेडियम निर्माण के संबंध में है । अब उत्तर सुन लीजिए, बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी ।

सुश्री श्रेयसी सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जवाब में हमने स्पष्ट कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है खेल को बढ़ावा देने की वह उनकी प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कार्य करा दिया जायेगा जिसमें कि 200 मीटर ट्रैक युक्त फुटबॉल स्टेडियम बनाया जायेगा । निश्चित रूप से अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई और सुझाव हो और यदि जो जमीन जो आपके सामने है, आप खेल विभाग को अपना सुझाव दे दीजिए ।

अध्यक्ष : आप लिखित दे देंगे ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : आपके अनुसार ही स्टेडियम का निर्माण कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–433, श्रीमती अनीता (क्षेत्र सं0–239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा नवादा जिलान्तर्गत प्रश्नाधीन महाविद्यालय सहित अन्य महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विभाग में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक–3054, दिनांक–20.08.2025 द्वारा प्रस्तावित उन महाविद्यालयों में से सबसे अच्छे एवं उपयुक्त आधारभूत संरचना वाले महाविद्यालय का नाम, शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति या बगल के अन्य महाविद्यालयों से शिक्षकों की सेवा लिए जाने की संभावना की जानकारी के साथ एक महाविद्यालय का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश विश्वविद्यालय को दिया गया । तदालोक में विश्वविद्यालय द्वारा के0एल0एस0 महाविद्यालय, नवादा एवं टी0एस0 महाविद्यालय, हिसुआ में स्नातकोत्तर की पाठ्यक्रम के संचालन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है । प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है ।

3. उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है । एक माह के अंदर निर्णय संसूचित कर दिया जायेगा ।

श्रीमती अनीता : महोदय, मेरा प्रश्न है कि नवादा जिलांतर्गत बारसलीगंज विधान सभा क्षेत्र के एकमात्र सरकारी महाविद्यालय एस0एन0 सिन्हा महाविद्यालय सहित नवादा जिला के किसी भी सरकारी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विज्ञान एवं स्नातकोत्तर कला की पढ़ाई नहीं होती है । क्या यह बात सही है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए आप । बिना अनुमति के मत बोलिए, आप बैठिए । आप पूरक प्रश्न पूछिए । आप बिना अनुमति के मत बोलिए ।

श्रीमती अनीता : कि वारसलीगंज विधान सभा क्षेत्र, नालंदा जिला के छात्र–छात्राओं को स्नातकोत्तर विज्ञान एवं कला की पढ़ाई के लिए जिले से बाहर गयाजी एवं अन्य जिलों में जाना पड़ता है । यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार एस0एन0 सिन्हा महाविद्यालय...

अध्यक्ष : प्रश्न पढ़ दिया, उत्तर तो मिला है न आपको ।

श्रीमती अनीता : मैं संतुष्ट नहीं हूं । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एस0एन0 सिन्हा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर साइंस एवं कला की पढ़ाई कब तक शुरू करवाई जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

(व्यवधान)

अनावश्यक मत बोलिए बीच में, बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो अपनी चिंता जाहिर की है इस सदन में उसकी एक प्रक्रिया होती है । कई महाविद्यालयों से कई विश्वविद्यालयों से एक प्रक्रिया उसको पास कराकर के हमारे पास आता है ।

(क्रमशः)

टर्न–5 / मुकुल / 10.02.2026

क्रमशः

श्री सुनील कुमार, मंत्री : कई महाविद्यालयों से, कई विश्वविद्यालयों से एक प्रक्रिया में उसको पास कराकर के हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से हमलोग कोशिश करेंगे कि आवश्यकतानुसार वहां पर क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर देना होगा, क्या टीचर्स देने होंगे सभी को ध्यान में रखना होता है और उनसे हमलोग रिपोर्ट मंगाकर के इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, आवश्यकतानुसार जैसा कि माननीय सदस्या बोल रही हैं निश्चित रूप से कई अन्य जगहों पर हमलोगों ने नये विषयों को इन्ट्रड्यूस किया है और यहां भी करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन उस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है इस वजह से, लेकिन इसको हमलोग पूरा करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण कुमार ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में हाउस से वाक–आउट करने का, बहिर्गमन करने की नई परिभाषा लिखी जा रही है, हमारे विपक्ष के सभी साथी वाक–आउट कर गये । महोदय, हम उनके अधिकार को चुनौती नहीं देते हैं, आना सवाल पूछना यही तो सरकार भी चाहती है कि वे सदन में रहें और प्रश्न पूछें सरकार उत्तर देगी, लेकिन अभी महोदय, आसन ने भी देखा होगा कि एक सदस्य श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन जी वे सारे सदस्य चले गये वे अकेले बैठे थे, उनका प्रश्न आया वे पूछें, सरकार ने जवाब दिया, संतुष्ट भी हो गये फिर बाहर चले गये । अभी अनीता जी आयी हैं, उनका स्वागत हैं

और प्रश्न पूछने का उनका पूरा अधिकार है, सरकार भी उनके अधिकार का सम्मान करती है लेकिन आज सदन वाक–आउट करने का, बहिर्गमन करने का नया तरीका, नई परिभाषा देख रहा है वह सिर्फ हम कह रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या–434 (श्री अरूण कुमार, क्षेत्र सं0–180, बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिला के ग्राम पंचायत सलारपुर में प्राथमिक विद्यालय तरौरा के पोषक क्षेत्र से एक किलोमीटर के अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय फरीदपुर एवं दो किलोमीटर के अंतर्गत मध्य विद्यालय पीरबुढौना संचालित है, जिसमें उक्त पोषक क्षेत्र के बच्चे नामांकित हैं ।

आंकनीय है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं तदालोक में निर्गत नियमावली 2011 के आलोक में प्रत्येक बसाव क्षेत्र के 01 कि0मी0 की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय एवं 03 कि0मी0 की परिधि में एक प्रारंभिक विद्यालय/मध्य विद्यालय का प्रावधान है ।

पूर्व से ही विभागीय मानक के अनुरूप पोषक क्षेत्र में दो मध्य विद्यालय रहने के कारण प्राथमिक विद्यालय तरौरा को उत्क्रमित करने का विचार नहीं है।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, मैं इस जवाब से असंतुष्ट हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री अरूण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अलावलपुर पंचायत के तरौरा प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय करने के लिए कहा गया है, जिसमें बच्चे–बच्चियों को दूर के स्कूल में जाकर पढ़ने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, इसलिए अगर वहां पर मध्य विद्यालय बन जाता है तो उस विद्यालय से सभी बच्चे–बच्चियां पठन–पाठन का लाभ उठा सकेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे जो हमलोगों ने मानक बनाया है उसके अनुसार इसको हमलोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसको पुनः दिखवा लेंगे, अगर ऐसी प्रशासनिक तौर पर संख्या बहुत ज्यादा हुई बच्चों की जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो उस पर हमलोग पुनर्विचार करेंगे, ऐसा हमलोगों ने पूर्व में भी किया है ।

तारांकित प्रश्न संख्या–435 (मो0 तौसीफ आलम, क्षेत्र सं0–52, बहादुरगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत महाविद्यालय द्वारा शासी निकाय एवं प्रबंध समिति के निबंधन हेतु प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कार्यालय को दिनांक–07.03.2024 को प्राप्त कराया गया था । उक्त प्रस्ताव के आलोक में बहादुरगंज कॉलेज, बहादुरगंज, किशनगंज के शासी निकाय एवं प्रबंध समिति को निबंधित करते हुए समिति के पत्रांक–1251, दिनांक–10.04.2024 द्वारा संसूचित कर दिया गया है ।

2. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति संबद्धता विनियमावली में निहित प्रावधान के तहत शासी निकाय एवं प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का है । तद्नुसार प्रश्नगत महाविद्यालय के शासी निकाय एवं प्रबंध समिति का कार्यकाल दिनांक–09.04.2027 तक है ।

3. अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु विभागीय पत्रांक–202, दिनांक–06.02.2026 के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : श्री कुंदन कुमार ।

मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय, यह कॉलेज पेन–पेपर पर चल रहा है और एक दिन भी क्लास नहीं हो रहा है और जो कॉलेज की जमीन है उसमें अतिक्रमण में काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं और जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो कॉलेज का मैनेजमेंट कमेटी है सारे लोग मिल–जुलकर के उस जमीन को बेचा जा रहा है और कॉलेज सिर्फ पेन–पेपर पर चल रहा है । मेरी मांग यह है कि क्या अतिक्रमण हटाकर के उस कॉलेज को, जमीन जितना कॉलेज में है उतना उसको किया जाए और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का मामला है और अगर किसी को उस कॉलेज से डिग्री मिल जायेगा और कहीं जाकर के वह नौकरी करेगा तो वह क्या पढ़ायेगा । हम चाहते हैं कि उस कॉलेज की जांच हो और अगर अनियमितता होती है, अगर क्या हम तो जान ही रहे हैं कि वहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं कि इसके लिए एक जांच कमेटी बैठे और राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय कमेटी के द्वारा इसकी जांच की जाए कि वहां फर्जी डिग्री दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने अपनी बातों को रखा सदन में, वह निश्चित रूप से गंभीर प्रकृति के हैं और मुख्यालय से हमलोग वरीय पदाधिकारी की टीम भेजकर के इसकी जांच निश्चित रूप से समय अवधि के अंदर करा लेंगे लेकिन सदन को साथ–साथ यह भी सूचित करना चाहेंगे, पूर्व में भी मैंने कहा जो अतिक्रमण का कई स्कूलों में, कई महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में यह मामला है इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमलोगों ने हर जिले में एक स्टेट ऑफिसर की तरह, एक रिटायर्ड ए0डी0एम0 ऑफिसर को रेवेन्यू का, हमलोग कॉन्ट्रेक्ट पर रखेंगे ताकि

पूरे जिले की जो भी जमीन है शिक्षा विभाग की, चाहे वह यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, स्कूल्स का हो तो उसका एक लेखा–जोखा रख पायेंगे ताकि इस तरह का अतिक्रमण या बॉन्ड्रीवॉल बनाने में हमें सहायता होगी ।

मो0 तौसीफ आलम : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : श्री कुंदन कुमार । माननीय सदस्य, बहुत क्लीयर हो गया जवाब । कुंदन जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

तारांकित प्रश्न संख्या–436 (श्री कुंदन कुमार, क्षेत्र सं0–146, बेगूसराय)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर कंडिका–(1), (2) एवं (3)

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में विभागीय पत्रांक–3644, दिनांक–29.09.2023 द्वारा सभी विश्वविद्यालयों से प्राथमिकता के आधार पर असैनिक निर्माण कार्यों के लिए 05–05 महाविद्यालयों का प्रस्ताव गठित करने का निदेश दिया गया था, परन्तु असैनिक निर्माण कार्य से संबंधित योजनाओं के चयन में पारदर्शिता को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक–3802, दिनांक–17.08.2024 द्वारा अंगीभूत महाविद्यालयों में असैनिक निर्माण/जीर्णोद्धार कार्यों के लिए योजनाओं के चयन एवं अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति गठित की गयी है । प्रश्नाधीन महाविद्यालय में असैनिक निर्माण कार्यों से संबंधित किसी भी योजना के लिए उक्त समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं है ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हमें जवाब प्राप्त है । मेरा प्रश्न जो था यह स्व0 विश्वनाथ सिंह शर्मा महाविद्यालय के बारे में जिसको कॉपरेटिव कॉलेज के नाम से हमलोग जानते हैं और महोदय, प्रश्न में मैंने पूछा था कि वहां पर लगभग 20 हजार छात्र–छात्राएं पढ़ते हैं और मात्र 13 कमरा है जिसमें 5 कमरा तो विभाग ने ही जर्जर घोषित कर दिया है और जवाब आया है कि उक्त समिति, कोई समिति जिला स्तर पर बनाया गया है, उससे कोई भी अनुशंसा प्राप्त नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कौन सी समिति है, मेरा पहला तो पूरक प्रश्न यह है कि यह कौन सी समिति है जिसमें जिला स्तर पर विधायक को सम्मिलित नहीं किया गया है और दूसरा प्रश्न है कि अगर विद्यालय में 20 हजार छात्र–छात्राएं हैं और समिति ने अनुशंसा नहीं भेजी है और 5 कमरे उसमें जर्जर हैं तो क्या 8 कमरे में 20 हजार छात्र–छात्राएं पढ़ते रहेंगे और क्या जब विधायक यहां पर प्रश्न कर रहे हैं तो क्या उसको अनुशंसा नहीं समझा जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, हम पूरक ही पूछ रहे हैं कि मंत्री जी क्यों नहीं उसका निर्माण कराना चाह रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जिज्ञासा है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी समिति तो हमलोगों ने जान के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और संबंधित शिक्षा के पदाधिकारियों को रखा है, पोर्टल भी है जिन विद्यालयों में कमियां हैं किसी भी चीज की, चाहे पेयजल की हो, शौचालय की हो, बाउंड्री–वॉल या अन्य कमरों की तो यह दुर्भाग्यवश शायद उस कमेटी का ओवरसाइट रहा हो, नहीं देखा हो, वहां के स्थानीय माननीय विधायक जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी बात में सत्यता होगी और अलग से हमें एक रिक्वेस्ट लेटर ये दे दें उसको भी हमलोग सम्मिलित कर लेंगे अपने स्कीम ऑफ थिंक्स में ताकि वह आने वाले दिनों में हम इसको पूरा कर पायें, कई जगहों का हमलोगों ने काम शुरू किया है, पूर्व में भी माननीय विधायकों ने, माननीय पार्षदों ने जो अपनी अनुशंसाएं भेजी हैं उनमें बहुत सारे काम हुए भी हैं इनका भी काम हम निश्चित रूप से छात्रों के हित में करायेंगे ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा कमरा निर्माण से प्रश्न है और जब 15 दिन पहले हमलोग विधान सभा में अपना सवाल डाल देते हैं तो क्या सरकार इसकी जांच नहीं करवा सकती थी कि मैं सही बोल रहा हूं कि वहां पर 20 हजार छात्र–छात्राएं हैं और मात्र 8 कमरे में पढ़ रहे हैं, इसका निर्माण कराना आवश्यक है कि नहीं और ये केवल एक क्वेश्चन का ओवरसाइट नहीं हुआ है महोदय, आज ही के प्रश्न में 531 नंबर के प्रश्न में मैंने एस0के0 महिला कॉलेज के बारे में भी पूछा है वहां 13 हजार हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और मात्र 12 कमरे हैं महोदय, उसका भी वही जवाब आया है तो क्या शिक्षा के प्रति जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी की और सम्राट चौधरी जी की और विजय कुमार सिन्हा जी की जो सोच है तो क्या हमलोग उसके विरोध में नहीं काम कर रहे हैं, इसको कब तक बनवा देंगे यह जवाब देने का करें मंत्री जी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने बहुत साफ–साफ कह दिया है । मंत्री जी आप बता दें ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और एन0डी0ए0 सरकार के अधीन जो काम हुए हैं वह अभूतपूर्व हुए हैं ऐसी बात नहीं है, जितने विद्यालय आज हमारे पास, मैं सदन को भी बताना चाहूंगा कि 76 हजार से ज्यादा स्कूल्स हैं, 15 यूनिवर्सिटीज हैं पहले 5 हुआ करती थीं तो इस तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जितनी नियुक्तियां हुईं करीब 5 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षक हुए, पहले 1 लाख हुआ करते थे तो सब जगह हो रही है चरणबद्ध तरीके से । हमने तो आश्वस्त किया ही कि जहां–जहां कमियां हैं उनको हमलोग पूरा करेंगे लेकिन कन्स्ट्रक्शन का वर्क ओवर नाइट करना मुश्किल है, कैसे कॉलेजों में स्कूलों में कमियां हैं खासकर जो स्कूल उत्क्रमित हुए हैं उस पर ध्यान दिया गया तो माननीय सदस्य की जो चिंता है बिल्कुल

जायज है और उसको हमलोग अलग से इसकी समीक्षा करा लेंगे, जहां तक सवाल है 10 दिनों में शिक्षा विभाग से कम–से–कम सवा सौ प्रश्न आते हैं ।

क्रमशः

टर्न–6 / सुरज / 10.02.2026

क्रमशः

श्री सुनील कुमार, मंत्री : उसको हमलोग कोशिश करेंगे कि निश्चित रूप से प्राथमिकता के तौर पर करायेंगे ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, समय बता दें कि कब तक करवा देंगे ?

अध्यक्ष : इतना स्पष्ट जवाब दिया गया है, इतना साफ जवाब दिया गया है । उन्होंने कहा तो जल्दी करवा देंगे ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, कब तक करवा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिये और जितना जल्द से जल्द हो सके करवा दीजियेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इस वित्तीय वर्ष में कमी हो रहा है इसलिये इसको अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में बताइये, जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताइये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, इसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पत्रांक–3802, दिनांक–17.08.2024 को एक कमेटी बनायी गयी है और मैं विधायक हूं और मेरे क्षेत्र में कमेटी है अभी तक कोई कमेटी की जानकारी नहीं हुई और न ही मंत्री महोदय श्री कृष्ण बाबू के नाम से 1959 का एकमात्र महिला महाविद्यालय है जो पूरे चंपारण, शिवहर जिला में एक है...

अध्यक्ष : पूर्वी चंपारण का क्वेश्चन आप अलग से कर लीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, क्वेश्चन को दिगभ्रमित करके....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी निश्चित तौर पर सारे विधायकों के लिये जो कमेटी बनी है उसका पत्र जारी करवा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पूर्वी चंपारण...

अध्यक्ष : आप पूर्वी चंपारण का क्वेश्चन अलग से कर लीजियेगा, मौका मिलेगा आपको ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0– 437, श्री रजनीश कुमार (क्षेत्र सं0–143, तेघड़ा)</u>

(लिखित उत्तर)

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

बेगूसराय जिला अंतर्गत विगत तीन माह में ग्राम पंचायत तकीया, भगवानपुर में 24, ग्राम पंचायत दामोदरपुर, भगवानपुर में 32,

नगर परिषद् ग्राम बिहट में 44, ग्राम पंचायत केशावे, बरौनी में 15, ग्राम गैरा, तेघरा में 12, ग्राम चंदौर, भगवानपुर में 22 अर्थात कुल–149 घोड़परास का नियमानुसार आखेट किया गया है ।

राज्य के अंतर्गत सभी मुखिया को उनकी पंचायत की सीमा के अंदर गैर–वन इलाकों में ऐसे घोड़परास तथा जंगली सूअर, जो खेती/बागवानी की फसल तथा मनुष्यों के जान–माल के लिए खतरनाक हो चुके हैं, को आखेट/मारने का आदेश देने हेतु प्राधिकृत किया गया है । इस हेतु घोड़परास के मारने पर अनुज्ञप्तिधारी शूटर को प्रति घोड़परास रु0 750/– (सात सौ पचास रुपये) एवं मारे गये घोड़परास को जमीन में गाड़ने हेतु रु0 1250/– (एक हजार दो सौ पचास रुपये) प्रति घोड़परास का प्रावधान किया गया है ।

इसके अतिरिक्त घोड़परास द्वारा फसल नष्ट किये जाने पर 50,000/–(पचास हजार) प्रति हेक्टेयर सहायता राशि के भुगतान का प्रावधान भी किया गया है ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह घोड़परास की जो समस्या है यह केवल मेरे विधान सभा या मेरे जिले का नहीं, पूरे बिहार सूबे का है और इसमें जो उत्तर दिया गया है मात्र 149 हमारे हमारे क्षेत्र में उसका आखेट किया गया है । महोदय, हजारों–हजार की संख्या है कहा नहीं जा सकता है । मुझे लगता है, मैं दो पूरक माननीय मंत्री जी से, सरकार से जानना चाहता हूं । पहला कि क्या आखेटक जो अनुज्ञप्तिधारी शूटर हैं उसकी संख्या कितनी है ? मुझे लगता है कि सफिसियेंट नंबर ऑफ शूटर्स नहीं होने के कारण और इसका प्रचार–प्रसार नहीं होने के कारण ये आखेट सफिसियेंट नहीं हो रहा है और समस्या जस की तस बनी हुई है । जबकि सरकार ने कोई ऐसा नियमावली बनाया है जिसकी चर्चा है । एक तो शूटर के बारे में, जहां तक मुझे जानकारी है ये 149 जो आखेट हुये हैं इसका भी भुगतान नहीं हुआ है शूटर को जिसके कारण हमलोग प्रयास कर रहे हैं, किसान प्रयास कर रहा है लेकिन वह आ नहीं रहा है आखेट करने । दूसरा, मेरा पूरक है कि जो सरकार ने बनाया है कि पचास हजार रुपया प्रति हेक्टेयर सहायता राशि के रूप में भुगतान करने का, इसकी कोई जानकारी निचले स्तर पर किसानों के बीच नहीं है मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं । तभी मैंने यह प्रश्न लाया है और अगर सरकार कोई योजना बनाती है किसान हित में, या कोई भी योजना अगर उसका प्रचार–प्रसार सही से नहीं होगा नीचे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा और हमलोगों को सवाल लाना पड़ता है । तो दूसरा पूरक यह है कि क्या इस योजना का पचास हजार रुपया जो सरकार अनुदान देगी इसके देने की पूरी प्रक्रिया का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से क्या मंत्री जी, क्या विभाग करवाना चाहती है ? मैं यह जानना चाहता हूं ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, एक तो माननीय सदस्य का था कि जिला में इतना ही आखेट किया गया है । माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि गोपालगंज में 1154, मुंगेर में 60, मोतिहारी में 94 यानी पूरे मिथिला में, बेगूसराय, नालंदा, समस्तीपुर ऐसे 2 हजार 411 आखेट किये गये हैं और जहां तक शूटर का सवाल है तो शूटर का हर जिलाधिकारी के पास भी उसकी संख्या है । हर जिला में अलग–अलग ढंग से है और उसके लिये वनरक्षी नियुक्त किये जाते हैं । जहां किसान को आवश्यकता पड़ती है कि नीलगाय हमारी फसल को नुकसान कर रहा है तो किसान...

(व्यवधान)

क्षमा करेंगे घोड़परास ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया करके मंत्री जी का जवाब सुन लीजिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : घोड़परास जहां नुकसान कर रहा है, उसके लिये यदि किसान लिखकर देते हैं मुखिया के पास तो उसके लिये शूटर की व्यवस्था होती है और जहां तक उनके पैसे की बात है तो पंचायती राज के द्वारा उनको साढ़े सात सौ और साढ़े बारह सौ रुपया, वह उनको दी जाती है आखेट करने के लिये और दफनाने के लिये ।

श्री रजनीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपने आप में कन्फ्यूजन करने वाला है, उन्होंने कहा कि वनरक्षी, उनका विभाग इस तरह की कोई व्यवस्था कर रहा है घोड़परास के शिकार के संबंध में । लेकिन फिर उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग के द्वारा इसका भुगतान होता है । जबकि मैं कह रहा हूं कि आखेटक की सफिसियेंट संख्या नहीं है और न ही इसकी जानकारी है । ठीक है राज्य भर में दो हजार हुआ होगा, ये उससे संबंध नहीं रखता है प्रश्न से । प्रश्न से हमारी यह मांग है कि आखेटक की सफिसियेंट संख्या क्या हमारे जिले में या अन्य जिले में है और अगर नहीं है तो उसकी सूचना, और जो भी है उसकी सूचना क्या वहां किसानों को देने की व्यवस्था कोई किया है विभाग ने और दूसरा अनुदान के संबंध में तो यह भी माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि अनुदान के लिये क्या व्यवस्था है ? कैसे उसका किसान आवेदन करेंगे और कैसे उसका भुगतान होगा ?

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : महोदय, हम इसको दिखवा लेते हैं । वैसे कृषि पदाधिकारी इसको लिखकर देंगे, जानकारी देंगे । पहले तो किसान अपना देंगे कि हमारा घोड़परास के कारण इतना क्षति हुआ है फिर उसको जांच–पड़ताल कृषि पदाधिकारी करेंगे, उसके बाद उसको दिया जायेगा

अध्यक्ष : इसका प्रचार–प्रसार करवा दीजिये ।

डॉ0 प्रमोद कुमार, मंत्री : ठीक है महोदय ।

श्री रजनीश कुमार : महोदय, यह बहुत आवश्यक है, यह कौन विभाग देगा ? कौन विभाग भुगतान करेगा यह तो मंत्री जी ने बताया ही नहीं ?

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : प्रमोद जी, आप वरीय सदस्य हैं । आपको मौका दिया तो था न हमने, फिर मौका देंगे आगे, बैठिये । बोलिये मिथिलेश जी ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह विषय पहले आ चुका है और मेरा एक अनुरोध होगा कि यह तीन विभाग का मामला है । इन तीनों विभागों को अपने कक्ष में बुलाकर या एक साथ बैठाकर मीटिंग करवा दीजिये और इस पर कोई नीति बनवा दीजिये समस्या का समाधान हो जायेगा ।

अध्यक्ष : हम कक्ष में बैठक बुलाकर, माननीय सदस्य भी वहां रहेंगे, तीनों डिपार्टमेंट भी रहेगा, इसका जल्द समाधान किया जायेगा ।

श्री मिथिलेश तिवारी : धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–438, श्री अविनाश मंगलम (क्षेत्र सं0–47, रानीगंज)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0– 439, श्रीमती बेबी कुमारी (क्षेत्र सं0–91, बोचहां)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां प्रखंड में कुल 20 उच्च माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अवस्थित है, जिसमें सह शिक्षा (Co-eduation)के अंतर्गत सभी विद्यालयों में छात्रा नामांकित हैं तथा अध्यनरत है । प्रखंड के अंतर्गत सभी 20 माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–09 से 12 तक में कुल 6675 छात्रा नामांकित एवं अध्यनरत है।

श्रीमती बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है लेकिन मैं तो मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां प्रखंड में कन्या उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण बच्चियों को शिक्षा में कठिनाई हो रही है । तो कन्या उच्च विद्यालय खोलने के मैं मांग कर रही हूं इसलिये कि माननीय मंत्री जी जवाब दिये हैं तो सभी माध्यमिक और उच्च विद्यालय में सभी बच्चियां पढ़ती हैं लेकिन मैं कन्या विद्यालय की मांग कर रही हूं बोचहां प्रखंड में । काफी कठिनाई हो रही है तो आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि कन्या विद्यालय खोला जाए।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो उत्तर दिया है, उसमें स्पष्ट है कि जो Co-eduational Instituiton हैं वहां पर अभी 6675 छात्रा नामांकित हैं आज के दिनों में । अगर आवश्यकता पड़ी अन्य स्कूलों की तो उस पर

विचार किया जायेगा । लेकिन अन्य कई जगहों पर स्कूलों की कमी है उसको पूरा करने के पश्चात ही ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां काफी कठिनाई हो रही है । मैं तो आग्रह कर रही हूं मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : सरकार निश्चित विचार करेगी मंत्री जी ने कहा है । आपके सुझाव को सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और माननीय मंत्री जी ने कहा भी कि आवश्यक कार्रवाई जरूर की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–440, श्री आलोक कुमार मेहता (क्षेत्र सं0–134, उजियारपुर)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–441, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव (क्षेत्र सं0–)

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चांपारण जिला के चकिया प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसौनी खेम कुरिया विभागीय निदेशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय, परसैनी खेम के प्रांगण में विद्यालय हेतु निर्मित 2 कमरा में कक्षा संचालित किया जा रहा है ।

प्रधानाध्यापक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वर्तमान में भूमि उपलब्ध नहीं है । जिला शिक्षा पदाधिकारी, मोतिहारी के पत्रांक–288, दिनांक–02.02.2026 के द्वारा अंचलाधिकारी, प्रखंड–चकिया को विभागीय मापदंड के अनुरूप भूमि उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य प्राथमिकता पर करा लिया जायेगा ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं..

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : विभाग ने जवाब दिया है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, परसौनी खेम कुरिया विभागीय निदेशानुसार वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मध्य विद्यालय, परसैनी खेम के प्रांगण में विद्यालय हेतु निर्मित 2 कमरा में कक्षा संचालित किया जा रहा है और सी0ओ0 चकिया से जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गयी है । तो हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि कब तक जमीन उपलब्ध कराकर वहां पर भवन निर्माण कराया जायेगा ताकि वहां विद्यार्थी पढ़ सके ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको प्राथमिकता के तौर पर हम खुद डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके कोशिश करेंगे कि वहां पर जमीन उपलब्धता बहुत आवश्यक है इस निर्माण के लिये । माननीय सदस्य ने अपनी बातों को सही कहा है । इसको हमलोग प्राथमिकता के तौर पर आज या कल डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट से बात करके कहेंगे की जमीन की उपलब्धता करायें ।

टर्न–7 / धिरेन्द्र / 10.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं । अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–10 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री रणविजय साहू, स०वि०स०, श्री राहुल कुमार, स०वि०स०, श्री मनोज विश्वास, स०वि०स०, श्री गौतम कृष्ण, स०वि०स०, श्री अजय कुमार, स०वि०स०, श्री अरूण सिंह, स०वि०स०, श्री अमरेन्द्र कुमार, स०वि०स०, श्री संदीप सौरभ, स०वि०स०, श्री शंकर प्रसाद, स०वि०स०, श्री अभिषेक रंजन, स०वि०स०, मो० कमरुल होदा, स०वि०स०, श्री सुरेन्द्र प्रसाद, स०वि०स०, श्रीमती सावित्री देवी, स०वि०स०, श्रीमती करिश्मा, स०वि०स० । आज दिनांक–10 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद तथा मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री बैधनाथ प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनिया प्रखंड के जमुआ घाट पर लालबकिया नदी पर बनी पुल मधु छपरा की ओर जाती है । गुणवत्ता विहिन निर्मित पुल पर पहुँच पथ का निर्माण अब तक नहीं हो सका है, जिससे आवागमन बाधित है । सरकार पुल के गुणवत्ता की जाँच कर पहुँच पथ का निर्माण कराये ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, अतरी विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की अभियान बसेरा–2 योजना अंतर्गत भूमिहीनों को तीन डिसमिल भूमि देने का प्रावधान है किन्तु सीमित लाभुकों का चयन कर खानापूर्ति की जा रही है । कई लाभुकों को पर्चा मिलने के बाद भी कब्जा नहीं मिला है । सरकार पाँच वर्षों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

डॉ॰ स्वेता गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिले में खेल प्रतिभाओं की प्रचुरता के बावजूद आधुनिक खेल सुविधाओं एवं मानक स्टेडियम के अभाव में खिलाड़ी अस्थायी मैदानों में अभ्यास करने को विवश हैं । इससे युवाओं के प्रशिक्षण एवं अवसर सीमित हो रहे हैं । सरकार से शिवहर में बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम निर्माण की मांग करती हूँ ।

मो॰ कमरुल होदा : अध्यक्ष महोदय, जिला व प्रखण्ड किशनगंज के हालामाला पंचायत अंतर्गत ग्राम–ताराबाड़ी में दिनांक–02.02.2026 को बिजली के 48 खंभों में लगे तार की चोरी हो गई है फलस्वरूप 35 किसानों के खेत की सिंचाई बाधित है ।

अतः मैं अविलंब बिजली का तार लगाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम चंपारण जिलान्तर्गत प्रखंड–बगहा–2 में मदनपुर से पनियावा एन॰एच॰–727 तक सड़क का मोटरेबुल कार्य स्वीकृत होकर टेंडर हो गया है, उक्त सड़क वन विभाग में आने के कारण एन॰ओ॰सी॰ नहीं मिलने से मोटरेबुल कार्य लंबित है । मैं सदन के माध्यम से सरकार से एन॰ओ॰सी॰ के लिए मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अभिषेक रंजन ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक–07.02.2026 की शाम को 06 वर्षीय बच्ची तनु कुमारी को दरिंदों द्वारा दुष्कर्म कर निर्मम हत्या कर दी गयी जो बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है । दरिंदों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी दिलाने की मांग करता हूँ ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, सिंघिया प्रखण्ड के हरदिया पंचायत अंतर्गत महुआटोला के निकट कमला नदी पर उच्चस्तरीय आर॰सी॰सी॰ पुल का निर्माण कराए जाने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नोखा विधान सभा के प्रखंड नोखा में दहासील सरोवर है । वहां पर प्राचीन मंदिर है । सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन स्थल घोषित करने का सरकार से मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह । आपका शून्यकाल अमान्य किया गया है, उसकी वजह है कि आपने शून्यकाल 155 शब्दों में दिया है तो हमारा आग्रह होगा कि या तो आप संक्षेप में अपनी बातों को रख दीजिये या फिर कल ले आइयेगा जो आपको सुविधा हो ।

श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह : महोदय, धन्यवाद । औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड में देवनगर पंचायत क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की मांग है । यह एक आकांक्षी

प्रखंड के रूप में भी चिन्हित है । यही आग्रह है कि हमारे क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज खोला जाय । धन्यवाद ।

श्री उदय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला के डोभी प्रखंड में कन्या उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण छात्राओं को अत्याधिक दूरी तय करके गया जी, शेरघाटी, बारहचट्टी प्रखंड जाना पड़ता है जिसके कारण विद्यार्थियों एवं उनके परिजनों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं प्रखंड डोभी में कन्या उच्च विद्यालय की स्थापना करवाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती विनीता मेहता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखण्ड में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं हैं जिससे जिले के किसान, ग्रामीण जनता सरकारी ऋण और सरकारी लाभ से वंचित रह जाते हैं, सरकार से नवादा जिला के रोह प्रखण्ड में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खोलने की मांग करती हूँ ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिले के विलुप्त या मृतप्राय हो रही नदियाँ कर्मनाशा, दुर्गावती, गोरिया, धर्मावती, गेहुवनवाँ नदी का उनके प्राकृतिक पारिस्थितिकी क्षेत्रों को बहालकर, जलभराव क्षेत्रों को पुनर्जीवित कर, गाद निकालकर, तटों पर वृक्षारोपण कर एवं अवैध बाँधों को हटाकर जीर्णोद्धार करने की माँग करता हूँ ।

श्री ई॰ शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगाँव के आसपास ईंटभट्टा संचालकों द्वारा घोघा नाला के निकासी मार्ग पर अवैध रास्ते बना दिए गए हैं । इससे कोदवार, सिमरो, सालपुर, नदियामा, राजपुर आदि गाँवों के खेतों में जलजमाव बना रहता है ।

अतः अवैध अतिक्रमण हटाकर प्राकृतिक जलप्रवाह बहाल करने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री रामचंद्र सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधान सभा के पंचायत दहमा खैरी–खुट्टा के खैरी डीह वार्ड नं॰–07 महेन्द्र पंडित के घर के निकट से कुशेश्वर मास्टर के घर होते हुए नीरज सरपंच के घर तक सड़क निर्माण कार्य की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गौतम कृष्ण ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अमरेन्द्र कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री बबलू कुमार उर्फ बबलू मंडल : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया और मानसी शहर में हजारों फुटपाथ दुकानदार अतिक्रमण हटाए जाने के बाद बेरोजगार हो गए हैं जिससे हजारों परिवारों की रोजी–रोटी पर संकट है । इनके पुनर्वास हेतु स्थायी वेंडिंग जोन अथवा बाजार परिसर उपलब्ध कराने की माँग मैं सरकार से करता हूँ ।

श्री रामानंद मंडल : अध्यक्ष महोदय, लखीसराय जिला के सुर्यगढ़ा विधान सभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं होने से वहाँ के छात्र–छात्राएं 30 कि॰मी॰ दूर लखीसराय जिला मुख्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करती है । सरकार से सुर्यगढ़ा प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्यगण के द्वारा श्री नितिन नवीन, माननीय सदस्य–सह–भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का खड़ा हो कर स्वागत किया गया)

टर्न–8 / अंजली / 10.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जायं । माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठ जाइए। शांति बनाए रखें ।

माननीय सदस्यगण, यह बड़े हर्ष का विषय है कि इस सदन के माननीय सदस्य आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस सदन में आए हैं, यह हमारे लिए गर्व का विषय है, उनका स्वागत तो होना ही चाहिए । मैं चाहूंगा कि सभी दल के नेता एक–एक करके उन्हें बधाई दें, फिर अंत में मैं अपनी बात कहूंगा । इसके बाद शेष शून्यकाल एवं अन्य सूचीबद्ध विषय लिये जायेंगे । माननीय मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ।

(व्यवधान)

शांति बनाए रखें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसी सूचना आपने सदन को दी है और आपने सही ही कहा है कि यह आज इस सदन के लिए भी गौरव की बात है कि हम सब लोगों के बीच के एक साथी एक बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं और इनके उस पद पर आसीन होने के लिए हम इनके दल भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेतृत्व हैं, प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी को हम बधाई देते हैं और बिहारवासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, वैसे हमलोगों को लगता है, जिन लोगों ने नितिन नवीन जी को नजदीक से देखा है कि भाजपा नेतृत्व का यह चयन स्वाभाविक ही है, क्योंकि लगता है कि उन्होंने पार्टी के सर्वोच्च पद पर आसीन करने के लिए व्यक्तियों के चयन के सिलसिले में जो भी मापदंड या मानदंड निर्धारित किए होंगे उसमें हमारे नवीन, न सिर्फ खरे उतरे होंगे, बल्कि जितने भी नामों पर विचार चल रहा होगा, उन सबों में इनका स्थान अव्वल नजर आया होगा, इसलिए हमारे नवीन जी आज वहां पहुंचे हैं ।

महोदय, हमलोगों ने भी जिन्होंने इनको करीब से देखा है, ये जितने ही सरल हैं, उतने ही दक्ष हैं, जितने ही सहज हैं, उतने ही कुशल हैं और

जिस तरीके से उन्होंने इस सदन के सदस्य के रूप में, न सिर्फ सदस्य के रूप में, बल्कि सरकार में एक मंत्री के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन इसी सदन में किया है, यह हम सब के लिए स्मरणीय है और हम सब लोगों ने न सिर्फ हम सब लोग प्रभावित हैं बल्कि इनसे इस रूप में हमलोगों ने बहुत कुछ इनके विचारों को आगे बढ़ाने का सोचा है और इस उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, ये असाधारण है और महोदय, भाजपा नेतृत्व ने जो भरोसा किया है यह भरोसा भी असाधारण है । इसलिए यह असाधारण उपलब्धि जो बिहारवासियों को हुई है, तो हम सदन के सदस्यों की तरफ से ही नहीं, बिहारवासियों की तरफ से भाजपा नेतृत्व को हम बधाई देते हैं और इस पद पर आसीन होने के लिए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि हमारे नवीन भाजपा को भी नवीन कलेवर में डालकर उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे कि जिससे भविष्य में भी किसी बिहारी पर भरोसा करने में किसी को हिचक नहीं हो । महोदय, ये भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हम बिहारवासी किसी के भरोसे के इतने हकदार और काबिल हैं कि कोई हम पर भरोसा कर सकता है, यह हमारे नवीन की उपलब्धि बताएगी, जब हमारे नवीन, नवीन उपलब्धियों से भाजपा को और हमारे एन0डी0ए0 को, क्योंकि हमलोग भी एन0डी0ए0 में हैं महोदय, हमारे साथी दल का कोई नेतृत्व आगे चमकता है, दोनों बात है न कि नेतृत्व भी चमक रहा है और बिहार भी चमक रहा है, तो दोनों जब चमक रहा है, तो हम सभी बिहारवासी आह्लादित हैं । एक बार फिर से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी को बधाई और बिहारवासियों की तरफ से आभार प्रकट करते हुए हम अपने नवीन को शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में ये नई ऊंचाइयों तक पार्टी को भी ले जायं, एन0डी0ए0 को भी ले जायं, हम सभी गौरवान्वित होंगे महोदय । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री सम्राट चौधरी जी ।

श्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज यह ऐतिहासिक दिन है और जैसा आपने बताया कि प्रथम बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आदरणीय नितिन नवीन जी बिहार विधान सभा में आए हैं, यह भारत के इतिहास में अपने आप में इस सदन का कोई व्यक्ति इतने बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो और इस सदन का सदस्य हो, यह सबसे बड़ी गौरव की बात हमलागों के लिए है ।

हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षामंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जिस तरह भरोसा दिखाया और ठीक कहा विजय बाबू ने जिस तरह बिहारी को इतना बड़ा दायित्व देने का काम किया और जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सरकार का मुखिया हूं, लेकिन नितिन नवीन जी हमारे बॉस हैं, यह सबसे बड़ी बात है । प्रधानमंत्री जी संगठन के तौर पर

जिस व्यक्ति को बॉस मानते हों वह संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से लंबे समय से साथ में नितिन नवीन जी काम किए सरकार में मंत्री के तौर पर, पथ निर्माण मंत्री के तौर पर भी काम किए और बिहार जैसे राज्य में इंवेस्टमेंट भी लाने का काम किया, 17 हजार करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट HAM मॉडल के तौर पर रोड सेक्टर में लाने वाले पहले मंत्री हमारे नितिन नवीन जी रहे हैं । कई चीजें नगर विकास एवं आवास विभाग में भी इन्होंने चेंजेज किए हैं, तो आगे भी संगठन के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर जहां आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 की ओर देख रहा है, हमलोग जब पहली बार यह सुने, तो अपने आप में हमलोगों को गौरव महसूस हुआ कि जिस तरह बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर बिहार में एन0डी0ए0 की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाया, उसका प्राइज यदि मिला है तो वह नितिन नवीन जी के तौर पर बिहार की जनता को मिला है । इसलिए मैं फिर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और पूरे बिहारवासी और पूरे सदन की तरफ से उनको विशेष बधाई देता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजू तिवारी जी ।

श्री राजू तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक पल है । आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सदन के आदरणीय श्री नितिन नवीन जी जो बने हैं, निश्चित रूप से हम अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ से, बिहार के बेटा हैं, बिहार के गौरव और बिहार का आज नाम पूरे विश्व में आज इनके माध्यम से मजबूत हुआ है और जैसा कि हमारे मंत्री जी ने बताया कि बिहारियों पर जो भरोसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने किया है, निश्चित रूप से हमलोग इनको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार के अपने माता–पिता का नाम, बिहार का नाम इनके नेतृत्व में और मजबूत होगा और ये अपना यश–कीर्ति पूरे देश में, पूरे विश्व में फैलाएंगे । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री माधव आनंद ।

टर्न–9 / पुलकित / 10.02.2026

श्री माधव आनंद : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एवं उपेंद्र कुशवाहा जी की तरफ से आदरणीय नितिन नवीन जी को बहुत–बहुत शुभकामना देता हूँ । आज इस सदन के लिए ऐतिहासिक दिन है कि नवनियुक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इनका आगमन हुआ है । पूरे बिहार के लिए यह गौरव का विषय है। मैं तो लगातार कहता रहा हूं कि जिस तरह बिहारियों को, बिहारी शब्द गाली समझा जाता था, आज

वही इस बिहार के लाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हमलोगों के लिए कितना गौरव का विषय है। खासकर हमारे जैसे युवा साथी के लिए तो और भी अत्यंत गौरव का विषय है कि हम लोग भी आशा कर सकते हैं कि बीजेपी किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचा सकता है, तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से इनमें जो नेतृत्व की क्षमता है, वो अकल्पनीय है। हमको भी काफी वक्त मिला इनको समझने में, बहुत दिनों से इनकी लगातार बातचीत भी हो रही थी और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भारत वैश्विक स्तर पर नाम कमा रहा है, नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बीजेपी और आगे बढ़ेगी और हमारा एनडीए और मजबूत होगा। पुनः एक बार मैं अपनी पार्टी के तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा जी के तरफ से आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : श्रीमती ज्योति देवी ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार विधानसभा में यह गौरव का विषय है कि माननीय श्री नितिन नवीन जी जो हम सबके ही साथी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार विधान सभा में पधारे हैं । मैं हिंदुस्तानी आवाम सेक्युलर एवं जीतन राम मांझी जी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ0 संतोष जी के तरफ से बधाई देती हूँ । मात्र 45 साल की उम्र में ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूं। माननीय श्री नितिन नवीन जी, इस तरह जिस तरह बिहार में मंत्री एवं विधायक रहते हुए निरंतर परिश्रम से राज्य के विकास के लिए अहम भूमिका निभाए हैं, उसी तरह से मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भाजपा, बिहार एवं पूरा देश नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। आज मैं उनके माता–पिता को भी श्रद्धापूर्वक नमन करती हूं, जिनके संस्कार, मूल्य और मार्गदर्शन ही आज माननीय श्री नितिन नवीन जी के व्यक्तित्व और नेतृत्व में स्पष्ट दिखाई देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार विधानसभा के माननीय श्री नितिन नवीन जी का हार्दिक स्वागत करती हूं। इस नेक चुनाव के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूं और बधाई देती हूं कि इस पद पर भी आ करके बिहार तथा पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। महोदय, यह इतिहास रहा है कि बिहार ऊर्जावानों का देश रहा है। यहां पर बहुत ऐसे महान नेता आए, जिन्होंने इतिहास बनाया और मार्गदर्शन समाज को दिया। उसी प्रकार से मैं हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आप भी ऐसा काम करें कि युग–युग तक आपका नाम हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी ।

श्री संजय सरावगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के लिए ही नहीं, हम सबके लिए बड़ा ही गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण है। जब इस सदन में हमारे युवा,

कर्मठ, जुझारू, जनप्रिय और लोकप्रिय साथी आदरणीय नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम सबके बीच मौजूद हैं। मैं इन्हें बहुत–बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस सदन की ओर से, अपनी ओर से, संपूर्ण बिहार की ओर से आपको आपकी नई भूमिका के लिए पुनः शुभकामनाएं देता हूं। आपका विनीत स्वभाव, जनता के प्रति आपका लगाव, अपने कर्तव्य के प्रति आपका समर्पण बोध, हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पाकर बिहार की राजनीति अंगड़ाई ले रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आपका सक्षम नेतृत्व देश के राजनीति परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन इस बात का गवाह ही नहीं, भागीदार भी बन रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष, हमारे युवा साथी माननीय नितिन नवीन जी हैं। आपका चयन यह दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है, जहां समर्पित कार्यकर्ताओं का पूरा ख्याल रखा जाता है। बिहार ने देश को हमेशा नई दिशा दिखलाई है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में माननीय नितिन नवीन जी का चयन भी राजनीति को नई दिशा दे रहा है। यह हम सब के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है। मैं एक बार पुनः माननीय नितिन नवीन जी को अपनी ओर से, सदन की ओर से और संपूर्ण बिहार की ओर से बधाई देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, हम सभी आपके निर्णय के साथ रहेंगे, आपके आदेशों का अनुपालन करेंगे और सरकार द्वारा किए जा रहे लोकहित के कार्यों को जन–जन तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आपके युवा और समर्पित नेतृत्व की बदौलत हम वहां भी अपनी पार्टी को जीत सुनिश्चित करेंगे जहां आज अपनी सरकार नहीं है, चाहे वह बंगाल हो, केरल हो, तमिलनाडु हो या कोई और इलाका हो। हमें आपके नेतृत्व पर आस्था और पूर्ण विश्वास है। हम सब आपके साथ हैं। मैं पुनः आपको आपके सक्षम नेतृत्व के लिए, आपके साथ हम सभी लोगों ने लगातार काम भी किया है और निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही बिहार भी अपनी उस ऊंचाइयों के एक मुकाम पर पहुंचेगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है विकसित भारत का निर्माण, तो निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में बिहार भी विकसित बनेगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ पुनः आपको बहुत–बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय बिहार।

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। लोकतंत्र की जननी की इस भूमि पर, लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर में आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो

इस सदन के सदस्य हैं और लंबे समय से सदस्य हैं और जिन्होंने अपने व्यवहार, कार्यकुशलता, सरलता, सुलभता के साथ अपनी पहचान बनाई। आज शून्य से शिखर तक पहुंचने के सफर में आज सारा सदन गौरवान्वित है। पूरे बिहार की जनता को भी आज लग रहा होगा कि शून्य से शिखर, हमारे कर्तव्य पथ पर ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ काम करने का पुरस्कार लोकतंत्रीय पद्धति से जो पार्टी काम कर रही है, वहां संभव है। जो सपना देख सकते हैं, वह साकार हो सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के उस स्वरूप को भी दिखाता है और पूर्व के वक्ताओं ने ठीक कहा कि आज हमारे प्रधान सेवक, सेवा के भाव से काम करने वाले हर कार्यकर्ता को सम्मान के भाव से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं। आज सारा बिहारी यह आशान्वित ही नहीं, गौरवान्वित भी हुआ है कि माननीय नितिन नवीन जी के कर्तव्य पथ पर बढ़कर जो विश्वास हासिल किए हैं, वह विश्वास और ऊंचे मुकाम को प्राप्त करे। हमारा बिहारी गौरवान्वित हो। बिहार गौरवशाली गाथा लिखने में आपकी बड़ी भूमिका बने और हमारा बिहार पूरे देश के अंदर जिस नजरिये से देखा जा रहा था, वह नजरिया बदलने के लिए हम अपने शीर्षस्थ नेतृत्व को हृदय से आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं और पूरा सदन पुनः आपका सम्मान, हर बिहारी आशान्वित होकर बिहार की गौरव गाथा में आपकी भागीदारी और सदन की नई भूमिका आज सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार बनाने का एक नए उत्साह के साथ कदम बढ़ाएगा। ये सारे लोग आपको गौरवान्वित करने के उस कार्य में पूरी तरह से पवित्रता के साथ भागीदारी करेंगे। पुनः हृदय से आपका अभिनंदन, स्वागत। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज बिहार विधानसभा के इस गरिमामय सदन में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं गौरवपूर्ण अवसर के साक्षी बन रहे हैं। बिहार की पावन भूमि से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए माननीय श्री नितिन नवीन जी का सम्मान करना इस सदन के लिए विशेष हर्ष और गर्व का विषय है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर माननीय श्री नितिन नवीन जी को सुशोभित होने के इस अवसर पर मैं बिहार विधानसभा की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ।

माननीय श्री नितिन नवीन जी का यह पद ग्रहण न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपितु समग्र बिहार और देश के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। ये बिहार की माटी से निकले ऐसे सपूत हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत, संगठन कौशल, युवा ऊर्जा और समर्पण से आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाली है। महज 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में एक मिसाल है।

श्री नितिन नवीन जी ने कम उम्र में ही चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और पहली बार 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2010 से ये लगातार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे।

(क्रमशः)

टर्न–10 / हेमन्त / 10.02.2026

(क्रमशः)

अध्यक्ष : 2010, 2015, 2020 और 2025 में जीत हासिल कर लगातार पांचवी बार विधायक चुने गये हैं। आपने बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में पथ निर्माण, शहरी विकास एवं आवास और कानून जैसे महत्वपूर्ण विभागों का भी कार्यभार संभाला है।

यह पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण है कि यहां के एक जनप्रतिनिधि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक पद पर आसीन हुए हैं। इनका यह चयन इनकी योग्यता, अनुभव और संगठन के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। यह उपलब्धि न केवल इनके व्यक्तिगत परिश्रम का परिणाम है, बल्कि बिहार की राजनीतिक चेतना और प्रतिभा का भी परिचायक है।

आज जब देश देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मूल मंत्र ''सबका साथ–सबका विकास–सबका विश्वास'' की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो संगठन, शासन और समाज तीनों को जोड़ सके। श्री नितिन नवीन जी इस भूमिका में स्वयं को बार–बार सिद्ध करते आए हैं। इनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि राजनीति में सिद्धांत और व्यवहार के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए।

श्री नितिन नवीन जी का राजनीतिक जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की त्रिवेणी रहा है। एक युवा विधायक से लेकर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में इन्होंने अपनी जो अमिट छाप छोड़ी है, वह हम सभी के लिए अनुकरणीय है। सदन के भीतर इनके तर्कपूर्ण वक्तव्य और जनहित के मुद्दों पर इनकी संवेदनशीलता ने सदैव संसदीय गरिमा को बढ़ाया है। बिहार के विकास, विशेषकर पथ निर्माण और अन्य विभागों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में जो भूमिका आपने निभाई है, वह प्रशासनिक दक्षता का जीवंत प्रमाण है।

इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नई पीढ़ी के लिए श्री नितिन नवीन जी एक प्रेरणास्रोत हैं। इनका जीवन यह सिखाता है कि निरंतर अध्ययन, जमीनी जुड़ाव और संगठन के प्रति निष्ठा से राजनीति

को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। आज जब राजनीति को लेकर समाज में अनेक प्रश्न उठते हैं तब ऐसे उदाहरण आशा का संचार करते हैं।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष के रूप में और इस सदन के संरक्षक के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं और जनहित की भावना के साथ आपका हर प्रयास इस सदन में सम्मान पायेगा।

श्री नितिन नवीन, नितिन संस्कृत शब्द नीति से बना है, जिसका अर्थ है नियमों का पालन करने वाला, नीति का ज्ञाता और नवीन का शाब्दिक अर्थ नया, नूतन, ताजा, आधुनिक, या फिर अभिनव होता है। संस्कृत के नव शब्द से उत्पन्न, नवीन है। यह नाम दृढ़ सोच, नेतृत्व, विनम्रता और नैतिकता के साथ–साथ सकारात्मक गुणों का स्वामी होता है। आपका स्वभाव शांत, सहज और मिलनसार होने के कारण संगठन में, विधायी कार्यों में जान फूँकता है। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति पर विचार रख रहा हूँ जो संगठन, सेवा और संकल्प के माध्यम से समाज में नई दिशा देने का कार्य करता है। मैं नितिन जी से कहना चाहता हूँ,

''नितिन नवीन हुआ नाम जो विश्वास जगाता है,
सेवा, संकल्प, साहस हर दिल में बस जाता है।
कदम–कदम पर राष्ट्र हित, यही पहचान बनी,
नितिन तो वैसा है जो सबको साथ लेकर चलता है।''

नितिन नवीन जी का राजनीतिक जीवन में उत्थान युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नेतृत्व पद से नहीं, सेवा एवं आचरण से पहचाना जाता है, यह सदा आपने कृतार्थ किया है। आपके राज्य में कटुता नहीं, तर्क है, अहंकार नहीं, आत्मविश्वास है, अपमान नहीं, सम्मान है और उद्दंडता नहीं, शालीनता है। आपके मार्गदर्शन में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर संगठन, सेवा, समर्पण के बल पर माननीय प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, विकसित भारत और विकसित बिहार के सपने को साकार करेंगे। माँ भारती के वैभव को विश्व में पुनः स्थापित करेंगे। इन्हीं विश्वासों के साथ अंत में

''नितिन नवीन के हाथ में जन–जन का है विश्वास,
संगठन पथ पर अग्रसर कर बनेगा नया इतिहास।''

अंत में चाहूंगा कि आज माननीय नितिन नवीन से आग्रह होगा कि आप भी दो शब्द कहें।

श्री नितिन नवीन : माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक सदस्य के रूप में जिस प्रकार से मुझे आज सम्मान दिया है और पूरा सदन जिस प्रकार से, मेरा विधायकी जीवन करीब 20 साल का रहा है, अभी तक का जो सफर है और उसमें सब लोगों के साथ मिलकर

जब काम शुरू किये और मुझे लगा कि आज के दिन की मैंने कभी कल्पना नहीं की थी और आज जिस प्रकार से अपने सभी अभिभावकों के शब्दों में, मैं कहूँ, जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं पूरे सदन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सदन में अपने माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, अपने वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, सभी दलों के नेता हमारे आदरणीय श्रवण कुमार जी, हमारे लोजपा के राजू तिवारी जी, ज्योति मांझी जी, माधव आनंद जी, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव जी, मैं सबको और पूरे सदन को, हमारे सभी साथी जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और सबको आभार व्यक्त करता हूँ।

माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से हम लोग सदन में आए तब से उनको काम करते देखा और मैं मानता हूँ कि राजनीति की दृष्टि से जो नए लोग आते हैं राजनीति में, जहाँ एक ओर अपनी पार्टी के विचारों से हम लोग आते हैं और वही जनता के बीच में भी एक मत लेकर आते हैं। जनता का मत जब मिलता है, तो कई मुद्दों के साथ हम उनसे जुड़ते भी हैं। लेकिन उन मुद्दों के साथ अपने विचारों के साथ आगे बढ़ने की जो कला यहाँ पर सीखने को मिलती है, सदन में आने के बाद कि कैसे हम अपने विषयों को भी उठाएँ, अनुशासन की गरिमा को भी रखें और साथ ही साथ यह भी कह सकते हैं कि अपनी जनता की आवाज बनकर भी हम बैठें। तो कहीं ना कहीं इन तीनों विषयों को साथ में लेकर एक विधायक के रूप में आप और हम यहाँ बैठते हैं। सदन की भी गरिमा कैसे बढ़े, इसकी भी चिंता करते हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कई अवसरों पर देखा है। अध्यक्ष जी, 2006 में मैं पहली बार विधायक बना और तब से लेकर मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से पूरे बिहार की छवि को, अभी चर्चा विजय चौधरी जी जिन शब्दों की कर रहे थे, हम लोग भी बिहार से बाहर जाकर पढ़े हैं और पढ़ाई–लिखाई करने के दौरान किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग बिहार के लिए किया जाता था, 2005 के पहले का कालखंड। मैं इस सदन में सत्ता और विपक्ष के रूप में नहीं, एक उस छात्र के रूप में बता रहा हूं जब हम लोग भी पढ़ते थे और पूरे बिहार की उस छवि को उस समय से लेकर और आज जब हम 2026 में खड़े हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि अपना बिहार आज देश में भी अगर सम्मान पा रहा है, तो कहीं न कहीं हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में जो बिहार की छवि बदली है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा किया। पार्टी के काम करने के उन्होंने सिस्टम को हमेशा सम्मान दिया है और मैं यह मानता हूं कि इस सदन में कई ऐसे हमारे पूर्व के वरिष्ठ नेता रहे हैं जिन्होंने बिहार को कई बार गरिमामय समय दिया, लेकिन कुछ लोग जो अभी साक्षात रूप से हमारे सामने हैं, जो नेतृत्व हमारे सामने है, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं कह सकता हूं कि देश के

प्रधानमंत्री जी ने जहां सेवा के भाव से काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुशासन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकार में रहते हुए कैसे हम ट्रांसपेरेंट सरकार दे पाएं, यह छवि कैसे बने, उस परिस्थिति में जब बिहार निकल कर आया था और आज जिस परिस्थिति में हम बैठे हैं, मुझे लगता है यहां पर बैठे हुए सभी सदस्यों के लिए यह अपने आप में एक ऐसा नेतृत्व है जिससे हम सब को प्रेरणा लेने की हमेशा जरूरत रहेगी। यह सदन मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद, मैं भी सदन का सदस्य बना और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं, अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जिस भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ कर मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है? मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा यह ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आपको आगे लेकर चलूं और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जन प्रतिनिधियों को यह बहुत आवश्यकता है, हम सब के लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़ें, उस भावना के साथ जुड़ें।

(क्रमशः)

टर्न–11 / संगीता / 10.02.2026

श्री नितिन नवीन (क्रमशः) : ताकि जब हम नहीं भी रहें जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी यही भावना रहे । हमारे राजनीति में सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे । साथ ही साथ सदन की हर छोटी–बड़ी घटनाओं से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है । हमलोगों ने सदन में सरकार में रहते हुए सरकार के विषयों को कैसे उठाया जाय, कैसे अपना काम विधायक के रूप में कराया जाय और साथ में विपक्ष में भी रहे तो विपक्ष की भी जो गरिमा होती है उस गरिमा के साथ कैसे काम किया जाय, दोनों ही समय में हमें काम करने का मौका मिला और मैं मानता हूं कि मेरे राजनीतिक जीवन में इस सदन के कामकाज को देखकर बहुत सीखने का मौका मिला है तो यह अपने–आप में एक ऐसा स्थान है जहां देश ने, विश्व ने लोकतंत्र का इतिहास कहते हैं कि वैभवशाली इतिहास में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार और उस लोकतंत्र की जननी में इस विधान सभा का बहुत बड़ा हमेशा योगदान रहा है और रहेगा और हम आज के अपने सभी सदस्यों का आभार भी व्यक्त करते हैं और अध्यक्ष जी, इतना विश्वास दिलाते हैं आप सबको कि एक विधायक के रूप में जो भूमिका, हम मंत्री के रूप में जो मौका पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और

पार्टी ने भूमिका जरूर बदली है पर विधायक के रूप में अगर मैं यहां हूं तो निश्चित रूप से यहां के राज्य के विकास में जो भी मेरी भूमिका हो पाएगी, दोनों ही हमारे एन0डी0ए0 दलों के लोग जो भी मुझसे उम्मीद करेंगे मैं निश्चित रूप से बिहार के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है 2047 के विकसित भारत का और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिशा में निरंतर आगे लेकर बढ़ रहे हैं हमलोग भी उस भूमिका में उन दोनों के नेतृत्व में पूरी ताकत से बिहार को विकास के पथ पर और तेजी से आगे ले जाने में पूरी अपनी योगदान देंगे । साथ ही साथ मैं अपने सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप सब मिलकर हम बिहार की वह टीम हैं सत्ता और विपक्ष में कोई भी लोग बैठे पर बिहार की छवि अगर बड़ी होती है तो उसका सम्मान सबको मिलता है । आज जब मैं देश के दूसरे राज्यों में जाता हूं लोग हमें उस रूप में नहीं जानते लेकिन बिहार के नाम पर जब लोग मिलने आते हैं और जिस भाव से मिलने आते हैं तो लगता है कि आज बिहार के लोगों को एक जुड़ाव का एक केंद्र मिल गया है । मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सम्मान आपने दिया है, जो सम्मान पार्टी ने दिया है उससे बिहार में देशभर में रह रहे सभी बिहार के लोगों को मैं जोड़कर निश्चित रूप से बिहार एक गर्व का विषय बने, बिहार एक सम्मान का विषय बने और हम अपने पुराने गौवशाली इतिहास को पुनः वापस लाने की दिशा में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग काम कर रहे हैं निश्चित रूप से 2047 में भारत भी विकसित होगा, बिहार भी विकसित होगा और बिहार अपना पुराना गौरव भी वापस लेकर आएगा । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शेष शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल जी अपना शून्यकाल पढ़ें ।

<u>शून्यकाल की शेष सूचनाएं</u>

श्री ललित नारायण मंडल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई नितिन नवीन जी का स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अंगिका भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत जोकीहाट प्रखण्ड के ग्राम पंचायत सिमरिया में धोबानिया चौक के निकट बागमारा

जानेवाली सड़क में जमुना नदी में लोहे का जर्जर पुल रहने के कारण आवागमन बाधित है भारी वाहनों का परिचालन बंद है ।

अतः उक्त जमुना नदी में पुल का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कुछ रिपोर्ट है जिन्हें पहले लेना है ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली, 2025'' एवं ''बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली 2025'' की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य जल विद्युत निगम के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2015–16 तक के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–99 के तहत अधिसूचना सं0–एस0ओ0–145, दिनांक–16.07.2025 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष : बिहार राज्य मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–99 के तहत अधिसूचना सं0–एस0ओ0–145, दिनांक–16.07.2025 की प्रति 14 दिनों तक सदन पटल पर रखी रहेगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना सं0 एस0ओ0–146, दिनांक–16.07.2025, एस0ओ0–149, दिनांक–27.08.2025, एस0ओ0–150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 एवं 162, दिनांक–17.09.2025 की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

उपाध्यक्ष : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना सं0 एस0ओ0–146, दिनांक–16.07.2025, एस0ओ0–149, दिनांक–27.08.2025, एस0ओ0–150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 एवं 162, दिनांक–17.09.2025 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी ।

उपाध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जा रहे हैं ।

शून्यकाल की शेष सूचनाएं

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवरसा प्रखण्ड अन्तर्गत सोनवरसा पंचायत में मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट–लाइट योजना ग्रामीण के तहत जो लाइट लगा है, गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण खराब हो गया है ।

अतः सरकार से मांग करती हूं कि सोनवरसा पंचायत में खराब सोलर–लाइट के स्थान पर नया सोलर लाइट लगावें ।

टर्न–12 / यानपति / 10.02.2026

सुश्री मैथिली ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत अलीनगर विधान सभा क्षेत्र में क्रमशः धनश्यामपुर, अलीनगर एवं तारडीह प्रखंड में आये दिन आगजनी एवं अन्य घटित घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अग्निशमन सामग्रियों सहित फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं ।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : उपाध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अंतर्गत सुरसंड प्रखंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरसंड के अधीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, कुम्मा को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में उत्क्रमित करने हेतु मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, डेहरी विधान सभा अंतर्गत डेहरी डालमियानगर में ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन जाम और दुर्घटनाएं होती रहती है जिससे स्थानीय लोग परेशान है ।

अतः डेहरी डालमियानगर में अविलंब ट्रैफिक पुलिस की तैनाती और सुव्यवस्थित सिग्नल प्रणाली लागू करने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री भरत बिंद : उपाध्यक्ष महोदय, कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ प्रखंड के ग्राम सयदरा एवं ममहान के बीच कोहिरा नदी पर पुल नहीं होने के कारण दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

अतः उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ जी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्या, डॉ0 करिश्मा जी ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

श्री सुजीत पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड के जलसैन पंचायत स्थित मदनपट्टी गांव में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन कई वर्ष पूर्व बनकर पूर्ण हो चुका है, किंतु आजतक विद्यालय को हस्तांतरित नहीं किया गया है ।

अतः सरकार से अविलंब इस दिशा में ठोस (आवश्यक) पहल की मांग करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : उपाध्यक्ष महोदय, छात्र/छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र में अभियंत्रण महाविद्यालय (Engineering College) खोलने की मांग सरकार से करती हूं ।

मो0 सरवर आलम : उपाध्यक्ष महोदय, कोचाधामन के बगलबाड़ी, पटकोईकद्दूभिटा, महीनगांवनूनिया में धारीवाल कंपनी खनन कर धुसबालू उठा रही है, पर स्थानीय लोगों द्वारा निजी कार्य हेतु धुसबालू ले जाने पर विभाग द्वारा चालान काटा जाता है । ग्रामीणों को निजी काम हेतु मिट्टी कटाई की अनुमति मिले, अन्यथा कंपनी के खनन की जांच कर कार्रवाई की जाय।

श्री गुलाम सरवर : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत बायसी प्रखंड के दर्जनों गांव नदी कटाव का भेंट चढ़ जाता है, इसको बचाने का कोई स्थायी कार्य नहीं किया जा सका जिससे हजारों लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है ।

अतः मैं ससमय नदी कटाव रोधक कार्य कराने की मांग करता हूं।

श्रीमती दीपा कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इमामगंज विधान सभा अंतर्गत नगर पंचायत इमामगंज क्षेत्र के रानीगंज से गया तक बिहार राज्य पथ परिवहन की बस सेवा प्रारंभ करने एवं महिलाओं के लिए एक पिंक बस सेवा बहाल करने हेतु सदन से मांग करती हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : उपाध्यक्ष महोदय, गयाजी जिलांतर्गत विधान सभा बाराचट्टी में विधवा, वृद्धजन एवं दिव्यांगजन आठ–दस माह से पेंशन से वंचित हैं । अधिकांश का खाता पी0एन0बी0 में है । उक्त लाभार्थी बैंक में जाते हैं तो रिजेक्ट घोषित करता है । पेंशनधारी परेशान हैं । तत्काल पेंशन भुगतान हेतु मांग करती हूं ।

श्री पप्पू कुमार वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अरवल जिला के कुर्था प्रखंड मुख्यालय में वर्तमान में जो बस स्टैण्ड है बहुत ही छोटा है, पास में जिला परिषद की जमीन उपलब्ध है इसलिए कुर्था मुख्यालय में आधुनिक बस स्टैण्ड बनाने की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जायेंगे और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शून्यकाल की सूचना ली जायेगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री आलोक कुमार सिंह, मुरारी प्रसाद गौतम एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) की ओर से वक्तव्य

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आलोक कुमार सिंह जी की सूचना पूर्व में पढ़ दी गई है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, सरकार द्वारा जवाब दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक खरीफ खरीद विपणन मौसम में राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य, धान अधिप्राप्ति की अवधि एवं अधिप्राप्त धान के विरुद्ध चावल प्राप्ति की अवधि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है । इस वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36 लाख 85 हजार मी0ट0 एवं धान अधिप्राप्ति का अवधि 28.02.2026 तक निर्धारित की गई है । जहां तक रोहतास जिला के धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित करने की बात है इस संबंध में अवगत कराना चाहेंगे कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त जिलावार धान के अनुमानित उत्पादन आंकड़े एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित कुल धान अधिप्राप्ति लक्ष्य के आधार पर जिलावार धान अधिप्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । इस वर्ष भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में फोर्टिफाइड राइस टनल की आपूर्ति फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के जांचकर्ता द्वारा एफ0आर0के0 नमूनों की जांचोपरांत फिट फॉर लैंडिंग प्रमाणपत्र सही पाये जाने के बाद उक्त एफ0आर0के0 की आपूर्ति मिलों को की जा रही है । जिसके कारण मिलों को एफ0आर0के0 की आपूर्ति में विलंब हो रही है । तथा पैक्सों द्वारा निगम के संग्रहण केंद्रों में भी फोर्टिफाइड चावल जमा कराने की गति धीमी है । उल्लखनीय है कि भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष एफ0एस0एस0ओ0आई0 से जांच की व्यवस्था की गई है जबकि पिछले वर्ष खरीफ विपणन में वर्ष–2024–25 में एफ0आर0के0 की जांच एस0एफ0सी0 द्वारा अधिकृत लैब से की जाती थी । जो वर्तमान समय की तुलना में शीघ्र जांच गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त हो जाता था । राज्य सरकार राज्य के किसानों को भारत सरकार द्वारा धान के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने एवं पैक्स के हितों को संरक्षित करने के लिए कृतसंकल्पित है ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / मुकुल / 10.02.2026

क्रमशः

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : बिहार राज्य के लिए निर्धारित धान अधिप्राप्ति लक्ष्य 36 लाख 85 हजार मीट्रिक टन को वृद्धि कर 85 लाख मीट्रिक टन करने तथा एफ0आर0के0 की आपूर्ति राज्य के सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में सुलभ करने हेतु भारत सरकार से लगातार अनुरोध एवं पत्राचार करते हुए सतत प्रयास किया जा रहा है । अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार अब तक राज्य के 3 लाख 19 हजार 136 किसानों से 21 लाख 93 हजार 264 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति कर ली गयी है, लक्ष्य के अनुरूप धान अधिप्राप्ति कार्य संपन्न करने हेतु विभाग स्तर से लगातार समीक्षा की जा रही है । धान अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित अवधि में लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने की संभावना की स्थिति में राज्य सरकार अधिप्राप्ति अवधि विस्तारित करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किये जाने पर विचार करेगी ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया है, यह हम जरूर कह रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को पत्रांक के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि एफ0आर0के0 राइस मिलर को मिले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि राज्य के द्वारा जो भी एफ0आर0के0 का आवंटन है, दो एजेंसी को चयनित किया गया है, उसकी उपलब्धता के कारण आज राज्य में 10 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन हुआ है । मात्र अभी माननीय मंत्री जी ने कहा....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न कीजिए ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि धान की खरीददारी में खासकर रोहतास जिले में 3 लाख 19 हजार मीट्रिक टन का सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारण किया गया है, हम सदन के माध्यम से यह मांग करेंगे कि मात्र अभी खरीददारी का समय 25 फरवरी तक है, एफ0आर0के0 नहीं मिलने की वजह से राइस मिल चावल नहीं गिरा पा रहे हैं जिससे किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है, किसान का भुगतान इस समय जो समय चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय, यह शादी का समय है और बाकी किसान का जो धान गिराये हैं उनका पेमेंट भी नहीं हुआ है.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदया ने विस्तार से जवाब दिया है, सारी बातें उनके जवाब में सन्निहित हैं, ये केन्द्र सरकार से चिट्ठी बढ़ाने का रिक्वेस्ट भी कर रही हैं, सारा जवाब माननीय मंत्री महोदया ने आपको दे दिया है और समय भी अब बीतने को चला है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमलोग एक चीज कहेंगे कि धान का कटोरा कहे जाने वाले रोहतास जिला में पत्रांक भारत सरकार को दिया गया है, पत्र दिया गया है लेकिन 25 फरवरी की समय सीमा के अंदर आज हम जो सदन के माध्यम से 10 फरवरी को बोल रहे हैं, 15 दिन शेष रह गया है, क्या 15

दिन में 10 लाख किसान का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, एफ0आर0के0 जब तक सुगमता से उपलब्ध नहीं होगा तो किसान का पेमेंट नहीं होगा चावल नहीं गिरने की वजह से तो माननीय मंत्री जी से....

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ।

श्रीमती लेशी सिंह, मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विस्तार से अपने वक्तव्य में बताया है कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, वह हमारी चिंता है और सरकार की भी चिंता है । इनका कहना है कि एफ0आर0के0 की वजह से अधिप्राप्ति में विलंब हो रहा है यह बात सही है लेकिन यह भारत सरकार को ही जांच करनी है, पिछले खरीफ विपणन मौसम में निगम के द्वारा होता था तो सुलभता होती थी तो ये हमलोग लगातार पत्राचार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से कर रहे हैं ताकि एफ0आर0के0 सुलभता से मिले और अधिप्राप्ति का जो चक्र है वह अच्छे से हो । इसमें भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं और जो लक्ष्य बढ़ाने का है और फिर एफ0आर0के0 का और अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ाने का भी तो हमलोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं और सारी प्रक्रिया भी कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदया ने बड़े ही स्पष्ट ढंग से जवाब दिया है ।

आज की शेष ध्यानाकर्षण सूचनाएं पुनः दूसरे दिनों में सूचीबद्ध रहेंगी ।

शेष शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ माना जाता है और सदन की सहमति से संबंधित विभाग को लिखित उत्तर के लिए भेजा जाता है।

<u>शेष शून्यकाल की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया</u>

श्री मनोज विश्वास : उपाध्यक्ष महोदय, फारबिसगंज क्षेत्र के सिमराहा में संचालित मांस फैक्ट्री से दुर्गंध, गंदगी एवं प्रदूषण फैल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसे तत्काल बंद कराने हेतु कार्रवाई करेगी ।

श्रीमती अनीता : उपाध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत मटिहानी अंचल के ग्राम–दरियापुर में पुस्तों से रह रहे भूमिहीन धानुक समाज के गरीबों का घर एवं सरकारी विद्यालय को तोड़ा जा रहा है । पटना उच्च न्यायालय तोड़ने से रोक लगाई है। अतः तोड़–फोड़ रोकने एवं वासिन्दों को 3–3 डिसमिल जमीन देने की मांग करती हूं ।

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत अशोक–चक्र से सम्मानित शहीद ज्योति प्रकाश निराला के सम्मान में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा काराकाट के बडीलाडीह में प्राथमिक विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करते हुए

शहीद के नाम पर नामकरण करने की घोषणा की गयी थी । मैं उक्त विद्यालय को उत्क्रमित सहित नामाकरण की मांग करता हूं ।

श्रीमती सावित्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, जमुई जिलान्तर्गत चकाई एवं सोनो प्रखण्ड के आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रति माह तीन हजार रुपया वसूली करने के कारण बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु मांग करती हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के रफीगंज–ओबरा पथ (भाया–बराही बाजार) बौर पंचायत के पास का पुल जो एक महीने पूर्व ध्वस्त हो चुका है, आवागमन बाधित है, जनहित में उक्त स्थान पर एक बड़ा पुल का अविलम्ब निर्माण करावें ।

श्री विनय बिहारी : उपाध्यक्ष महोदय, लौरिया प्रखंड अंचल अंतर्गत बसंतपुर में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क के साथ नाला नहीं होने के चलते यह सड़क सुगम नहीं है । ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस सड़क का चौड़ीकरण, नाला व पुल का निर्माण कराने हेतु सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्णिया गुलाबबाग मेला ग्राउंड कृषि विभाग की सात एकड़ जमीन पर किसान हित में कृषि बाजार एवं टूरिज्म के बढ़ावा हेतु क्रॉप एरिया फुड एरिया प्लांट एरिया कैफेटेरिया विरासत गलियारा मिनी ऑडिटोरियम प्ले ग्राउंड ग्रीन एरिया जैसी आधुनिक सुविधा हेतु एग्रो मॉडल पार्क बनाने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री बशिष्ठ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अन्तर्गत सदर अस्पताल सासाराम, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करगहर, कोचस सहित अन्य स्वास्थ्य केन्द्र पर रेबीज वैक्सीन नहीं होने के कारण बंदर एवं कुत्ता के काटने पर मरीज को वैक्सीन नहीं लग रहा है । सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर वैक्सीन उपलब्ध करावें ।

श्री मिथिलेश तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, छपरा से गोपालगंज की लम्बी दूरी एवं प्रशासनिक कार्यों में छात्र/छात्राओं, अभिभावकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का एक विस्तारित कार्यालय गोपालगंज जिला मुख्यालय में खोला जाए । साथ ही, गोपालगंज में रसायनशास्त्र, भौतिकीशास्त्र, भूगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं मनोविज्ञान की पढ़ाई प्रारम्भ किया जाए ।

श्रीमती छोटी कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम की बदहाल सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहती हूं । सफाई बजट 40 लाख से बढ़ाकर 1.40 करोड़ किए जाने के बावजूद शहर में गंदगी व्याप्त है । काली सूची में दर्ज एजेंसी का चयन किया गया है । वित्तीय अनियमितताओं की आशंका है । उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी प्रसाद गौतम : उपाध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत नगर पंचायत चेनारी में अंचलाधिकारी चेनारी द्वारा बस स्टैंड हेतु भूमि चयन न करने के चलते बस

स्टैंड का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है । अंचलाधिकारी चेनारी पर कार्रवाई करते हुए अविलंब उक्त बस स्टैंड निर्माण हेतु भूमि चयन की मांग करता हूं ।

प्रो0 विनय कुमार चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित पथ नारबांध से मुर्तुजापुर सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मतिकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–14 / सुरज / 10.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 66 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 63 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 18 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)	– 14 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 04 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	– 04 मिनट
राष्ट्रीय लोक मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰एल॰)(एल॰)	– 01 मिनट
सी0पी0आई0 (एम॰)	– 01 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	– 01 मिनट
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी	– 01 मिनट

.....

कुल = 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

डॉ0 दिलीप जायसवाल, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये 8260,16,83,000 / – (आठ हजार दो सौ साठ करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार) रुपये से अनाधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो0 कमरूल होदा, श्री अखतरूल ईमान एवं श्री सतीश कुमार सिंह यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं । ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार का प्रस्ताव प्रथम है अतएव माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव मूव करता हूं और सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है और केन्द्र की सरकार, बिहार की सरकार को पैसे नहीं दे रही है और बड़ी–बड़ी योजनाएं लंबित है । इसलिये मैं उसके लिये प्रस्ताव मूव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटाई जाए । ''

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राम अपना पक्ष रखें ।

श्री सुरेन्द्र राम : धन्यवाद सम्मानित अध्यक्ष जी । आज मैं इस सदन में कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं और इसके लिये मैं गरखा विधान सभा के सम्मानित जनता मालिक को दिल से आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही, गरीबों के मसीहा, जन–जन के नेता, दलितों के मसीहा, महान समाजवादी नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भी मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही, गरीबों की बात करने वाले, रोजगार की बात करने वाले, नौकरी माइंड ऑफ बिहार, नौजवानों के नायक, बेराजगारों के हमदर्द, दलितों के मसीहा, आदरणीय सम्मानीय प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू को मैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री सुरेन्द्र राम : दिल से धन्यवाद देता हूं । हंसिये आपको तो हंसना चाहिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें । गायत्री जी बैठे–बैठे मत बोलिये ।

श्री सुरेन्द्र राम : आपको अपनी सरकार पर जो पैसा तो लेती है लेकिन पैसे का सदुपयोग नहीं करती है और यह बजट का पैसा बिचौलिये, ठीकेदार और सरकार की मिलीभगत से जनता के पैसे को उड़ा लिया जाता है । यह दुर्भाग्य की बात है। आपको हंसना चाहिये तो अपनी सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री और सामने बैठे दो–दो उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री पर हंसना चाहिये कि जनता में जो वादे यहां करके आते हैं, उस जनता के वादों का सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं । इसलिये आपको हंसना चाहिये चूंकि जिम्मेवारी जिस विधान सभा की जनता माननीय सदस्य को दिया है, वह सदस्य आपसे सवाल करती है और उस सवाल के एवज में आप चुप्पी डाल लेते हैं आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है । चूंकि यह सरकार आपको जवाब देने लायक छोड़ी भी नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय मैं अपने यहां के रोड की

अवस्था को देखा है । यह रोड पथ निर्माण विभाग के द्वारा बनायी गयी है लेकिन जिला प्रशासन और सरकार के आदेश पर जो पथ निर्माण विभाग की सड़के हैं उस पर रोक लगा दिया गया है । राज्य सरकार रोड टैक्स लेती है लेकिन उस पर भारी वाहन चलने पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया जाता है जैसे कि मेरे यहां मानपुर से लेकर गरखा वाली रोड, दिघवारा से लेकर जो अमनौर जाने वाली रोड है, वह रोड है और चिरान से लेकर गरखा जाने वाली रोड है। ये सारे पथ निर्माण विभाग के रोड हैं और इस पर जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से रोक लगा दी जाती है । अब बताइये महोदय सरकार को हमारे ट्रक मालिकों ने टैक्स दिया है और टैक्स के एवज में उस रोड पर चलने पर भी प्रतिबंध है । कारण है महोदय कि ये जो रोड बनाये जाते हैं, ये गुणवत्तापूर्ण रोड बनते तो उस पर रोक नहीं लगाया जाता, ये टूटने के डर से छूई–मुई जो रोड बने हुये हैं, छूने से वह मर जायेंगे । इसके डर से जिला प्रशासन द्वारा उस रोड पर चलने पर रोक लगा दिया जाता है । केन्द्र की, राज्य की सरकार दोनों मिला लीजियेगा तो यह ना–नी शब्द है । ना से नरेन्द्र और नी से नीतीश । ये दोनों फिनिश है, दोनों काम की सरकार नहीं है महोदय...

(व्यवधान)

सरकार आने दीजिये, सरकार बदलने दीजिये । क्या–क्या आपने...

(व्यवधान)

आप बोल रहे हैं ट्रंप के सवालों का जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री दे नहीं पा रहे हैं, मजबूरी में उनको झुकना पड़ा अमेरिका से...

अध्यक्ष : आप पथ निर्माण पर बोलिये । पथ निर्माण पर बोला जाए ।

श्री सुरेन्द्र राम : इसलिये बोल रहे हैं कि एन0डी0ए0 वाले अभी चुप ही रहें तो जनहित में अच्छा है । महोदय, स्थिति गंभीर है । आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी बजट है । हमने उस दिन माननीय मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर यह कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप यह बताइये कि आपकी 21 साल की सरकार है । 21 साल की सरकार में क्या अनुसूचित जाति के चमार टोला में, पासवान टोला में, धोबी टोला में, पासी टोला में, ये सारे टोले जो हैं मुसहर भाई के टोला में, हलखोर भाई के टोला में, डोम भाई के टोला में, नट भाई के टोला में, आदिवासी समाज के टोला में कितनी सड़कें आप बनवाये हैं ? आप तो यह बात असत्य बोलते हैं कि बिहार के किसी भी कोना से चार से पांच घंटों में पटना पहुंचा जा सकता है । लेकिन मैं इस बात को बोलता हूं कि 21 साल की यह सरकार अब तक दलित टोला में पहुंच नहीं पाया है । इसलिये इससे बड़ी कोई...

(व्यवधान)

क्या कहा जा सकता है ऐसी सरकार को । महोदय, आज भी दलितों के गांवों में, अतिपिछड़ा के गांव में कंधा पर लाश उठाने को लोग मजबूर हैं ।

चूंकि चार से छः फीट चौड़ी गली भी नहीं है । खटिया पर मरीज या लाश को उठाने के लिये भी छः फीट चौड़ी कम से कम गली होना चाहिये ।

...क्रमशः....

टर्न–15 / धिरेन्द्र / 10.02.2026

...क्रमशः....

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, दुर्भाग्य की बात है, इस सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है । बड़ा–बड़ा ढकोसला परोसने वाले सामने खड़े हुए सरकार के लोगों से मेरा सवाल है कि कब वह चमार भाइयों के गाँव में, पासी–पासवान भाइयों के गाँव में, नट के गाँव में, धोबी भाइयों के गाँव में जो आज तक वंचित टोलों में आप सड़क बनाइयेगा । बजट तो मांग करते हैं लेकिन बजट का आप 50–60 परसेंट ही खर्च कर पाते हैं । क्यों खर्च कर पाते हैं चूंकि यहाँ के अफसरशाही और माननीय मंत्री में वह ऊर्जा नहीं है कि जो जनता की ली हुई बजट को भी सदुपयोग सही–सही नहीं कर पाते हैं । महोदय, आप यह बताइये कि आज अनुसूचित जाति, जनजाति की यह स्थिति है ।

(व्यवधान)

आप भी महागठबंधन की सरकार में थे । हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी और महागठबंधन की सरकार में जातिगत जनगणना कराया गया । हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू के प्रयास से जातिगत गणना कराया गया, जातिगत गणना कराने के बाद में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या लगभग 20 प्रतिशत थी, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या थी उसके मुताबिक हमारी महागठबंधन की सरकार ने आरक्षण को बढ़ाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का जो दायरा था 16 प्रतिशत, उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या थी उसे 01 से बढ़ाकर 02 प्रतिशत कर दिया गया और राज्य सरकार से पास करा कर केन्द्र सरकार को भेजा गया और यही एन॰डी॰ए॰ वाले लोग हैं, यही एन॰डी॰ए॰ वाले बिहार के लोग हैं जो एक बार भी केन्द्र सरकार पर आवाज नहीं उठायी कि जो बढ़ी हुई आरक्षण को नौवीं अनुसूचि में यदि केन्द्र सरकार शामिल कर ली होती तो आज यहां जो बहाली 100 होती तो उसमें हमारे लोगों का आरक्षित सीट 20 होता लेकिन ये एन॰डी॰ए॰ वाले लोग अनुसूचित जाति से वोट तो लेते हैं लेकिन उनके कामों की जब बात आती है तो वे चुप्पी साध लेते हैं, यह कितनी शर्म की बात है। एक हमारे हनुमान हैं, हनुमान की कृपा से वहां राम का शासन चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं ये हनुमान दूसरी तरफ, उस तरफ वाले उनको राम समझ गए हैं जिनको, जो राम के विरोधी हैं उन्हीं को राम समझ बैठे हैं । अनुसूचित जाति के यदि लोग हैं, ये यदि केन्द्र की सरकार पर दवाब बनाये होते तो आज हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20 प्रतिशत और 02 प्रतिशत होता तो हम यह देख रहे हैं कि यह जो सरकार है अनुसूचित जाति

के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ, उनके वोट को लेने के लिए, अब यह बताइये न कि हमारे चाचा तो दलित को महादलित बनायें, हम महादलित के वही बेटे हैं सुरेन्द्र राम जो आज इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहा है कि ये 19 साल तो हो गए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, आपने दलित को महादलित बांटा और दलित और महादलित के लिए कोई योजना नहीं चलायी....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार । माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री सुरेन्द्र राम : महोदय, चाचा, ये सवाल पूछ रहा है सुरेन्द्र राम महादलित का बेटा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइये, हो गया, आपका समय पूरा हो गया । माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार जी ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के 8,260 करोड़ 16 लाख 83 हजार रुपये की मांग के बजट के समर्थन में बोलने के लिए आपने जो समय दिया, अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय पथ निर्माण विभाग के मंत्री और क्षेत्र के समस्त जनता मालिकों का अभिवादन है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट पर बोलने से पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना अति आवश्यक है । अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी न होते तो देश के अंदर 04 लेन कॉरिडोर नहीं आता, गाँव के अंदर पक्की सड़क और पिच जो स्टेट हाइवे, नेशनल हाइवे, जितनी देशभर में सड़कें चमक रही हैं इसका कोई एक मात्र देन है तो हमारे श्रद्धेय अटल बिजारी वाजपेयी जी हैं, जिनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हें याद करना आवश्यक है । महोदय, देश की आजादी हुई, आजादी के बाद किसी सरकार ने साहस नहीं की कि गांव के गरीब और दलित और समाज के विभिन्न वर्गों के अंदर रोड का निर्माण हो और एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि गाँव के लोग शहर की ओर कूच कर गए, चूंकि गाँव से आना–जाना कठिन था, गाँव में बिजली नहीं थी, गाँव में सड़क नहीं थी, गाँव में पानी नहीं था, हर साधन संपन्न आदमी अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए ब्लॉक में, जिला में और राज्य के मुख्यालय में और केन्द्र दिल्ली तक अपने बाल–बच्चों के भविष्य की तलाश में भटकते रहे और वहीं तलाश करते रहें लेकिन धन्यवाद है महोदय कि जब एन॰डी॰ए॰ की सरकार बनी, मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, उन्होंने देश के सामने नीति लायी और उस नीति के तहत जो पेट्रोलियम पदार्थ पर टैक्स लगाया और उसी टैक्स से

आज पूरे देश के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और वह कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब उसके बाद हमारे नरेन्द्र भाई मोदी हुए, इन्होंने भी स्टेट जो हाइवे है उसको 04 लेन, 06 लेन में तब्दील करने के लिए राज्य सरकार को पैकेज दिया और महोदय, यह पैकेज 33 हजार 446 करोड़ का 52 सड़कों का है और महोदय, वाराणसी से कोलकत्ता, गोरखपुर से सिलीगुड़ी ये 23 हजार 434 करोड़ की लागत से 416 किलोमीटर, हमलोगों के बिहार से अपने चम्पारण क्षेत्र से होकर गुजर रहा है । इसी प्रकार गोरखपुर–सिलीगुड़ी के बाद वाराणसी–कोलकत्ता, रक्सौल–हल्दिया, पटना–पूर्णियां, सीतामढ़ी–अयोध्या श्रीराम पथ और भारतमाला रोड, इंडो–नेपाल रोड । महोदय, हर जगह जाने–आने के लिए जो सड़कों का जाल बिछा, इसी जाल का परिणाम है कि आज बिहार के अंदर बड़े–बड़े उद्योग घराने आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं और उद्योग लगाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं और सरकार को धन्यवाद है, अपने माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को, जो जमीन देकर और उद्योगों का जाल बिछाने का काम आज बिहार सरकार कर रही है, इसके लिए कोटि–कोटि अभिवादन है । महोदय, आज की जो स्थिति है, एक जमाना था, मैं वर्ष 2005 में विधायक बना, जनवरी–फरवरी में बना और नवम्बर में बना और लगातार अभी बना हुआ हूँ । महोदय, जब 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लखौरा, महोदय, मोतिहारी गए हैं, मधुबनी घाट, पकड़ीदयाल, ये सब 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाने में घंटों लग जाते थे और चार चक्का पर नहीं जाते थे बाईक पर जाते थे, नहीं तो साईकिल पर जाते थे, इस स्थिति में बिहार खड़ा था । वर्ष 2005 के सभी साथी हैं अपने दिल पर हाथ रख कर देख लीजिये, सोच लीजिये, दर्पण में थोड़ा अपना चेहरा देख लीजिये कि वर्ष 2005 के पहले कहाँ थे ?

....क्रमशः....

टर्न–16 / अंजली / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, वर्ष 2005 के पहले जो बजट था समझिए कि 183 करोड़ का बजट था और महोदय, इसी सदन के माननीय मंत्री श्रीमान् इलियास हुसैन, यही पथ निर्माण विभाग के कारण क्या नहीं हुआ ? शर्मसार हो गया पथ निर्माण विभाग, शर्मसार हो गया पूरे देश में पर एक मैसेज बिहार छोड़ दिया कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री अलकतरा पी गए, अलकतरा पी गए । आज कोई माई का लाल बिहार सरकार के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, कोई पथ निर्माण विभाग के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता, कोई भी हमारे अधिकारी, कोई भी हमारे सत्ता और सरकारी या गैर सरकारी लोग पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता और यही आज बोल रहे हैं, कहां थे, कहां पहुंचा बिहार ? महोदय,

मोतिहारी से पटना आना कठिन था, 5 घंटे, 6 घंटे, आप तो हमलोग के प्रभारी मंत्री रहे हैं, गांव को जोड़ने वाला पुल आपकी देन है, कितना पुल दिये, यह स्थिति थी कि दो दिल को मिलने के लिए 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर फेरा करना पड़ता था । महोदय, धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी को, बिहार सरकार को कि दिल की दूरी को, दिल की दूरी को करीब कर दिये । क्या–क्या लोग नहीं कहते थे, गड्ढे में सड़क कि सड़क में गड्ढा, कितने–कितने लोगों का नाम रखते थे, जब बाहर की गाड़ी बिहार में आती थी तो लोग कहते थे कि आ गए बिहार, यह हमलोगों का परिचय था और जब दिल्ली चले जाइए, दूसरे पार्क में चले जाइए, तो कह दीजिए कि बिहारी हैं, तो ओ वही बिहार, गड्ढा वाला बिहार यह कहते थे लोग, यह हमारा परिचय था । महोदय, इस परिचय को आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एन0डी0ए0 सरकार ने उठाकर इस मुकाम पर पहुंचाया है, अपने–आप ये लोग तरस रहे हैं, कहां थे, कहां पहुंचे हैं, अभी इन्हें महसूस नहीं हो रहा है, यह दुर्भाग्य है इनके लिए । महाशय, यह दुर्भाग्य है । महोदय, आज मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जैसे 4 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है । मैं चंपारण मुख्यालय, मोतिहारी पूर्वी चंपारण की तरफ से आपसे आग्रह कर रहा हूं। महोदय, मोतिहारी मुख्यालय से जोड़ने वाला इंडो–नेपाल रोड जो स्टेट हाइवे से जुड़ा है, उसको भी फोर लेन में तब्दील कीजिए । मोतिहारी मुख्यालय से जोड़ने वाला पकड़ीदयाल का रामजानकी पथ उसको भी मुख्यालय से जोड़ने का काम कीजिए । मोतिहारी शहर से जुड़ा हुआ ढांका का रोड, जो ढांका होकर भारतमाला रोड से जुड़ता है तो जो ब्रांच स्टेट हाइवे है उसको भी मूल एन0एच0 से जोड़ने का काम किया जाए ताकि जो जाम की समस्या है उसका समाधान हो जाय और ऐसे भी अभी हमलोग का बहुत काम करना है तो मैं यह सुझाव आपको देना चाहता हूं । महोदय, इसी प्रकार जो सड़कें शहरों के अंदर हैं, सड़क बन गए हैं, लेकिन उसका अतिक्रमण भी हो रहा है तो वहां पेवर ब्लॉक बिछाया जाए, मोतिहारी शहर में बिछ रहा है लेकिन मुहल्लों में नहीं बिछ रहा है...

(व्यवधान)

सुझाव बता रहे हैं, आप सबों का सुझाव ।

अध्यक्ष : सुझाव बता रहे हैं, आप बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, तो सड़क का अतिक्रमण नहीं होगी, सड़क की पैमाइश कराकर और वहां पिलर लगाकर और जहां तक पी0डब्लू0डी0 की प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित करके और उसको पेवर ब्लॉक लगाया जाय ताकि भविष्य में उस सड़क का चौड़ीकरण भी करने में सुविधा हो, यह सुझाव मैं देना चाहता हूं ।

महोदय, एक्सप्रेस–वे हाइवे जो आपने बनाया है और इस सरकार ने जो टू–लेन भारत सरकार के बारे में कह रहे थे, भारत सरकार ने जो चकिया

भिट्टा मोड़ रामजानकी पथ के लिए 146 किलोमीटर रोड के लिए 2300 करोड़ रुपया दिया, बेतिया–बगहा 59 किलोमीटर रोड के लिए 4300 करोड़ रुपया, बरियारपुर–विष्णपुर रोड के लिए 3400 करोड़ रुपया, अरवल–बिहार शरीफ 89 किलोमीटर रोड के लिए 2900 करोड़ रुपया, दरभंगा–जयनगर के लिए 38 किलोमीटर रोड के लिए 1350 करोड़ रुपया, ढाका मोड़ 27 किलोमीटर रोड के लिए 1055 करोड़ रुपया, विक्रमशिला एक्सप्रेस–वे के लिए 233 करोड़, नौबतपुर के लिए 38 करोड़, महोदय, भारत सरकार ने जो रुपया दिया है और आज पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी जो काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि गड्ढा बताओ और इनाम पाओ...

(व्यवधान)

आप गड्ढा खोजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति–शांति । शांति बनाए रखिए । संजब बाबू, सुनिये ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ था, देश में पहले हमारे पथ निर्माण मंत्री हैं, जिन्होंने ऐलान किया है गड्ढा बताओ, इनाम पाओ । इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को दिल से बधाई देता हूं । महोदय, मोतिहारी नगर मुख्यालय में, अब तो नगर निगम क्षेत्र हो गया है, आप तो देख रहे हैं, लेकिन नगर निगम में मोतिहारी है, 8 पंचायत जुड़ा है, तो पंचायत में नगर वाली जो सुविधा है, वह अभी नहीं पहुंचा है । पंचायत की जो सड़के हैं वह आर0डब्लू0डी0 के हैं, तो मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि मोतिहारी नगर निगम क्षेत्र में जो आपके पी0डब्लू0डी0 पैमाइश की जो सड़कें हैं, यानी इतना लंबा चौड़ा, उसको अधिग्रहित करके, भविष्य के लिए, उसको पैमाइश करके अधिग्रहित कर लीजिए ताकि भविष्य में जैसे–जैसे फंड हो वैसे–वैसे उसका डेवलपमेंट हो, भविष्य का मोतिहारी कमिशनरी है, आने वाले समय में मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मोतिहारी शहर कृषि का तीर्थ स्थल है, महोदय, इसलिए मैं आग्रह करूंगा क्षेत्र की जनता की तरफ से कि उसको पिपराकोठी चौक से ढेकहा, मधुबनी **घाट, टिकुलियाहरा,** भरौलिया, भविष्य का कमिशनरी है...

(व्यवधान)

लंबा समय नहीं लगने वाला है भाई वीरेंद्र, आप इसी सदन में रहिएगा हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

नहीं, मैं कह रहा हूं, आप सुनिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू, आप बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार : पी0डब्लू0डी0 फतुहां लखौरा, लखौरा–नौरंगिया,

(व्यवधान)

अध्यक्ष : भाई वीरेंद्र जी, बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री प्रमोद कुमार : झिटकियां, फुलवार, ये पी0डब्लू0डी0, आर0डब्लू0डी0 की सड़क है, जो पी0डब्लू0डी0 को जोड़ता है, आपके अधिकारी नोट कर रहे होंगे, लखौरा से सुगौली स्टेशन जाना हो, तो समझिए कि 20 किलोमीटर की दूरी एकदम नजदीक हो जाएगी, उधर से पी0डब्लू0डी0 है, इधर पी0डब्लू0डी0 है, तो वैसे भी पी0डब्लू0डी0 का संकल्प है कि एक छोर पी0डब्लू0डी0 हो, दूसरा छोर पी0डब्लू0डी0 हो, बीच का जो गैप की सड़क है उसको जोड़ लेना चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि इसको भी जोड़ लिया जाय और मोतिहारी शहर में लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा शहर के अंदर पी0डब्लू0डी0 सड़क है ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो रहा है । आप संक्षिप्त कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार : लेकिन सड़क में ड्रेन का अभाव है तो थोड़ा उसमें ड्रेन का निर्माण करा देते तो अच्छा होता महोदय और इस प्रकार...

अध्यक्ष : कृपया आप बैठ जायं । आपका समय समाप्त हुआ, माननीय सदस्य ।

श्री प्रमोद कुमार : एक मिनट अध्यक्ष महोदय । मोतिहारी शहर में मोती झील है और आप देख रहे हैं, वर्षों से ओवर–फ्लाई पुल का निर्माण हो, पुल निर्माण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब विकास यात्रा में गए थे उसी समय बताकर आए थे कि ओवर फ्लाई पुल बन जाएगा, तो आग्रह करूंगा मंत्री महोदय से कि कम से कम आने वाला वित्तीय वर्ष में एक ओवर फ्लाई पुल दोनों एन0एच0 को जोड़ने वाला...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया । कृपया आप बैठ जाइए । माननीय सदस्या, श्रीमती मनोरमा देवी ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, आपने जो समय दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मनोरमा देवी ।

टर्न–17 / पुलकित / 10.02.2026

श्रीमती मनोरमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको कोटि सह धन्यवाद देती हूँ । साथ ही, सदन के नेता माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी एवं हमारे दल के सचेतक श्री श्रवण बाबू को भी मैं धन्यवाद देती हूँ । मैं बेलागंज की महान जनता को भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सदन तक पहुंचाने का आशीर्वाद दिया ।

महोदय, आज मैं पथ निर्माण, उद्योग विभाग एवं पंचायती राज विभाग पर कटौती प्रस्ताव के विरोध में तथा सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ । हमारी सरकार ने पथ निर्माण में, उद्योग क्षेत्र में आमूल–चूल परिवर्तन

किया है। महोदय, हमारी एनडीए सरकार आधारभूत संरचना विकास हेतु बड़े पैमाने पर पथों का चौड़ीकरण एवं पुलों के निर्माण का कार्य कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 7404 करोड़ 79 लाख का बजट आवंटन किया गया है ।

महोदय, विगत एक वर्ष में लगभग 38732 करोड़ 54 लाख रुपये में कुल 266 पथ एवं पुल परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 137 परियोजना प्रगति यात्रा के तहत तथा 129 अन्य परियोजना सम्मिलित है। राज्य में पांच एक्सप्रेस–वे निर्माण की योजना है।

महोदय, 60 मीटर से अधिक लम्बाई के 624 पुलों का संधारण एवं प्रबंधन बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा किया जाएगा।

महोदय, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 2005–06 से अब तक 2063 योजनाओं का गुणवत्ता सहित निर्माण किया गया है। जिसमें हमारे मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत लगभग 1150 परियोजना को पूर्ण किया गया है। वर्तमान में 86 परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त में 9 मेगा परियोजना सहित 27 आर0ओ0बी0 भी शामिल है।

महोदय, बिहार राज्य रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जे0पी0 गंगा पथ, कुल लम्बाई 20.5 किलोमीटर, राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर शहीद कारगिल चौक से अशोक राजपथ, मीठापुर–महुली एलिवेटेड पथ परियोजना, भूपतीपुर से पुनपुन तक, कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल के पटना से राघोपुर अंश का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, औटा–सिमरिया के बीच गंगा नदी पर छह लेन का पुल, बख्तियारपुर–मोकामा चार लेन परियोजना, जे0पी0 सेतु समानांतर गंगा नदी पर छह लेन पुल प्रगति पर, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर चार लाइन पुल प्रगति पर, आमस–दरभंगा ग्रीन फील्ड परियोजना प्रगति पर, दानापुर–बिहटा एलिवेटेड प्रगति पर।

महोदय, हमारी एन0डी0ए0 सरकार एन0एच0 82 गया–मानपुर–हिसुआ, राजगीर–नालंदा–बिहारशरीफ खंड कुल लम्बाई 93.935 किलोमीटर के चार लाइनिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सुगम, सुरक्षित, बाधा रहित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के जाम प्रवण क्षेत्रों में बाईपास पथ, एलिवेटेड पथ निर्माण के साथ–साथ रेल समपार पर आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु योजना स्वीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार के लगातार प्रयास के फलस्वरूप राज्य के विभिन्न पथों पर अवस्थित 222 रेलवे फाटकों के स्थान पर रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आर0ओ0बी0 निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है।

महोदय, राज्य सरकार सभी सिंगल लेन विभागीय पथों को आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से दो लाइन में उन्नयन की योजना पर कार्य कर रही है।

महोदय, एन0डी0ए0 सरकार हमारे उद्योग विभाग में भी बहुत आगे काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 3337 करोड़ 64 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की घोषणा से राज्य सरकार में एक नया औद्योगिक वातावरण निर्मित हुआ है। राज्य में 767 कारखाने लगेंगे जिसमें 13 हजार करोड़ से अधिक निवेश होगा।

महोदय, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। जिसमें महिलाएं, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभुक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 209 करोड़ 88 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6,225 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 2060 आवेदक नियोजित कराया गया है।

महोदय, स्टार्टअप नीति, 2022 के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक का सीड फंड एवं 15 लाख रुपये तक का पोस्ट सीड फंड का राशि देने का प्रावधान है। अब तक महिलाएं द्वारा स्थापित 235 स्टार्टअप सहित कुल 1597 स्टार्टअप को चयनित किया गया है। जिन्हें 84 करोड़ 96 लाख की सहायता राशि वितरित की जा चुकी है।

महोदय, वर्ष 2025–26 में अभी तक 1550 करोड़ राशि भू–अर्जन परियोजना के तहत उपलब्ध कराई गई है एवं वर्ष 2026–27 के भावी कार्य योजना में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न जिलों में 20 हजार 767 एकड़ भूमि को भू–अर्जन का प्रस्ताव है।

महोदय, वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में 767 इकाइयों को आवंटित 1027 एकड़ जमीन में 13,438 करोड़ निवेश से लगभग 75,518 लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई है।

पटना और मुजफ्फरपुर के बाद अब दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर, मुंगेर, गया जी एवं छपरा में भी खादी मॉल का निर्माण किया जाएगा।

अमृतसर–कोलकाता औद्योगिक गलियारा के अंतर्गत गया जी में फेज–2 को विकसित किया जा रहा है। फतुहा, पटना के पास मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिटनेस सिटी की स्थापना की जाएगी। राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एवं प्ले सेंटर का निर्माण कर औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जाएगा।

महोदय, हमारी एन0डी0ए0 सरकार में भी पंचायती राज के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु 10,955 करोड़ 51 लाख का बजट प्रावधान किया है। पंचायती राज भवन का निर्माण राज्य की सभी 8,053 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। पंचायत सरकार भवन दो मंजिला है। इस भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायलय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, पंचायत स्थाई समिति में बैठने के लिए हॉल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कंप्यूटराइजेशन, शौचालय का प्रावधान किया गया है। उक्त पंचायत भवन में पुस्तकालय, डाकघर, बैंक, ऑपरेशनल फाइबर, सुधा मिल्क केंद्र एवं आर0टी0पी0एस0 काउंटर की भी स्थापना की जा रही है।

(क्रमशः)

टर्न–18 / हेमन्त / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती मनोरमा देवी : राज्य के कुल 8053 ग्राम पंचायतों में से अब तक 7943 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें से 2534 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

महोदय, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायत में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। महोदय, हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को पूर्व से देय नियत मासिक भत्ता में वृद्धि कर भुगतान कर रही है।

महोदय, पर्यटन विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2026–27 में 665.71 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के दौरान घोषित कुल 36 योजनाओं जिसकी कुल स्वीकृत राशि 2030.31 करोड़ है, जिसमें 33 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसमें धार्मिक स्थल जैसे पुनौराधाम, महाबोधि केंद्र एवं पर्यटकीय सुविधा आदि शामिल हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत सहरसा जिला के मत्स्यगंधा झील उसके पास पर्यटक की सुविधा के विकास हेतु 98.66 करोड़ की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

महोदय, पर्यटन निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष मेला में श्रद्धालुओं, तीर्थ यात्रियों के लिए पुनपुन एवं गयाजी में पिंडदान करने के लिए सामान्य पैकेज एवं ई–पिंडदान की व्यवस्था का पैकेज उपलब्ध कराया गया है।

महोदय, पर्यटन विभाग का वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए निर्धारित लक्ष्य में गया एवं बोधगया के समग्र विकास हेतु तैयार किये मास्टर प्लान के अनुसार योजना की स्वीकृति प्रदान कर ससमय निर्माण कराना है।

महोदय, माननीय मंत्री, पर्यटन से एक मेरा निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बेलागंज में माता काली का पौराणिक मंदिर है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं। माननीय से मैं पिछले वर्ष भी आग्रह की थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट बनाकर विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उक्त पर अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी। पर्यटन निगम के द्वारा उक्त फाइल को अब तक रोक कर रखा गया है। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि माता काली मंदिर, बेलागंज का जीर्णोद्धार करते हुए पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

महोदय, मैं अंत में बोलना चाहती हूं कि जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, मेरे पास प्रमाण है, मैं प्रमाण के साथ बोल रही हूं, जो विपक्ष के लोग हैं, चुनाव के दौरान मनोरमा देवी को बोला गया कि यह धन की लक्ष्मी है, जो देती है, पॉकेट खुला रखो, पॉकेट में रख लो और फिर आप लालटेन छाप को वोट दो। मैं कहना चाहती हूं विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जमाना बदल गया है, एन0डी0ए0 सरकार का है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जमाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जमाना है। समय के अनुसार आप भी बदल जाइये और अगर आप नहीं बदले तो आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। माननीय तेजस्वी प्रसाद जी, आपका जो वोटर है उनको आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि आप जैसी शिक्षा देंगे, वह क्षेत्र में वैसा ही करते हैं। तो मैं इनको यह सजेशन देती हूं कि इनका जो वोटर है, उनको गलत बात नहीं सिखायें, अच्छी शिक्षा दें कि आने वाले समय में भी आपका वोटर सही जगह पर वोट दे सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ और आभार प्रकट करती हूं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एन0डी0ए0 सरकार को कि मेरे जैसी महिला, मैं यादव समाज से आती हूं और हमारे क्षेत्र की महान जनता, आपकी बदौलत मैं यहां खड़ी हूं। इसलिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करती हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मोहम्मद कमरूल होदा जी। आपका समय चार मिनट है।

मो0 कमरूल होदा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मौका दिया, इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ और इस सदन के माध्यम से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और हमारे सांसद जावेद आजाद साहब और हमारे क्षेत्र की जनता, तमाम लोगों को इस सदन के माध्यम से मुबारकबाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

(व्यवधान)

बिहार के नेता तेजस्वी यादव जी को भी और लालू यादव जी को भी मुबारकबाद देता हूँ। महोदय, बात होती है विकसित बिहार की कि बिहार विकसित है। महोदय, कहाँ पर बिहार विकसित है? आज बिहार विकसित कैसा है, जहाँ पर 70 प्रतिशत बीपीएल परिवार के लोग रहते हैं। बीपीएल परिवार के लोग यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और कहा जाता है कि बिहार विकसित है। मैं किशनगंज से आता हूँ। महोदय, मैं उस जगह से आता हूँ, जहाँ से 400 कि. मी. दूर पटना है और बगल में बंगाल है, एक तरफ नेपाल की सीमा है। जहां पर किसान खेती करके, अधिकतर खेती सीमांचल में मक्का की खेती होती है। पहले लोग पाट की खेती करते थे। पाट की खेती में मुनाफा नहीं होने की वजह से किसान अब बदलकर मक्का की खेती करने लगे हैं। महोदय, वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने की वजह से आज लोगों को, किसानों को मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मक्का की खेती कैश क्रॉप है। मक्का को बेचकर किसान अपने बच्चों की पढ़ाई, अपने घर–परिवार को चलाना, अपने कपड़े–लत्ते खरीदना उसी मक्का की खेती से करता है। मक्का की खेती बेचने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं, जो 1700 रूपये प्रति क्विंटल मात्र वहां पर मिलता है। अगर वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट हो जाए तो, मैं समझता हूं कि सीधे किसानों को 25 से 3000 रूपया मक्का की खेती में मिलेगा। महोदय, किशनगंज और ठाकुरगंज एक ऐसा प्रखंड है जहां पर अनानास की खेती होती है। 1600 एकड़ में अनानास की खेती होती है। अब वहां पर तो ड्रैगन फ्रूट भी पैदा होता है। लोग अनानास की खेती करते हैं और वह किसान अनानास की खेती करके, अनानास पैदा करके 10 रूपया से 15 रूपया में अनानास बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर उसका प्रोसेसिंग प्लांट हो, तो मैं समझता हूं कि सीधे किसानों को फायदा होगा। वह अनानास जब वहां से निकलकर इस शहर पटना में आता है, उसकी कीमत 80 रूपये हो जाती है। वही अनानास जब निकलकर देश के अन्य राज्यों में जाता है, उसकी कीमत 100 रूपये हो जाती है। अगर वही अनानास विदेशों में चला जाता है तो उसकी कीमत 200 रूपये हो जाती है। किसानों को मात्र 10 रूपये और 20 रूपये में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। महोदय, अगर वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट हो जाता है, तो मैं समझता हूं कि उस अनानास की सीधी कीमत, डायरेक्ट किसान को मिलेगी। मैं प्रोसेसिंग प्लांट के लिए मांग करता हूं। महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे जो उद्योग मंत्री हैं और पथ निर्माण मंत्री हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र के ही हैं और विधानसभा क्षेत्र के साथ–साथ हमारे विधानसभा के वोटर भी हैं। माननीय मंत्री महोदय, दिलीप जायसवाल जी हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि वहां पर प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाए और वहां पर मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट हो और ड्रैगन फ्रूट भी वहां पर पैदा होता है। महोदय, दूसरी तरफ यह बात की जाती है, एस0सी0, एस0टी0 की बात की जाती है।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ। कृपया, बैठ जायें।

मो0 कमरूल होदा : महोदय, एस0सी0, एस0टी0 की एक बात है। एक एस0सी0, एस0टी0 की सड़क है, जो बेलवां से लेकर रामगंज को जाती है, मुख्य सड़क है और वहीं से सटा हुआ तीन किलोमीटर भांसीवाड़ी गांव, जो कोलथा पंचायत अंतर्गत पड़ता है। वहां पर 60 से 70 हमारे आदिवासी समाज के परिवार रहते हैं और वहां पर एक नाला भी है।

(क्रमशः)

टर्न–19 / संगीता / 10.02.2026

श्री मोहम्मद कमरूल होदा (क्रमशः) : वहां पर एक नाला भी है उस नाला में चचरी का पुल बना हुआ है, बच्चे उस पुल को पार करके स्कूल जाते हैं...

अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री मोहम्मद कमरूल होदा : कभी भी वहां पर घटनाएं घट सकती हैं इसलिए उस भांसीवारी पुल को...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू तिवारी जी ।

श्री मोहम्मद कमरूल होदा : जो एस0सी0, एस0टी0 समाज के वहां पर परिवार लोग रहते हैं महोदय, मैं अपनी बातों को बस एक बात कहकर समाप्त करूंगा कि

''तू इधर–उधर की न बात कर,
ये बात काफिला किसने लूटा,
मुझे रहजनों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है ।

इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राजू तिवारी जी, आपका 6 मिनट है राजू बाबू ।

श्री राजू तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आज पथ निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में हमको बोलने का आपने मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और साथ–साथ अपने गोविन्दगंज की देवतुल्य जनता बाबा सोमेश्वरनाथ के चरणों में और अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं । अध्यक्ष महोदय, अभी मैं बड़ी देर से सदन में सुन रहा था आज पथ निर्माण विभाग पर, हम यही जानना चाहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, पहले अभी हमारे बहुत सारे सदस्यों ने बताया कि 2005 से पहले क्या–क्या उदाहरण मिलता था । हमारे यशस्वी नेता प्रतिपक्ष के पिताजी उस समय बिहार चला रहे थे, कई–कई तुलनाएं होती थीं यहां तक कि कहा जाता था कि रोड बन जाएगा तो लोगों का एक्सीडेंट होगा, ये ऐसी–ऐसी तुलनाएं और आज हमारे देश के सर्वोच्च सदन के वे सांसद हैं उनका क्या–क्या तुलना दिया जाता था । आज बिहार में आप नेता जो हमारे

विपक्ष के बैठे हैं साथी, हमको लगता है कि सदन में ये कुछ बात और करते हैं और बाहर जाते हैं तो ये एन0डी0ए0 की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है, उसी को अपने क्षेत्र में भुनाने का काम करते हैं । ये है इन लोगों का सच, दोहरा चरित्र । आप आज देख लीजिए गया हो, कहीं भी किशनगंज, खगड़िया, अररिया, इधर आप कैमूर से लेकर गोपालगंज, चंपारण की धरती से मैं आता हूं, चंपारण बाल्मीकिनगर से आने में कितना टाइम लगता है, कोई ऐसा 38 जिला, दो पुलिस जिला है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां से आपको आने में मतलब मैक्सिमम पांच घंटा, पांच घंटे में आप पटना में जा सकते हैं और आज आप सदन में कुछ और बात बोलते हैं, बाहर कुछ और बात बोलते हैं । आप अपने क्षेत्र में काम भी करवाते हैं एन0डी0ए0 सरकार से और फिर सदन में आकर के बोलते हैं और वहां जाते हैं तो बोलते हैं कि मैंने ये रोड बनवा दिया, मैंने वो रोड बनवा दिया। अरे भाई, कभी–कभी सत्य को भी आपलोग तारीफ करिए । आप बात करते हैं मैं अभी बोलूंगा, अभी देखिए सीधे टाइम कम मिला है । हमारे यहां जैसे साहिबगंज, अरेराज, बेतिया, फोर लेन प्रस्तावित है, बन रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो रोड महत्वपूर्ण रोड बन रहा है फोर लेन जबकि रोड बहुत शानदार है । हम मंत्री जी को भी बताना चाहते हैं चूंकि मंत्री जी अभी प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे बिहार में हमलोगों के साथ हमलोग भ्रमण भी किए हैं, देखिए आज वो दिन है कि पथ निर्माण विभाग के मंत्री जो पहले थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आज इस सदन में आगमन हुआ है तो उनके भी कार्यकाल में बहुत शानदार काम हुआ तो मैं यह कहना चाहता हूं, उस रोड में एक हमारे यहां सलेमपुर जो गोपालगंज एन0एच0 है, वहां से सलेमपुर से गोविन्दगंज घाट होते हुए अरेराज से सीधे अगर रक्सौल रोड ये हम 15 से लगातार सदन में हमारे एक साथी हैं मिथिलेश तिवारी, माननीय विधायक हमलोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमको उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कि मंत्री जी के कार्यकाल में ये पुराना बहुत रास्ता है, अंग्रेजों के जमाने से आने–जाने का रास्ता है, अगर वह बन जाएगा तो ये अन्तर्राष्ट्रीय सीधे नेपाल से जुड़ता हुआ यह रोड हो जाएगा और यह बड़ा महत्वपूर्ण काम होगा तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि मेरा सुझाव है आप मेरे क्षेत्र में काम करवाने की कृपा करेंगे मंत्रीजी । हमारे क्षेत्र में जैसे एक बहुत अत्यधिक आवश्यक रोड है पशुपतिनाथ चौक से सरैया, पिपरा, मलाही होते हुए गेहरी होते हुए, वह सीधे इंग्लिश और घिउआढ़ाड़ होते हुए सीधे मोतिहारी और अरेराज मुख्यमार्ग में जुड़ता है । वह रोड आर0डब्लू0डी0 से है, रोड ठीक–ठाक है लेकिन उस रोड में आने जाने वाले लोगों का भारी वाहनों का ज्यादा उधर से आना जाना है इसलिए मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से मंत्री जी को कि इस रोड को भी आप पी0डब्लू0डी0 में, इसको आप ले लीजिए और जिससे ये रोड चौड़ा हो जाएगा और मजबूत

एवं बेहतर बन जाएगा । महोदय, हमारे यहां अरेराज सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, पर्यटन विभाग ने करोड़ों रुपया दिया है उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास हो रहा है । अरेराज मंदिर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शनार्थी, तीर्थयात्री आते हैं, जिससे जाम की समस्या है । अध्यक्ष जी, हम वहां पूजा भी करने हमेशा जाते रहते हैं मंत्री जी तो अध्यक्ष जी, मैं यही आग्रह करूंगा उसपर ओवरब्रिज की आवश्यकता है, इसको भी जरा ध्यान देंगे और उसको बनवाने का काम करेंगे । हमारे नेता श्रद्धेय पद्मभूषण रामविलास पासवान जी की आज याद आ रही है । हमारे संस्थापक बोलते थे कि बगीचा में कई तरह का फूल होता है और सच्चा माली वही है जो सभी फूलों को बारिकी से देख–रेख करके और सभी फूलों को सूखने मुर्झाने मत दें । इसका तात्पर्य यह है कि सरकार एन0डी0ए0 की सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है और...

(व्यवधान)

आप चिन्ता मत करिए चिराग जी की बात जहां कहें आपलोगों को मैं बताना चाहता हूं । 2005 के बाद आप भाग्य मनाइए एक बार नीतीश कुमार जी की कि आपका दल जिन्दा रह गया 2015 में नहीं तो 2010 का स्कोर देख लीजिए और दूसरा चिराग पासवान जी की भी कृपा मनाइए हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर 2020 में अगर अलग नहीं लड़े होते तो यही दशा आपकी उस समय भी होती । यह बात दिमाग में रख लीजिएगा । आज जो दशा आपकी है आपलोग जनता का काम थोड़े न करते हैं अनर्गल बातों में विश्वास रखते हैं, व्यक्तिगत आरोपों में विश्वास रखते हैं आपलोग कभी जनता के बीच में मत जाइए, वह दिन भूल गए, यह 2025 है, 2025 में आप 14 तारीख को आप एकदम गणना के दिन 18 को सरकार बना रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ आपलोगों की...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजू तिवारी : महोदय, मैं बता रहा हूं । महोदय, थोड़ा सा और दो–चार मिनट लेंगे महोदय। अभी ये लोग बात करते हैं महिला सशक्तीकरण का क्षेत्र हो, चाहे कहीं हो हर जगह हमारी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम किया है । अभी 10 हजार रुपये की बात बड़ी इनलोगों को चुभता है, अरे भाई अभी तो 10 हजार रुपया दिये हैं महिला सशक्तीकरण के लिए, हमारी माताओं–बहनों को दिया गया है जिस दिन 2 लाख रुपया चला जाएगा, उस दिन आपलोग कहां रहिएगा, आपलोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा, इसलिए चिन्ता मत करिए...

(व्यवधान)

जनता ने भी दिया है रिजल्ट आपलोगों को तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज देखिए न, आज मरीन ड्राइव इतना बढ़िया बना है कि जिसमें नेता प्रतिपक्ष जाते हैं और वह पथ निर्माण विभाग का ही रोड है...

अध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं ।

श्री राजू तिवारी : वहां कितना सुंदर रील बना था, वो भूल गए । अभी आदरणीय लालू ली जब भी कभी, रोज हमको लगता है कि मरिन ड्राइव घूमने चलें । ये डेवलपमेंट है, आपलोग दिल से कभी–कभी बोला करिए...

अध्यक्ष : मोहम्मद मुर्शिद आलम जी ।

श्री राजू तिवारी : और अच्छे कामों को बताया करिए । महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान के मांग के पक्ष में खड़ा हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : मोहम्मद मुर्शिद आलम जी, आपका समय 4 मिनट है ।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस सदन में पंचायती राज मंत्री और सरकार से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पंचायती राज में आप 3 हजार रुपये कबीर अन्त्येष्टि के रूप में देते हैं । इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक घोषणा था कि मुखिया के जेब में 15 सौ रुपया रहेगा जिस वक्त कोई आदमी मरेगा, उसको अंतिम संस्कार के लिए या कफन–दफन के लिए दे दिया जाएगा । इसमें ऐसा किया गया कि 3 हजार राशि तो बढ़ा दी गई लेकिन बी0पी0एल0 के माध्यम से देना चाहते हैं और ऑनलाइन देना चाहते हैं, उसके बाद भी कहता है कि मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वह भी दीजिए तो सरकार एक मुखिया पर जनकल्याणकारी योजना पर लाखों और करोड़ों रुपया पर भरोसा करती है लेकिन 3 हजार उसको सचिव के माध्यम से नहीं देना चाहती है ।

(क्रमशः)

टर्न–20 / यानपति / 10.02.2026

(क्रमशः)

मो0 मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव होगा कि इसको 3 हजार रुपये आप जो बी0पी0एल0 खोजते हैं नहीं, पी0एच0एच0 जो आपका एक माध्यम है राशन देने का, उसके माध्यम से तुरंत दे दीजिए क्योंकि मरने के बाद मुखिया के दरवाजे पहुंच जाता है । अब व्यवस्था है ऑनलाईन का, मृत्यु प्रमाण पत्र का, मुखिया जी को देना पड़ता है । उसके खाते में पैसा चला जाता है, यह विडंबना है और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कन्या विवाह योजना तो कन्या विवाह योजना में आप पांच हजार रुपये देते हैं लेकिन करोड़ों रुपये की राशि पंचायत पर भरोसा करते हैं, ब्लॉक स्तर पर देने की व्यवस्था करते हैं वह ससमय नहीं मिल पाता है ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

डसके बारे में भी हम यह कहना चाहते हैं कि आप पंचायत स्तर पर करिए करोड़ों रुपये देते हैं भरोसा करते हैं और इस राशि को कम से कम दुगुनी कर दीजिए ताकि 10 हजार उसको ससमय पर मिल जाय और एक है कि आप चला रहे हैं सिक्स फाइनेंस, सिक्स फाइनेंस में पैसा आप कम देते हैं कभी 13 लाख दे देते हैं, कभी 12 लाख देते हैं उसको तीन कैटेगरी में बांट दिए हैं आप कि जेनरल फंड, मेंटेनेंस फंड और डेवलपमेंट फंड में बांट दिए हैं और उसका कर दिए हैं कि 40, 30–30 का रेशियो बना दिए हैं तो कोई काम पूरा नहीं हो पाता है, छोटा–छोटा होता है और पंचायत स्तर का एक फिफटींथ फाइनेंस है, जिसमें आपका तीन तरह का यह है कि अनटाइड, टाइड, टाइड आप टाइड में 40 परसेंट देते हैं और अनटाइड में 40 परसेंट और टाइड में 30 परसेंट, टाइड में 30 परसेंट लेकिन काम की जो आप एक सूची बनाए हैं कहीं न कहीं उतने पैसे में नहीं हो पाता है । अभी हाल में आप 9 लाख रुपया दे दिए अनटाइड में और टाइड में 9 लाख रुपया दे दिए लेकिन एक बनाने का जो यह है कि वह 11 लाख में कम से कम बनता है और जो पैसा रहता है उसी के अनुकूल काम करने के लिए भी कहते हैं और एक चीज इसमें यह है कि पुल–पुलिया बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है पंचायत में अभी । तो कम से कम यह 15वीं वित्त आयोग में पुल–पुलिया भी बनाने की व्यवस्था की जाय । पारिवारिक लाभ का जुड़ गया है कि आप ब्लॉक स्तर पर कर दिए हैं जिला में है, इसमें भी लाभ नहीं ले पाता है । इसको भी 20 हजार की राशि मिलती है, इसको भी पंचायत में कर दिया जाय। आपका पंचायत सरकार भवन एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वह पहले ठेकेदार के माध्यम से बनता था, बाद में आप पंचायत को दे दिए इसके लिए आपको धन्यवाद और यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह, यह भी पंचायत को दे दिए और इस संबंध में हम कहेंगे कि हमारे जो वार्ड सदस्य और पंच हैं वह कहीं न कहीं उसका जो सम्मानजनक मानदेय भत्ता नहीं है, वह कहीं न कहीं निराश है, उसमें कुछ न कुछ यह किया जाय और इस संबंध में हम अब चूंकि आर0सी0डी0 मंत्री जो हमारे हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, पथ निर्माण के भी मंत्री हैं सीमांचल के इलाका में पथ निर्माण की सड़कें कम हैं और उनसे हमलोग बहुत अपेक्षा भी रखते हैं किशनगंज से आते हैं कि सीमांचल में सभी क्षेत्रों में कम से कम आप आर0सी0डी0 का जो रोड है उसको बढ़ाया जाय । पर्यटन विभाग से है कि कोचाधामन में शीतलनगर में एक झील है इसी तरह का अररिया जिलांतर्गत बेलवा में भी एक झील है उसको भी मिथिला हाट की तर्ज पर सुजात्री हाट बनाया जाय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें, आपका समय हो गया है, आप आसन ग्रहण करें ।

मो0 मुर्शिद आलम : बायसा प्रखंड अंतर्गत मानवपारा से रौटा जानेवाली सड़क अमोल प्रखंड अंतर्गत बेलगच्छी पी0डब्लू0डी0 और मोछहट्ठा गरिया जानेवाली सड़क को भी आर0सी0डी0 में किया जाय ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, लोक जनशक्ति पार्टी (रा0) के नेता राजू जी ने हमारे पार्टी के बारे में कहा कि हम थे तब राष्ट्रीय जनता दल जिंदा थी, मैं सदन को और बिहार को बताना चाहता हूं महोदय कि 50 वर्ष तक रामविलास जी स्वर्गीय बेचारे कांग्रेस की बैसाखी पर चले और अंतिम समय में जब उनको भाजपा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार जी ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री कुमार सर्वजीत : उनका घर खाली करा रहा था महोदय, यही लालू यादव ने उनको राज्यसभा भेजा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार जी, आप अपना भाषण प्रारंभ करें।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने का जो मौका आपने दिया है, उसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद । सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक को बहुत–बहुत आभार और धन्यवाद । माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस गरिमामय सदन के माध्यम से बिहार की जनता को वह दौर याद दिलाना चाहता हूं जिसे इतिहास में लालटेन युग के नाम से जाना जाता था।

(व्यवधान)

और उसकी तुलना आज के ये लोग क्या करेंगे ? उसकी तुलना आज के स्वर्णिम युग से भी करना चाहूंगा पहले आईना में चेहरा तो देख लीजिए, आप अलकतरा पीनेवाले लोगों के साथ हैं । महोदय, यह वही बिहार है, जहां 2005 से पहले माननीय सदस्य प्रमोद भैया कह रहे थे कि सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढा में सड़क हुआ करता था । बारिश के दिनों में जब सड़कों पर निकलते थे तो युद्ध के जैसा हालात रहता था कि कब गिर जायेंगे । नदी बना हुआ रहता था, कई सड़क था वैसा । यह वही बिहार है जहां एक समय कागज पर ही सड़कें बना दी जाती थीं । महोदय, अलकतरा घोटाला को कौन भूल सकता है । जब राजद सरकार में सड़क निर्माण के लिए तेल कंपनियां एच0पी0सी0एल0, बी0पी0सी0एल0 आदि से अलकतरा खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपये सरकारी खजाने से निकाले गए

लेकिन वह अलकतरा कभी सड़कों तक पहुंचा नहीं । अधिकारियों और ठेकेदारों ने फर्जी बिल और ट्रांसपोर्ट वाउचर पेश किए, जांच में पाया गया कि जिन वाहनों के नंबरों को अलकतरा ढोने वाले ट्रक के रूप में दिखाया गया था, वह असल में स्कूटर रिक्शा और मोपेट के नंबर थे । लगभग 400 करोड़ रुपया से अधिक के इस घोटाले से पूरे देश में बिहार की जो किरकिरी हुई थी, वह हमलोग भूले नहीं हैं । भ्रष्टाचार और लेवी रंगदारी के डर से बड़े इंजीनियर बिहार छोड़कर भाग जाते थे और निर्माण कार्य पूरी तरीके से बाहुबलियों के चंगुल में थे । बड़े से लेकर छोटे कामों तक में गुंडा टैक्स चलता था । अध्यक्ष महोदय, आज परिस्थितियां कितनी बदली है, इसको मैं आंकड़ा के माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 के बीच में सड़क के निर्माण की दर प्रतिवर्ष तीन सौ से चार सौ कि0मी0 हुआ करती थी, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि एन0डी0ए0 के शासन में यह दर बढ़कर के 25 सौ से 3 हजार कि0मी0 तक प्रतिवर्ष पहुंच गई है । वर्ष–2005 तक प्रदेश के कोने–कोने से किसी जगह पर पहुंचने में 12 से 15 घंटे का समय लगता था, हमको तो लगता है कि यहां से बेगूसराय हम दो घंटे में पहुंचते हैं जबकि रास्ते में फतुहा पहुंचने में लग जाता था तीन–चार घंटा, यही समय मसौढ़ी पहॅुचने में लगता था । आज हमलोग दो घंटे में गया और बेगूसराय, कहीं भी पांच घंटे में पहुंच सकते हैं आगे हमलोगों का लक्ष्य इसको घटाकर के तीन से चार घंटा तक करने को लेकर के आया है । 2005 से पहले पूर्व प्रदेश के पुल पुलियों की क्या स्थिति थी, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है । जर्जर पुल और अधूरे पुल दशकों तक लंबित कार्य बंद रहा है । वैसा भी दौर देखे हैं । अध्यक्ष महोदय, अभी बता रही थी माननीय सदस्या, उसका पूरा नाम हम नहीं लेंगे सब सड़कों का लेकिन आज गंगा पर 17 से अधिक मेगाब्रिज या तो कार्य कर रहे हैं या तो निर्माणाधीन है । आज उत्तर बिहार से पटना, दक्षिण बिहार पहुंचना मात्र कुछ घंटों का खेल रह गया है । अध्यक्ष महोदय, एन0डी0ए0 शासन जवाबदेही और विजन के दो पहियों पर आधारित है । 2005 के बाद जब एन0डी0ए0 की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबसे पहले भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया गया और आज प्रदेश के जर्जर हो चुके कानून व्यवस्था को भी सशक्त बनाया गया । अध्यक्ष महोदय, पुरानी ठेकेदारी प्रथा को पारदर्शी बनाया गया । ई टेंड्रिंग लागू की गई तथा काबिल लोगों को काम मिले, बाहुबलियों को न मिले इसका ध्यान रखा गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने और उसे राज्य के कोने–कोने तक पहुंचाने के लिए कितनी गंभीर है, इस बात से समझा जा सकता है । (क्रमशः)

टर्न–21 / मुकुल / 10.02.2026

क्रमशः

श्री संजय कुमार : पिछली सरकारों ने केवल सत्ता के केन्द्रों को सड़क से जोड़ा, हमने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिये सुदूर टोले और मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया । जहां वर्ष 2005 से पहले बिहार के केवल 15 परसेंट गांव सड़क से जुड़े थे आज 95 प्रतिशत से अधिक टोले में पक्की सड़क जुड़ चुकी है । जहां हमारा बजट जो पहले था 200 करोड़ के लगभग था आज हमारा जो बजट है 18 हजार 716 करोड़ रुपये का है, यह हमारा कई गुना में वृद्धि है। बिहार के विभिन्न हिस्सों को औद्योगिक केन्द्र और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए पांच नये एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है। उसकी घोषणा हो रही है उसमें पटना–पूर्णिया एक्सप्रेस वे, भागलपुर–बक्सर एक्सप्रेस वे, गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे, रक्सौल–हलदिया एक्सप्रेस वे, बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेस वे ये सभी सड़कें बिहार की आर्थिक प्रगति को अभूतपूर्व गति देगी । मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 हजार कि0मी0 नई सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है यह बिहार को बदलने के लिए दृढ़–निश्चय और संकल्प का नीतिगत आधार है । महोदय, एक लंबे समय तक हमारे यहां रोड मेंटेनेंस जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, पिछली सरकार की मानसिकता थी सड़क बना दो और भूल जाओ, कागज पर बना दो और भूल जाओ, लेकिन एन0डी0ए0 सरकार ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लाकर जवाबदेही तय की । आज अगर सड़क खराब होती है तो संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगता है, यह हमारे गुड गवर्नेंस का जीता–जागता उदाहरण है । इस वर्ष के बजट में भी सड़कों के बेहतर रख–रखाव के लिए 3 हजार करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है ताकि बनी हुई सड़कें जर्जर न हों । महोदय, एक सही और ईमानदार नेतृत्व का क्या प्रभाव होता है इसे इस बात से समझा जा सकता है जब केन्द्र और राज्य दोनों में एन0डी0ए0 की सरकार है तो बिहार को 54 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मिला है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बिहार को विकास के प्राथमिकता के आधार पर ऊंचाई पर रखा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पी0एम0 गति कुशल विजन और केन्द्र से मिले 50,000 करोड़ रुपया से अधिक के पैकेज ने बिहार की सड़कों को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे के वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया है । महोदय, मैं इस सदन में पटना के कुम्हरार विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं इसलिए मेरे लिए पटना भी एक आवश्यक है। हम सब लोगों के ध्यान में है कि पटना का विकास कितना तीव्र गति से हुआ है। विपक्ष के सदस्य तो सब लोग यहीं रहते हैं आज अगर 10 वर्षों के

बाद कोई पटना आये तो भूल जायेगा कि पटना किधर से किधर, कौन पुल से निकले, ध्यान ही नहीं रहेगा, विकास का आईना तो आपको यहीं पर दिखता है कि वह कैसा हुआ है । ऐसा पिछले 20 वर्षों में पटना में जिस तेजी से रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ है यह न केवल ऐतिहासिक है बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए भी एक उदाहरण है । पटना जे0पी0 गंगा पथ जिसे विपक्ष कभी असंभव कहता था, आज बिहार की शान है । अटल पथ आर–ब्लॉक से दीघा के बीच बना यह 6–लेन का एक्सप्रेस वे पटना का लाइफलाइन बन चुका है । इसके अतिरिक्त शहर में जिस तेजी से फ्लाईओवरों का जाल बिछाया गया है, वह भी बेमिसाल है । लोहिया पथ चक्र, करबिगहिया–मीठापुर फ्लाईओवर, पटना से महुली फ्लाईओवर, एम्स–दीघा एलिवेटेड रोड, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज अशोक राजपथ पर डबल–डेकर फ्लाईओवर यह सब यह हमलोगों का आईना है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री संजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । भारत माला परियोजना के तहत बिहार में बन रहे एक्सप्रेस वे आने वाले समय में बिहार को दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर का लॉजिस्टिक हब बना देगा । बौद्ध सर्किट और राम–जानकी मार्ग सड़कों ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया है, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया से जोड़ा है । आज डबल इंजन की सरकार में बिहार तेजी से बढ़ रहा है और रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रतिदिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद । महोदय, एक और विषय सिर्फ ध्यान में दिलाना चाहते हैं कि इतना काम हुआ लेकिन चूंकि शहर में है, 6 मीटर की जो सड़कें हैं उनको भी हम सब लोगों ने तय किया था कि हमलोग बनायेंगे। इस पर भी.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री अरूण बाबू । अपना पक्ष रखें, आपके पास 1 मिनट का वक्त है ।

श्री अरूण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005 में डबल इंजन की सरकार आयी, यह बात तो हमें मालूम है और 2005 के पहले भी मैं विधायक था और 2005 के बाद भी मैं विधायक लगातार हूं । इसलिए दोनों शासन को हमने बहुत बारीकी से देखा है। 2005 में हमने देखा पहले कि गरीब बसते थे बिहार सरकार की जमीन पर और 2005 के बाद हम देख रहे हैं कि गरीब को उजारा जा रहा है बिहार सरकार की जमीन पर से, दूसरा हमने देखा कि न्याय की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है । अब देख लीजिए विधान सभा में आप घोषणा करते हैं कि सबको 5 डिसमिल जमीन दिया जायेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट कहता है कि बिना बसाये उनको उजाड़ा नहीं जायेगा । 1948 में

कानून बना कि सबको बसने की जमीन दी जायेगी, कानून नहीं है, तोड़े जा रहे हैं मकान । महोदय, हम 2005 के बाद देख रहे हैं कि भारत, अमेरिका का अभी हाल ही में ट्रेड डील आया, भारत का सर नीचे झुक गया । कभी नहीं सुने होंगे, इस तरह का अपमानजनक समझौता देश में कभी नहीं हुआ । अभी एपस्टीन फाइल खुला....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, सुन लीजिए, हमारा इतना दिमाग खराब हो गया, 2005 के बाद क्या था । फाईल खुला है ये, फाईल क्या है यह बात आप समझ लीजिए । महोदय, अब मैं कहना चाहता हूं.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है ।

श्री अरूण सिंह : अगर आप रोड बनाना चाहते हैं तो ग्लोबल टेंडर को बंद कीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अरूण बाबू आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अरूण सिंह : इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, ये ग्लोबल टेंडर को बंद कीजिए और जो दलित बस्तियां हैं वहां सड़क बनाइये, सुलभ सम्पर्कता को लागू कियें हैं उसपर काम कीजिए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । आपके पास एक मिनट का वक्त है, गागर में सागर भरिये ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया । महोदय, पथ निर्माण विभाग के बारे में, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं मोहनियां–चौसा रोड एन0एच0 319–A पजरांव गांव के सामने गोरिया नदी पर निर्माणाधीन पुल बन रहा है लेकिन उसकी हाइट इतनी कम ऊंचाई कर दी गयी है कि अभी इस साल बरसात के मौसम में पानी जो है पुल के स्लैब से टच कर रहा था, अगर जांच करके उस पुल की ऊंचाई को नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे । साथ ही, महोदय दुर्गावती ककरैत रोड पथ निर्माण विभाग का रोड है जो सीधे एन0एच0–19, जी0टी0 रोड से उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, इस रोड के चौड़ीकरण की मांग वर्षों से हो रही है, क्योंकि इस रोड पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, इसके चौड़ीकरण की भी मांग मैं पथ निर्माण विभाग के मंत्री जी से करना चाहता हूं । महोदय, इसी दुर्गावर्ती ककरैत रोड पर बहेरा गांव के सामने मुगलसराय गया रेलवे लाइन है महोदय, उस रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज नहीं होने से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है । साथ ही, महोदय, दुर्गावती में एन0एच0–19 जी0टी0 रोड पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत हुआ और वह जी0टी0 रोड स्वीकृत हुआ था, 4–लेन, 6–लेन और 8–लेन तक वह स्वीकृत हो गया लेकिन आज तक दुर्गावती में महोदय वह रोड आधा–अधूरा बना हुआ है जिसके कारण उस रोड पर हर दिन

रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, क्योंकि दुर्गावती के सामने महोदय, बहुत जरूरी विषय है, वहां पर दुर्गावती ककरैत रोड जाता है एक तरह और दूसरी तरफ जी0टी0 रोड के स्वयं पथ निर्माण विभाग का दो सड़क है, एक सड़क है दुर्गावती–हाटा रोड और एक सड़क है दुर्गावती–चैनपुर रोड । महोदय, वहां पर आज तक एन0एच0–19 में अंडरपास, दुर्गावती के पास नहीं बना है महोदय, तो मैं इसकी भी मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया है । अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, अजय बाबू । आपके पास एक मिनट का समय है, गागर में सागर भरा जाए ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण का बजट है और मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पथ निर्माण विभाग ने एक पत्र दिया था कि नितिन नवीन साहब आये थे आज और उन्होंने पत्र दिया था कि पथ निर्माण विभाग के बगल में जल निस्सरण के लिए नाला का निर्माण वह विभाग करायेगी।

क्रमशः

टर्न–22 / सुरज / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्री अजय कुमार : उसके विहाफ में मैं एक पत्र दिया था । विभूतिपुर के पटपाड़ा में, सिंघिया में, फखसाहा में जल–जमाव के कारण साल में दो बार वह सड़कें टूट जाती है और वह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता है इसलिये मैं समझता हूं कि उसको आपको जोड़ना चाहिये । उद्योग विभाग के लिये बिहार का एकलौता नाथनगर का रेशम उद्योग था, जो बुनकरों को अनुदान के अभाव में, आज रेशम उद्योग जो वहां था उसकी चमक आज वह खो रहा है । हैवी इंडस्ट्री के बगैर बिहार के अंदर पलायन को रोकना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, बिल्कुल यह संभव नहीं है । इसलिये हैवी इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत है । अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिये मैं कहना चाहता हूं कि आज आपको दलित बस्ती के लिये सड़क नहीं है और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में आज से कुछ रोज पहले सिर्फ मजदूरी मांगने के लिये गया और उसकी पिटाई कर दी गयी और 11 साल की बच्ची जिसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया और कोई आपका विभाग इस पर कुछ नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है बिहार के अंदर ? यह सिर्फ सड़क का नहीं है । ये आपने सभी चीजों को दिया । उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका छात्रवृत्ति जो आपका सेंसेक्स है 2023 को उसमें 44 हजार दलित छात्र और छात्राएं जिनको आवासीय विद्यालय और छात्रवृत्ति और आवास से वंचित है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : महोदय, एक लाइन कहकर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं । पंचायती राज विभाग ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिये एक मानदेय तय किया था और वह इतना अल्प मानदेय है, उसका पुनरीक्षण करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है और जिनका बकाया है उसका अविलंब भुगतान करने की जरूरत है ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता जी। आपके पास 01 मिनट का वक्त है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : जी महोदय, जानते हैं हमारे पास तो उतना ही समय रहेगा । लेकिन मैं 3 चीजों के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं । जब मैं बजट देख रहा था विशेष रूप से तीन चीजों के लिये आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । पहला कि पिछले एक दशक में पहली बार काबिल मंत्री बने हैं आदरणीय श्री दिलीप जायसवाल जी और मैं तो चाहूंगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो इनको रोड निर्माण में बनाए रखिये, उद्योग भले ही किसी को दे दीजिये । मैं दिल से आपको इस्तकबाल करता हूं कि आप एक बेहतरीन मिनिस्टर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है । लेकिन हुजूर नंबर दूसरा बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 जो सरकार लेकर आयी है यह देर से लाया हुआ लेकिन एक बढ़िया कदम है उसका भी मैं समर्थन करता हूं मंत्री जी । तीसरा है कि 250 मीटर से अधिक पुल वाले जो 85 पुलों को आपने मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिये जो आई0आई0टी0, दिल्ली और पटना को आपने जो एम0ओ0यू0 किया है Really this is very appreciable of commondable work have you done मंत्री जी । लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सारे पुलों के लिये कीजिये । अगर यह पहले किये होते तो ये जो धकाधक–धकाधक पुल गिर है न बिहार में, वह नहीं गिरा होता । आप इसको भी कीजिये और साथ में माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जमुई में तीन पुल बना है और जब से बना है, तब से क्रैक हो गया है । अभी तक वह पुल झुका हुआ है उसको माननीय मंत्री जी जरा दिखवा लीजियेगा और आपने एक आर0ओ0बी0, सहरसा में दिया है जिससे 50 परसेंट उसका ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है । तीन आर0ओ0बी0 के लिये मैंने तारांकित प्रश्न डाला है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : उसको आप जरा देख लीजियेगा ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जाएं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : हुजूर, यह सात निश्चय के तहत 2025 और 2030 में पांच जो न्यू एक्सप्रेस–वे बनाने की बात हुई है...

उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : उसमें सहरसा और जमुई को जोड़ दीजियेगा तो मैं हमेशा समर्थन करूंगा हुजूर और लास्ट में आप जो कहते हैं कि बजट लाना पड़ता है पूरक । नार्मली जब टेंडर निकला है तो ठेकेदार और विभाग के....

उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : और उसमें इस्टीमेट को बढ़ाया जाता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रकाश चन्द्र । आपके पास 04 मिनट का वक्त है ।

श्री प्रकाश चन्द्र : धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय । आज मुझे पहली बार इस सदन में बोलने का मौका मिला है, इसके लिये मैं आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के प्रति, जिन्होंने मुझे इस सदन का सदस्य बनने का मौका दिया और मेरे इस कंधे पर भरोसा किया । क्योंकि मैं जिस ओबरा विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं, वहां एन0डी0ए0 पहली बार चुनाव जीती है और एक दल विशेष के गढ़ को उखाड़कर अपनी जीत को सुनिश्चित की है । मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों का कि आपके द्वारा जो इतने अच्छे काम बिहार में किये जा रहे हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी बहुमत के साथ एन0डी0ए0 चुनाव जीतकर आयी है । मैं अपने नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारा दिया था कि मैं उस घर में दीया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है और यह एन0डी0ए0 की सरकार उसी अनुरूप काम कर रही है । आप दलित, महादलित, गरीब सभी के उत्थान के लिये लगातार काम कर रहे हैं । आज मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांगों के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं आभार प्रकट करता हूं अपने पथ निर्माण मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी का जो लगातार हमारे बिहार की सड़कों को और सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं । आज मैं इस सम्मानित सदन के सामने बिहार की प्रगति की जीवन रेखा यानी पथ निर्माण विभाग के गौरवशाली वर्तमान और विजनरी भविष्य को प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारी सरकार के लिये सड़कें केवल कोलतार और कंक्रीट का ढांचा नहीं है बल्कि यह बिहार के विकास की वह धमनियां हैं जिनसे होकर राज्य की समृद्धि का रास्ता गुजरता है । महोदय, मुझे यह बताते हुये गर्व है कि हमारी सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के बजट के बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया है । सड़कों के लिये लगभग 17 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । जहां 2015–16 में ग्रामीण सड़कों की लंबाई 64 हजार किलोमीटर थी वह आज बढ़कर 1 लाख 19 हजार किलोमीटर को पार कर चुकी है । बिहार अब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहां सड़क घनत्व, रोड डेनसिटी सबसे अधिक है और यह मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को भी पूरा

करता है । बिहार अब सिंगल लेन से आगे बढ़कर हाईवे और एक्सप्रेस–वे स्टेट बनने की ओर अग्रसर है । आमस–दरभंगा एक्सप्रेस–वे बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो 2026 तक पूरा होने की ओर है । वाराणसी–औरंगाबाद सिक्सलेन इस परियोजना के पूरा होने से बिहार से दिल्ली और कोलकाता का सफर घंटों कम हो जायेगा । भविष्य का विजन सात निश्चय–3 के तहत हम पांच नए एक्सप्रेस–वे जैसे पटना–पूर्णियां, बक्सर–भागलपुर और गोरखपुर–सिल्लीगुड़ी पर काम शुरू कर रहे हैं जो बिहार के आर्थिक भुगोल को बदलकर रख देगा । माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पटना पहुंचने में पांच घंटे से अधिक का समय न लगे और आज हम उस लक्ष्य के बहुत ही करीब हैं । विपक्ष के साथी अक्सर सवाल उठाते हैं लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ पथ निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि रख–रखाव मेंटेनेंस पॉलिसी पर भी सख्ती से काम कर रहे हैं । हाल ही में विभाग ने 131 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है, स्पष्ट निर्देश है काम में देरी या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जायेगी । डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिये हर प्रोजेक्ट की पल–पल की रिपोर्ट ली जाती है । महोदय, यह सड़कें केवल आवागमन के लिये नहीं है, यह हमारे किसानों के लिये मंडियों का द्वार खुल रही है, हमारे युवाओं के लिये उद्योगों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, पर्यटन के नये केन्द्र विकसित कर रही है । हमारी सरकार डबल इंजन की रफ्तार से बिहार के विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने के लिये प्रतिबद्ध है । महोदय, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं, मैं औरंगाबाद जिला से गुजरने वाली एन0एच0–139 के बारे में कुछ कठिनाइयों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मैं सबसे पहले माननीय पथ निर्माण मंत्री जी का इस सदन में आभार प्रकट करूंगा कि चुनाव जीतने के दो दिनों बाद मैं आपसे मिला था । मैंने लोगों से कहा था कि एन0एच0–39 जो कि मौत की सड़क बन गयी है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री प्रकाश चन्द्र : उसकी चौड़ाई इतनी कम है जिसके कारण लगातार दुर्घटनाएं होती थी, लोगों की मौत होती थी । आपने आश्वस्त किया कि तीन–तीन मीटर उसकी चौड़ाई बढ़ायी जायेगी लेकिन मैं मांग करता हूं कि जिस सोन तट से यह सड़क गुजरती है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अनिता ।

श्री प्रकाश चन्द्र : महोदय, एक मिनट का समय दें । मैं पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक मिनट में मेरी बात को पूरा कर लेने दिया जाए ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अनिता ।

श्री प्रकाश चन्द्र : गंगा नदी के किनारे गंगा एक्सप्रेस–वे बनाया है । सोन नदी के किनारे भी फोरलेन सड़क का निर्माण करें ताकि बालू के कारण वह सड़क जाम रहता है । लोगों का आवागमन...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्या श्रीमती अनिता ।

श्रीमती अनिता : जय हिंद माननीय उपाध्यक्ष महोदय । राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के पुरोधा माननीय लालू प्रसाद यादव जी । संकल्पित, समर्पित युवा दिलों की धड़कन नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद और आभार । जिन्होंने मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में बोलने का अवसर प्रदान किया । सूबे बिहार के देवतुल्य, परिवारतुल्य, अभिभावक तुल्य जनता मालिकों

(क्रमशः)

टर्न–23 / धिरेन्द्र / 10.02.2026

....क्रमशः...

श्रीमती अनीता : महोदय, मुंगेर लोकसभा के सभी जनता मालिकों, नवादा जिला के वारिसलीगंज विधान सभा के सभी जनता मालिकों को तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ । आज पथ निर्माण विभाग, अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्यय में पथ निर्माण विभाग की अनुदान मांगों पर वाद–विवाद एवं विमर्श में सरकार के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

चमकती सड़कें सिर्फ विज्ञापनों में हैं, धरातल पर भ्रष्टाचार का गड्ढा है । पुलों का गिरना, पिछले दो सालों में बिहार में एक दर्जन से अधिक निर्माणाधीन पुल गिरे हैं । जैसे–सुलतानगंज का अगुवानी घाट पुल । क्या यह इंजीनियरिंग की विफलता है या कमीशनखोरी की ? रख–रखाव का अभाव, नई सड़कों की लाइफलाइन 05 साल होती है लेकिन पहली बारिश में ही वे उखड़ जाती हैं । मेंटेनेंस पॉलिसी सिर्फ कागजों पर है ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है सड़कें विकास की भाग्यरेखा है लेकिन बिहार में ये भ्रष्टाचार की लाइफलाइन बन चुकी है । पुल पानी में बह रहे हैं और मंत्री जी नैतिकता की बात कर रहे हैं । महोदय, नवादा जिला में नवादा से पकरीबरावां होते स्टेट हाइवे जो जमुई तक गई है यह सड़क दक्षिणी बिहार को देवघर से जोड़ती है इसे फोरलेन किया जाना अति आवश्यक है । पकरीबरावां बाजार से हमेशा जाम लगी रहती है । पकरीबरावां में बाइपास का निर्माण किया जाना बहुत ही जरूरी है । महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र वारिसलीगंज में पथ निर्माण विभाग की सड़क....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, टोका–टोकी नहीं कीजिये ।

श्रीमती अनीता : महोदय, सरकट्टी मोड़ से काशीचक सुभानपुर होते चातर मोड़ तक 20 किलोमीटर सड़क बहुत ही सकरी है इस सिंगल रोड पर गाड़ियों के पास लेने में काफी परेशानी होती है बरसात में गाड़ियां जगह–जगह पर फंस जाती है ।

इस सड़क को चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है । इस सड़क को चातर मोड़ से धरणीविगहा के रास्ते केसउरी मोड़ तक ले जाना बहुत जरूरी है ।

महोदय, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सड़क बनाने वाले जितने भी संवेदक, ठेकेदार हैं उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्गों की हिस्सेदारी नहीं है, इन सभी वर्गों के लिए ठेकेदारी में आरक्षण के प्रावधान की मांग मैं करती हूँ ताकि सामाजिक न्याय हो सके ।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं नवादा की उस धरती की आवाज बनकर खड़ी हूँ, जहाँ के किसानों के साथ इस सरकार ने क्रूर मजाक किया है । वारिसलीगंज में अडानी सीमेंट फैक्ट्री के नाम पर जो खेल हो रहा है, वह विकास नहीं, किसानों की विरासत की हत्या है । अध्यक्ष महोदय, मेरा सदन से सीधा सवाल है कि चीनी मिल की हत्या क्यों ? वारिसलीगंज में दशकों से चीनी मिल बंद पड़ी है । वहाँ की जमीन उपजाऊ है, किसान मेहनती हैं । वहाँ फिर से चीनी मिल की फैक्ट्री लग सकती थी...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे–बैठे नहीं बोलें ।

श्रीमती अनीता : महोदय, जिससे गन्ने की खेती को बढ़ावा मिलता और किसानों की खुशहाली लौटती लेकिन सरकार ने किसानों के हित वाली चीनी मिल को पुनर्जीवित करने के बजाय, वहां एक प्रदूषणकारी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है, जो जनहित में काफी गलत है । सरकार ने फैक्ट्री लगाने के लिए सभी मापदंडों का घोर उल्लंघन कर रही है । अडानी सिमेंट फैक्ट्री के निर्माण में एन॰ओ॰सी॰ ग्राम पंचायत, मोसमा के नाम से लिया गया जबकि वह जमीन नगर परिषद वारिसलीगंज के लाखों लोगों के घनी आबादी से सटा हुआ है। सिमेंट फैक्ट्री को आबादी से दूर बनानी चाहिए परंतु वहाँ रह रही जनता को मौत के मुँह में धकेला जा रहा है । जमीन को बंजर बनाने की साजिश आस–पास के गांव जैसे चैनपुरा और लीलाविगहा के किसानों के खेतों में बिजली के ऊंचे–ऊंचे टावर गाड़े जा रहे हैं । टावर गड़ने से जमीन स्थायी रूप से बंजर हो जाएगी । साथ ही, सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली धूल पूरी उपजाऊ भूमि पर जम जाएगी जिससे फसलें बर्बाद हो जाएंगी । इसके धूल से 10 किलोमीटर की परिधि में रह रहे नागरिकों को गंभीर बीमारी से जूझना पड़ेगा । एक तरफ चीनी मिल थी जो मिट्टी को सोना बनाती थी और दूसरी तरफ यह सीमेंट फैक्ट्री खुल रही है जो मिट्टी को राख बना देगी । क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया कि सीमेंट फैक्ट्री की बजाय अगर वहां चीनी मिल शुरू होती तो किसानों को कितना ज्यादा फायदा होता ? अध्यक्ष महोदय, सरकार अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए उपजाऊ जमीन को रेगिस्तान बनाना बंद करे । वारिसलीगंज की उस बंद चीनी मिल को फिर से

चालू करने का रोडमैप बनाए । अध्यक्ष महोदय, हमें सीमेंट की धूल नहीं, चीनी की मिठास और किसान की खुशहाली चाहिए ।

महोदय, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण विकास और राजनीतिक भागीदारी में बड़ी क्रांति लाई है लेकिन इसके कई नकारात्मक पहलू और चुनौतियां आज भी हैं जो इसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा बनती है । भ्रष्टाचार और बंदरबांट, पंचायती स्तर पर सरकारी फंड के दुरूपयोग की शिकायतें आम हैं । नल–जल योजना और गली नाली पक्कीकरण जैसी योजनाओं में कमीशनखोरी और घटिया निर्माण सामग्री का मुद्दा अक्सर सामने आता है । विकास कार्यों का लाभ आम जनता तक पहुँचने से पहले ही बिचौलियों के पास चला जाता है । वित्तीय निर्भरता, बिहार की पंचायतों के पास अपने राजस्व के स्रोत बहुत ही सीमित हैं । वे पूरी तरह से राज्य और केन्द्र सरकार के फंड पर निर्भर हैं । जब तक फंड नहीं आता, पंचायतें कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पातीं । नौकरशाही का हस्तक्षेप है सर, पंचायत प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों बी॰डी॰ओ॰, पंचायत सचिव के बीच बक्सर तालमेल की कमी रहती है । विकास कार्यों की फाइलों को पास कराने के लिए प्रतिनिधियों को लंबी कागजी कार्रवाई और अफसरों की मनमानी का सामना करना पड़ता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका एक समय का वक्त है ।

श्रीमती अनीता : महोदय, काशीचक ब्लॉक के पार्वती पंचायत में पार्वती गाँव में पार्वती गुफा में गौतम बुद्ध आए थे और एक साल तक निवास किए थे । इस पार्वती गुफा को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की मैं सरकार से मांग करती हूँ।

बिहार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की मुख्य कमियां आप ध्यान से सुनिये । छात्रवृति में भारी देरी, सबसे बड़ी समस्या पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति के वितरण में होती है । तकनीकी खामियों और वेरिफिकेशन की सुस्त प्रक्रिया के कारण छात्रों को समय पर पैसा नहीं मिलता.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं ।

श्रीमती अनीता : महोदय, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है । छात्रावासों की बदहाली ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती अनीता : महोदय, राज्य के कई कल्याण छात्रावासों की स्थिति चिंताजनक है । बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होता ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मीना कुमारी । आपके पास 15 मिनट का वक्त है ।

श्रीमती अनीता : महोदय, भ्रष्टाचार और बिचौलिए से भी बचाया जाय । जागरूकता की भी कमी है । यदि सरकार....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभारी हूँ कि

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, आपने मुझे पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में अपना विचार रखने का मौका दिया । साथ ही, उद्योग विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन विभाग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के पक्ष में, सरकार के पक्ष में मैं बोलना चाहती हूँ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पथ निर्माण मंत्री को हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने मुझे पथ निर्माण विभाग पर बोलने का मौका दिया और साथ ही, मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ माननीय ऊर्जा मंत्री, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय हमारे सदन के नेता, हमारे गॉड फादर जो हमेशा, मैं उनके नेतृत्व में रहकर, मैं जब छात्र जीवन से राजनीति देखते आ रही हूँ, तब से मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखते हुए बड़ी हुई हूँ और उनके नक्शे–कदम की उनकी सोच, उनकी विचारधाराओं को, उनकी समाजवादी जो विचार रही और मेरे फादर–इन–लॉ जो मेरे ससूर जी इनके साथ काम किये और उन्हें वर्ष 2015–20 में पंचायती राज मंत्री के रूप में इनके साथ काम करने का मौका मिला । इन सारी चीजों को देखते हुए आज मैं खुद को इतना खुशनसीब मानती हूँ कि जिस नेता को मैंने अपना गॉड फादर माना, जिसकी राजनीति को देखते हुए मैंने अपनी राजनीति सीखी, उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने नेता की आभारी हूँ....

....क्रमशः....

टर्न–24 / अंजली / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्रीमती मीना कुमारी : और आभारी हूं मैं बाबुबरही विधान सभा की उस महान जनता की जिसने दूसरी बार मुझे चुनाव जीताकर सदन में भेजा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली को दर्शाते हुए उनके लिए मैं चार पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी–

''परिंदे को मिलेंगे, मंजिल एक दिन,
ये उनके फैले हुए, पंख बोलते हैं,
वही लोग रहते हैं, खामोश अक्सर,
जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं ।''

साथ ही, मैं मुख्य सचेतक श्री श्रवण बाबू जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ।

महोदय, बिहार के लिए जो बजटीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है इससे यह स्पष्ट यह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व

में डबल इंजन की सरकार के समेकित सहयोग से बिहार के विकास के लिए संकल्पित है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एवं बदलते बिहार के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक एवं शैक्षणिक विकास में पथ निर्माण विभाग की भूमिका अग्रणी है । महोदय, पथ निर्माण विभाग उच्च गुणवत्ता एवं त्वरित निर्माण के मूल मंत्र के आधार पर योजनाओं का कार्य कराने में बल देती है । साथ ही, राज्य सरकार के न्याय के साथ विकास का नजरिया रखते हुए सभी क्षेत्रों और वर्गों को लेकर सरकार कृत–संकल्पित है । पूरे देश में बिहार ने जो परिवर्तन की अंगड़ाई ली, उसमें पथ निर्माण विभाग ने एक बड़ी भूमिका निभायी है, जो निश्चित रूप से सराहनीय है । महोदय, बिहार के उत्थान हेतु राज्य के सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग दृढ़संकल्पित है । विकसित भारत 2047 को दृष्टिपथ में रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पथ एवं पुल परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे आने वाले वर्षों में सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में राज्य में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सकेगी। महोदय, पथ निर्माण विभाग ने जो आज सड़क का नजरिया बदला है, आज बिहार के किसी भी कोने से चार से पांच घंटा में हमलोग पटना आ जाते हैं, चाहे वह किशनगंज हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी या मधुबनी हो, चाहे पश्चिमी चंपारण हो या पूर्वी चंपारण हम चार से पांच घंटा में पटना पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले की जो स्थिति थी, हमको याद है, हमलोग जब अपने क्षेत्र में एक किलोमीटर का सफर तय करते थे तो हमलोगों को दो से तीन घंटा जाने में लगता था, लदनिया से जयनगर जाने में हमलोगों को लगभग 1 से डेढ़ घंटा की दूरी तय करनी पड़ती थी, आज वहां हमलोग 15 मिनट में पहुंच जाते हैं, तो यह स्थिति थी 2005 से पहले वाली सरकार की। महोदय, पथ निर्माण विभाग के द्वारा राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए हर विभाग में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत सफलता मिल गई है । महोदय, राज्य सरकार के विगत एक वर्ष में लगभग 38732.54 करोड़ रुपए की कुल 266 पथ एवं पुल परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें राज्य अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक के आवागमन में काफी समय की बचत भी होती है तथा राज्य के आर्थिक विकास को और गति मिलेगी, जिसका जिक्र माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी किया है । उन्होंने कहा है कि राज्य के बड़े पैमाने पर नई सड़कों, पुल–पुलिया, रेल ओवर–ब्रिज, एलिवेटेड रोड, बाईपास का निर्माण तथा पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया जाना है । जिससे लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से राजधानी पटना पहुंचना संभव है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और एन0डी0ए0 सरकार के नेतृत्व में, उनकी दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि हैम मॉडल के तहत बिहार में 17 हजार करोड़ की सड़कें, हाइवे का निर्माण कराया जा रहा है महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एन0डी0ए0 सरकार ही यह पहल कर सकती है । महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष उस दिन बोल रहे थे कि महिलाएं बिहार में बिकती हैं, यह नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता, यह सदन के अंदर में बोला गया है ।

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बोला है ।

श्रीमती मीना कुमारी : नेता प्रतिपक्ष बोले हैं कि महिलाएं बिकती हैं सदन में, यह प्रूफ है महोदय । ये बोले हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्रीमती मीना कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए यह अपशब्द...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति । आलोक बाबू, बैठ जाइए ।

श्रीमती मीना कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, शायद बाकी लोग नहीं सुने हैं, आप प्रोसीडिंग निकाल कर दिखवा लीजिए कि उसमें नेता प्रतिपक्ष बोले हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप अपनी बात रखें, माननीय सदस्या । समय का अभाव है ।

श्रीमती मीना कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के दम पर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो अधिकार दिया है, जो बिहार ने इज्जत दी है, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर कटाक्ष नहीं करना चाहूंगी लेकिन नेता प्रतिपक्ष को मैं कहना चाहूंगी कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय,

''कोमल हूं कमजोर नहीं,
शक्ति का नाम ही नारी है,
इस जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है ।''

मैं इस कविता के माध्यम से ही नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा संस्कार सीखकर आइए, आपके घर में भी माँ–बहन हैं उनकी इज्जत करना सीखिए, कम से कम सात बहन आपकी भी है, आप महिलाओं की इज्जत करना सीखिए । आज इस सदन में हम बोल रहे हैं, जिन

महिलाओं पर जिन्होंने कटाक्ष किया है, उन्हें बिहार का नेतृत्व करने का कभी मौका नहीं मिलेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्रीमती मीना कुमारी : वह महिलाएं ही उन्हें बिहार की गद्दी पर कभी नहीं बैठने देगी, यह मैं इस सदन से आज कहना चाह रही हूं कि कभी भी उनको नहीं बोलने का मौका मिलेगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं । आप अपनी बात रखिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, राज्य सरकार से मैं सुरक्षित....

(व्यवधान)

सुनिश्चित करने हेतु राज्य का.....

(व्यवधान)

एलिवेटेड पथ के निर्माण के साथ–साथ, रेल समपार आर0ओ0बी0 निर्माण के सुदृढ़ किया जाता है....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : किये जा रहे एक सराहनीय कदम है । सभी सिंगल लेन विभागीय पथों के आगामी वर्षों में चरणबद्ध तरीके से....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : समय कम है । पथ निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, समय बेवजह बर्बाद मत किया जाय ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, राष्ट्रीय उच्च पथ के महत्वपूर्ण मेघा परियोजना क्रमशः औंटा सिमरिया के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल, बख्तियारपुर, मोकामा पर फोर लेन पुल परियोजना पूर्ण की जा रही है । दानापुर–बिहटा–कोईलवर–आमस...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाए रखिए ।

श्रीमती मीना कुमारी : दरभंगा, ग्रीनफील्ड परियोजना, मुंगेर, मिर्जाचौकी पर फोर लेन की परियोजनायें की जा रही हैं । परियोजना दिघवारा–शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल, महात्मा गांधी सेतु को...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : 15 मिनट समय था महोदय ।

उपाध्यक्ष : संक्षिप्त करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : जी महोदय । महोदय, पथ निर्माण के साथ–साथ पंचायती राज पर भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी । पंचायती राज के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है और उसके बाद

विवाह मंडप की भी, महिलाओं को इतना सम्मान अभी तक मिला है, पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए विवाह भवन का निर्माण कराया जा रहा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15वें वित्त के तहत जो अभी विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ग्रामीण एरिया में जो काम नहीं हो रहा है, 15वें वित्त और 16वें आयोग के तहत बहुत सारी गली–नली में काम किया जा रहा है महोदय ।

उपाध्यक्ष : अपना भाषण समाप्त करें माननीय सदस्या ।

श्रीमती मीना कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी एक–दो मांग रखना चाहूंगी, पथ निर्माण मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि लदनियां और छपकी में, छपकी से पदमा रोड का डी0पी0आर0 बन गया है उसको बनवा दिया जाय ।

उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : जी, लास्ट में एक कविता की एक लाइन बोलकर मैं बैठ जाऊंगी महोदय ।

उपाध्यक्ष : बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है ।

श्रीमती मीना कुमारी : ''इस जग में जितना जुल्म नहीं,
उतने सहने की ताकत है,
लोगों के इस भीड़ में रहकर,
सच कहने की आदत है ।''
मैं सागर से भी गहरी हूं,
तुम कितने कंकड़ फेंकोगे,
मैं चुन–चुन कर आगे बढ़ूंगी,
तुम कब तक मुझको रोकेगे ।''

टर्न–25 / पुलकित / 10.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी । आपके पास चार मिनट का वक्त है ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, पांच मिनट का समय था । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी के संरक्षक माननीय श्री जीतन राम मांझी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी को और हमारे विधान सभा क्षेत्र बाराचट्टी की महान जनता के प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं। मैं आपको आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। आज मैं इस सदन में सिर्फ एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की लाखों आवाजों को लेकर और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राजनीतिक चेतना के साथ वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट पर समर्थन ही नहीं, पूरा पक्ष रखने के लिए खड़ी हुई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। यह बिहार की सोच में आए हुए परिवर्तन का प्रमाण पत्र है। यह बजट उन लोगों को असहज करता है जिनकी राजनीति बिहार को कमजोर दिखाकर चलती थी। जिन्हें डर वाला बिहार चाहिए था, रफ्तार वाला बिहार नहीं। यह बजट न नारों की मिठास पर टिका है, न भावनाओं की बैसाखी पर। यह बजट जमीन पर खड़ा है और जनता के भरोसे पर खरा उतरने वाला बजट है।

मैं पथ निर्माण विभाग पर बोलना चाहूंगी कि अब बिहार रुकता नहीं, दौड़ता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 2005 से पहले बिहार की सबसे बड़ी पीड़ा पूछी जाती तो जवाब सिर्फ एक ही शब्द होता– सड़क। वह दौर था जब बिहार में सफर शुरू करने से पहले लोग दूरी पूछते थे। पूछते थे कि रास्ता कैसा है? बरसात में जाएं या नहीं? दिन में निकलें या सुरक्षित लौट पाएंगे या नहीं? तब दूरी किलोमीटर में नहीं, घंटों, धूल और डर में मापी जाती थी। वर्ष 2005 से पहले सड़कें फाइलों में पक्की और जमीन पर भगवान भरोसे होती थीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने सबसे पहले इसी सोच को तोड़ा। सरकार ने साफ कहा, अब सड़कें राजनीति का विषय नहीं, विकास का साधन बन गई है। आज लक्ष्य बिलकुल स्पष्ट है– बिहार के किसी भी कोने से चार से पांच घंटे में पटना पहुंच जाते हैं और यह कोई सपना नहीं है, यह जमीन पर उतरती हुई सच्चाई है। आज एक्सप्रेस–वे बन रहे हैं, फोरलेन सड़कें बिछ रही हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर खड़े हो रहे हैं। रेलवे ओवरब्रिज जाम तोड़ रहे हैं। नदियों पर पुल दूरी घटा रहे हैं। राघोपुर जाने के लिए घंटों लगते थे, अब पटना से 20 मिनट में राघोपुर पहुंचा जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार, माननीय नीतीश जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया, हमारे विपक्ष के भाई तेजस्वी यादव जी ने यही गरज कर बोला कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है। मैं रात में करीब साढ़े नौ बजे पुल देखने गई, गंगा नदी पर दीघा जेपी सेतु, दीघा ओवरब्रिज देखने गई। मुझे ताज्जुब हुआ, हमने दिल से धन्यवाद दिया, वाह माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी आपने तो इतिहास रच दिया और हमारे तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि काम नहीं हुआ। आप उस जमाने को याद करिए...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती ज्योति देवी : आप उस जमाने को याद करिए कि जिस समय आप अपने विधानसभा में जाते थे, जे0पी0 गंगा पथ 20.5 किलोमीटर का...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करिये । माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी । अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

श्रीमती ज्योति देवी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय दिया जाए, हम थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष : ठीक है । एक मिनट माधव बाबू रूक जाइये ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में कहना चाहती हूं कि हमारा विधानसभा झारखंड से सटा हुआ है। बहुत काम आपने किया है लेकिन वन विभाग की जमीन के चलते लाखों घर, सैकड़ों घर अभी भी रोड और पुल–पुलिया से वंचित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपने गार्जियन, माननीय श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह होगा, पूरी टीम से आग्रह होगा कि उसे कराना चाहिए, कराएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरे भाषण को इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना दें।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री माधव आनंद जी। अपना भाषण प्रारंभ करें।

श्री माधव आनंद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री और जो रोड विभाग के मंत्री हैं श्री दिलीप जायसवाल जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो सड़क से रिलेटेड इस बजट में इतना सारा प्रावधान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हमलोग चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक है विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप वर्ष 2005 से पहले की बात क्यों करते हैं? लेकिन स्वाभाविक है जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो जो पूर्व की सरकारें होती है तो निश्चित रूप से उसका भी आकलन करना होता है। जब 2005 से पहले जब हमलोग देखते थे, मैं मधुबनी से आता हूं सर और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से मैं जीत कर आया हूं। यही मुझे याद है कि वर्ष 2005 से पहले जब मैं मधुबनी जाया करता था, तो पटना से मधुबनी जाने के लिए लगभग पूरे दिन का समय निकालना पड़ता था, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे भी लगते थे। और आज जो है मैं पटना से मधुबनी निकलता हूं, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि तीन से साढ़े तीन घंटे में मैं मधुबनी शहर में पहुंच जाता हूं। यही है काम।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं ।

श्री माधव आनंद : आप शांत रहिये, आप भी फॉर्च्यूनर गाड़ी यूज करते होंगे ।

उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री माधव आनंद : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की प्रगति उस पर डिपेंड करती है कि उसके मुखिया की नीति, नियति और उसकी ईमानदारी क्या है। मुझे याद है वर्ष 2005 से पहले जब हमलोग छात्र हुआ करते थे, उस समय लोग कहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम में और लोग उनसे मांग करते थे कि सड़क बनवाइये तो लालू जी कहते थे कि सड़क बनवाएंगे तो लोग धरना–प्रदर्शन देने पटना आ जाएंगे, इसीलिए उससे अच्छा

है कि सड़क ही न बनवाएं। और एक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं जिनकी सोच, जिनका विचार यह है कि जितना अधिक पुल–पुलिया और सड़क बना दें जिससे लोगों का आवागमन जो है वह आसान हो जाए और लोग इनसे मिल सकें, यही दोनों की नियति में फर्क है ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की प्रगति उसकी सड़कों से मापी जाती है। जहां सड़क पहुंचती है वहां शिक्षा पहुँचती है, स्वास्थ्य पहुँचता है, निवेश पहुँचता है और रोजगार पहुँचता है। हम लोगों ने देखा है कि लोग कहते थे कि शाम के बाद यात्रा मत करो। आज लोग कहते हैं सड़क इतनी अच्छी है कि समय अब आधा हो गया है, अब रात के वक्त भी ट्रेवल करो, कोई दिक्कत बिहार में नहीं है क्योंकि सुशासन बाबू की सरकार है। यह बदलाव एनडीए की सरकार लाई है। इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। खासकर ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण, नए स्टेट हाईवे और बाईपास, पुल–पुलियों का विस्तार, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, आर्थिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, इन सबों के लिए अभूतपूर्व बजट का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी सरकार है और मैं इस अपनी सरकार के माध्यम से स्वाभाविक है कि हमलोगों का भी हक बनता है कि जिस जगह से मैं निर्वाचित हुआ हूँ । वहां की समस्या और वहां के बारे में भी चर्चा करूं ।

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया।

श्री माधव आनंद : उपाध्यक्ष महोदय, बस एक मिनट दिया जाए। यहां पर्यटन मंत्री भी बैठे हुए हैं जो हमारे मधुबनी जिला से ही आते हैं। मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं और मैंने पहले भी आग्रह किया था कि मिनी मिथिला हाट जो है मधुबनी में भी बनना चाहिए, झंझारपुर में बना है ।

उपाध्यक्ष : कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री माधव आनंद : उपाध्यक्ष जी और मेरा इनसे आग्रह होगा कि इसपर विचार करने का काम करें। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय....

उपाध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्या बैठ जाएं । माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य माधव आनंद जी बोल रहे थे कि माननीय लालू प्रसाद जी ने कभी कहा कि सड़क मत बनाओ क्योंकि धरना–प्रदर्शन के लिए लोग आ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कोई ऑथेंटिक बात नहीं, अब सदन में भी जब अफवाह फैलेगी, अफवाह फैलायी जाएगी तो इसका गलत इस्तेमाल होगा।

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोलकर मेरा समय ले रहे हैं ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बहुत सारी बातें हैं, ये बिलकुल अन–ऑथेंटिक बातें सदन में कह रहे हैं, जो व्यक्ति सदन में नहीं है और वह बड़ा नेता है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है । महोदय मैं इसको कंडेम करता हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको दिखवा लिया जाएगा ।

माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

टर्न–26 / हेमन्त / 10.02.2026

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया, शांति बनायें।

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पथ निर्माण विभाग के द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया है। मैं तहेदिल से अपने विधानसभा परिहार के मतदाता मालिकों के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि मुझे तीसरी बार सदन में चुनकर भेजने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की आर्थिक विकास दर भी तेज गति से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। न्याय के साथ विकास भी हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक दशक में बिहार ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को मजबूत किया है। आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। ग्रामीण सड़कों की लम्बाई वर्ष 2015–16 के 64,205 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 1.16 लाख किलोमीटर हो गयी है, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सड़क आधारभूत संरचना को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग दृढसंकल्पित है। विगत वर्षों में राज्य में सड़क आधारभूत संरचना के विकास हेतु बड़े पैमाने पर पथों के चौड़ीकरण एवं पुलों के निर्माण का कार्य किया गया है जिससे राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में काफी सहूलियत हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले, मैं याद दिलाती हूं इन लोगों का, जो हमारे सदस्य लोग बोल रहे थे, बिहार में सड़कों का बुरा हाल था। कहीं अलकतरा घोटाला था, कहीं चारा घोटाला था, कहीं कॉलेज घोटाला था, घोटाला पर घोटाला चल रहा था। जब सुबह को आदमी घर से निकलता था, तो मन में सोचता था, दिल में दर्द होता था कि कहीं रात हो जाय, तो कहां

टिकेंगे। ऐसा 2005 से पहले का बिहार था। आज बिहार में कहीं भी जाइये, आपका रोड कभी बाधित नहीं होता है। आज अधिक से अधिक पांच घंटे में कहीं से भी राजधानी पटना पहुंच सकते हैं। आज कहीं दो–तीन घंटे में आ जा सकते हैं। जिसके लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, श्री नंदकिशोर यादव, श्री नितिन नवीन जी एवं श्री दिलीप जायसवाल जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयास से यह संभव हो सका है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बिहार के विकास में विशेष राशि दी जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य को सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने एवं विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार अर्थात् आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी तथा आदरणीय विजय सिन्हा जी के कुशल नेतृत्व में सड़क, पुल एवं पुल–पुलिया में काफी प्रगति हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा विगत वर्ष में लगभग 38732.54 करोड़ रूपये की कुल 266 पथ एवं पुल परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिससे कुल 23974.97 करोड़ रूपये की 137 परियोजनाएं प्रगति भाग के तहत तथा 14757.57 करोड़ रूपये की कुल 129 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन स्वीकृत योजनाओं में बिहटा से कोईलवर, मुंगेर, बरियारपुर, खोरमपुर से सुल्तानगंज एवं सुल्तानगंज–भागलपुर से सबौर लगभग 118 किलोमीटर गंगा पथ परियोजना को राज्य में प्रथम बार HAM मॉडल पर काम करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए माननीय मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी को धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त सड़क आधार निर्माण में राज्य सरकार की...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अपना भाषण संक्षिप्त करें।

श्रीमती गायत्री देवी : कोशिश में केंद्र सरकार द्वारा भी पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा चार एक्सप्रेस–वे की स्वीकृति दी गयी है। बनारस से कोलकाता, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, रक्सौल से हल्दिया, पटना से पूर्णिया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा राम जानकी पथ के अंतर्गत मशरख से भीठामोड़ की भी स्वीकृति प्रदान की गयी, जो सीतामढ़ी एवं मेरे क्षेत्र परिहार होकर भी गुजरेगी, जिसके लिए आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025–26 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एन0एच0 के विकास हेतु 33,464 करोड़ रूपये की कार्य योजना की स्वीकृति दी गयी है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र परिहार विधान सभा की...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नितेश कुमार सिंह जी।

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, परिहार से भीसवा पथ में खैरवा एवं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट का समय दिया जाय।

उपाध्यक्ष : बोलिये।

श्री नितेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्रीमती गायत्री देवी : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा–सा तो हमें समय दीजियेगा।

उपाध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्रीमती गायत्री देवी : परिहार से भीसवा पथ में खैरवा एवं विष्णुपुर में नाला निर्माण की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आदरणीय दिलीप जायसवाल जी उद्योग मंत्री भी हैं, उनसे आग्रह करती हूं कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए मैं आपके प्रयास की सराहना करती हूं। सीतामढ़ी जिला के परिहार विधानसभा में भी उद्योग लगाने के लिए आपसे आग्रह करती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं खुशनसीब अपने आपको भाग्यशाली समझती हूं कि मैं जानकी जी की जन्म स्थली सीतामढ़ी से आती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर....

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्रीमती गायत्री देवी : एक हजार करोड़ की लागत से बनाने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नितेश कुमार सिंह जी। आपके पास चार मिनट का समय है।

श्री नितेश कुमार सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस सदन में मेरे जीवन में पहली बार बोलने का अवसर दिया है। इस सदन में अपने विधानसभा की बात रखना मेरे लिए गर्व की बात है, साथ–साथ एक जिम्मेदारी भी है। मैं अपनी पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी (आर) का आभार व्यक्त करता हूं जिसने मुझ पर विश्वास किया और इस अवसर पर, मैं आदरणीय स्वर्गीय राम विलास पासवान जी को नमन करता हूं और उनके पूरे राजनीतिक जीवन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्यधारा में जोड़ने का जो विजन समर्पित रहा है, उन्होंने हमेशा कहा कि बिहार को अधिकार भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। यही सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज की उसी विरासत को बढ़ाते हुए, हमारे युवा योद्धा, हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का उल्लेख करना चाहता हूं। उनका यह विजन ''बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'' इसी मंत्र के साथ वह बिहार की राजनीति को एक नई ऊर्जा, नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही, मैं

अपने विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, मेरे जैसे नए व्यक्ति को मौका दिया अपनी बात रखने का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारत का परचम पूरे विश्व में हर क्षेत्र में लहराया। जिनके नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक मजबूती और वैश्विक पहचान तीनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है। इसी तरह मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने राज्य को एक कमजोर राज्य, एक पिछड़े राज्य से यह सफर एक मजबूत, प्रगतिशील और विकसित राज्य की ओर जा रहा है। मेरे जीवन में, मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूं और हमारे उम्र के उस समय जितने भी व्यक्ति होंगे, जब पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जाते थे, जब आप बस में बैठते थे, तो कंडक्टर आपकी ओर आपकी भाषा को देखते हुए एक हीन भावना से देखता था। आप जिस जगह पर रहते थे, वहां जो आपके पड़ोसी होते थे, आप बिहार से आते हैं, तो उनकी जो भावना आपके प्रति होती थी, वह हीन होती थी। हमारे कई ऐसे दोस्त जो कॉलेजेज में, स्पेशली अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में वह यह कहते थे कि मैं गोरखपुर से हूं, इलाहाबाद से हूं, कानपुर से हूं, पर बिहार से कहने में कतराते थे।

(क्रमशः)

टर्न–27 / संगीता / 10.02.2026

श्री नितेश कुमार सिंह (क्रमशः) : उसी दौर में 2005 में ये सरकार यहां की जनता ने एक नई सरकार चुनी और मुझे याद है मैं एक इंटरव्यू मुख्यमंत्री साहब का देख रहा था, करन थापड़ साहब का एक क्वेश्चन था कि You will the last hope for the people of Bihar और उन्होंने बोला कि I took this responsibility और उन्होंने ये रिस्पांसिब्लिटी लिया बिहार के उस जंगल में जहां दिन में जाने में भी लोगों को डर लगता था, उस जंगल में जब एक नया निजाम आता है तो क्या बदलता है, मैं एक कल्पना जो मेरी स्टोरी है वह मैं बताना चाहता हूं । उस जंगल में दिन में जाने में लोगों को डर लगता था, भय लगता था । जब निजाम बदला तो उन्होंने अपने मंत्री अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि आप सुनिश्चित करें जंगल को भयमुक्त करें और जो मंत्रिगण थे, सैनिकगण थे उन्होंने जंगल के उन आदमखोरों को न्यूट्रलाइज किया, कुछ को पिंजरों में डाला और कुछ पालतू हो गए, ऐसे यह जंगल भयमुक्त हुआ । अब जंगल की सरकार की जो अगली कड़ी आती है एक छोर से दूसरे छोर जाने की, इस छोर में सरकार ने सड़क का निर्माण किया और इस सड़क का निर्माण सिर्फ पटना से किसी डिस्ट्रिक्ट तक नहीं रहा, ये हर डिस्ट्रिक्ट से हर प्रखंड तक...

उपाध्यक्ष : आपके पास एक मिनट का वक्त है माननीय सदस्य ।

श्री नितेश कुमार सिंह : हर प्रखंड से हर गांव तक और हर गांव के आखिरी घर तक रहा । मेरा यह करियर सिर्फ 90 दिन का है और मेरे जैसा व्यक्ति अगर 24 दिन में विधायक बनकर आया है तो इसका श्रेय मेरा नहीं है, इसका श्रेय वहां की जनता और इस एन0डी0ए0 सरकार की है और यह कैसे है, यह सरकार कमिटमेंट, डिलिवरी और सेटिस्फेक्शन, ये तीन वर्ड पर ध्यान देती है । ये सिर्फ वादे नहीं करती, उन वादों को पूरा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जनता संतुष्ट रहे । इसी का परिणाम है कि आज एन0डी0ए0 एक ब्रांड है सिर्फ राज्य में ही नहीं पूरे देश में और मैं विपक्ष के साथियों के लिए, हमारी बड़ी बहन श्रीमती मनोरमा देवी जी ने कहा बदलना बहुत जरूरी है । एक कंपनी थी नोकिया अगर याद होगा, नोकिया एक कंपनी थी जिनका यह स्लोगन होता था कनेक्टिंग इंडिया पर उनका एक जो दिक्कत थी वे बदलते नहीं थे । वे बदलते नहीं थे अपने–आप में और आज नोकिया कहां है वही हाल इनका है और देखिए एप्पल भी एक ऐसी कंपनी है जो 90 के दशक में जब वह अपना प्रोडक्ट डिस्कवर कर रहे थे तो उन्होंने ...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य ।

श्री नितेश कुमार सिंह : मैं धन्यवाद देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा ये सरकार आज के डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी में...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं ।

श्री नितेश कुमार सिंह : वह एप्पल फोन है जो किसी भी नोकिया को, यानी 20 सालों में 30 सालों में पीछे छोड़कर रखेगी । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजू कुमार सिंह जी, आपके पास में 5 मिनट का वक्त है ।

श्री राजू कुमार सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सड़क निर्माण विभाग के अनुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सबसे पहले साहेबगंज विधान सभा के तमाम महान कार्यकर्ता और सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पांचवीं बार मुझे इस सदन में भेजकर के आपके सामने इस सदन के सामने कुछ बोलने का मौका दिया । साथ ही सदन के नेता को बधाई देना चाहूंगा माननीय नीतीश कुमार जी को और अपने द्वय उपमुख्यमंत्री जी और पथ निर्माण विभाग के मंत्री मान्यवर श्री दिलीप जायसवाल जी को । आज जिस पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं सब जानते हैं कि सड़क राज्य की नींव होती है । सड़क से ही राज्य की पहचान बनती है । मैं साहेबगंज विधान सभा का प्रतिनिधित्व करते हुए पथ निर्माण विभाग की इस महत्वपूर्ण अनुदान की पूरे मनोयोग से समर्थन करता हूं । सड़क केवल दाम और मिट्टी और गिट्टी का ढांचा नहीं होती सड़क किसी भी राज्य के विकास की जीवन रेखा होती है । जहां सड़क पहुंचती है वहां शिक्षा पहुंचती है, जहां सड़क पहुंचती है वहां स्वास्थ्य पहुंचता है, वहां बाजार पहुंचता है और निवेश पहुंचता है । सबसे

महत्वपूर्ण सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है । अगर किसी राज्य की प्रगति को परखना हो तो उनके भवनों को मत देखिए, उनकी इमारतों को मत देखिए उनकी सड़कों को देखिए तब जाकर पता चलता है कि राज्य की उन्नति और प्रगति क्या है । रास्ते अगर मजबूत हों तो मंजिलें खुद करीब आ जाती हैं और नियत अगर साफ हो तो तस्वीरें भी बदल जाती हैं । उपाध्यक्ष महोदय, एक समय था जब बिहार की पहचान टूटी सड़कों, गड्ढ़ों और कीचड़ों से होती थी आज वही बिहार मजबूत चौड़ी सर्वऋतु योग्य सड़कों के नेटवर्क से जुड़ चुका है । वर्ष 2005 की बातें अगर याद करें तो वर्ष 2005 में आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे यहां राज्य के पथ निर्माण विभाग के सड़कों का कितना किलोमीटर का जाल बिछा था और आज गुणात्मक वृद्धि होते हुए कई गुणा वृद्धि होकर के आज राज्य में पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया गया वह अति स्वागतयोग्य है । जो अभी लगभग 26 हजार किलोमीटर के आसपास हो चुकी है । राजमार्गों का बड़े पैमाने पर चौड़ीकरण हुआ है । जिला सड़कों का सुदृढ़ और सर्वऋतु योग्य बनाया गया है, हजारों पुल–पुलियों का निर्माण हुआ, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ा गया है । यह परिवर्तन अपने आप नहीं आया यह सड़क निर्माण विभाग के निरंतर कार्यशैली और सरकार की स्पष्ट नीति का परिणाम है । पहले सफर में धूल थी अब रफ्तार की शान है, यह बदला हुआ बिहार और यही विकास की पहचान है । उपाध्यक्ष महोदय, पहले सड़क नहीं था तो गाड़ी भी सीमित थी, अब अच्छी सड़कें बनने के साथ ही अच्छी महंगी गाड़ियां भी सड़कों पर दिखाई देती हैं । मुझे याद है जब मैं 2004 में एन0आर0आई0 रहते हुए मुझे चुनाव लड़ने का जब इच्छा हुई थी तब 2004 मैं बिहार की सड़कों पर आया था तो मेरे पास उस समय में दिल्ली के अंदर मेरी एक गाड़ी थी ऑडी–Q7 उसको लेकर जब मैं यहां आया था तो मैं पटना से अपने घर तक सही से नहीं पहुंच पाता था और वहां जाने में भी 3 घंटा से ज्यादा समय लगता था । आज वही बिहार है कि 1 घंटा 10 में मैं यहां से अपने घर पहुंच जाता हूं 1 घंटा 10 मिनट, 15 मिनट में पहुंच जाता हूं, यही अंतर है...

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

यही अंतर आया है सड़क बनने के कारण हुआ है शंकर जी आप भी जानते हैं, 1 घंटा 10 मिनट में ही । आपको नहीं भूलना चाहिए आप भी उन्हीं सड़कों पर चला करते थे । अध्यक्ष महोदय, बिहार नदियों का प्रदेश है । यहां सड़क बनाना ही पर्याप्त नहीं होता है, हर कुछ किलोमीटर पर पुल और पथों का संतुलन बनाना पड़ता है इसलिए हजारों नए पुल–पुलियों का निर्माण हुआ जिससे उनका संपर्क वर्षभर बना रहे । बारिस के समय में आवागमन बाधित न हो व्यापार और यातायात सुचारू रहे आज पुलों की गुणवत्ता जांचने के लिए

आई0आई0टी0 जैसे संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा है । यह दर्शाता है कि सरकार केवल निर्माण नहीं कर रही, गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है । अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ है । हर वर्ष कोशी, गंडक, बागमती जैसी नदियां सड़क व्यवस्था की परीक्षा लेती हैं । इसी को ध्यान में रखते हुए ऊंचे स्तर पर सड़कों का निर्माण, पी0सी0सी0 सड़क का सुदृढ़ जाल, जल निकासी प्रणाली, अधिक पुल–पुलियों का निर्माण, आपदारोधी सड़क डिजाइन यानी सड़क केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनायी जा रही हैं जो हर साल बाढ़ से लड़ता है वही सड़क की कीमत जानता है कागज पर बोलने वाला दर्द कहां से पहचानता है । अध्यक्ष महोदय, राज्य और राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार के लिए हजारों करोड़ रुपयों का निवेश किया जा रहा है कई सड़कों को दो लेन और चार लेन में बदला जा रहा है । ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रख–रखाव के लिए व्यापक बजट, आधुनिक तकनीकी से सड़क निर्माण, बाहरी तकनीकी सहयोग और संस्थागत समर्थन यह दर्शाता है कि सड़क निर्माण विभाग केवल खर्च नहीं कर रहा बिहार के भविष्य के लिए दीर्घकालीन निवेश कर रहा है । अध्यक्ष महोदय, सड़क का सबसे बड़ा लाभ गांव और किसान को मिलता है, किसान का अनाज बाजार तक जल्दी पहुंचता है, छात्रों को स्कूल और कॉलेज जाने में सुविधा होती है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राजू कुमार सिंह : मरीजों को अस्पताल पहुंचने में समय नहीं लगता...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय समाप्त हुआ ।

श्री राजू कुमार सिंह : छोटे व्यापारियों की आय बढ़ती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तीकरण है । राज्य में कुल 1030 किलोमीटर का हाई–स्पीड कॉरीडोर नेटवर्क से विकसित बिहार का संकल्प पूरा हो रहा है । सरकार द्वारा इस हाई–स्पीड कॉरीडोर के विकास हेतु, आप समझ सकते हैं अध्यक्ष महोदय, जब हमलोग 2005 में बिहार विधान सभा में आए थे उस समय बिहार का बजट जहां मात्र 22 हजार करोड़ का हुआ करती थी आज पथ निर्माण विभाग केवल बिहार राज्य के हाई स्पीड कॉरीडोर के लिए 48 हजार 212 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है...

अध्यक्ष : आप कन्क्लूड कर लीजिए ।

श्री राजू कुमार सिंह : यह सरकार की विशेषता है । मैं विशेष करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा । दो–चार मिनट में, एक मिनट में महोदय, एक मिनट में ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राजू कुमार सिंह : मैं ग्रीनफील्ड हाइवे के बारे में नहीं बता पाया था लेकिन सरकार के समर्थन में मैं अपने पक्ष को रखा हूं । बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं । हमने वादे नहीं रास्ते बनाये हैं और इन रास्तों पर बिहार को आगे बढ़ाया है । अध्यक्ष

महोदय, साथ ही माननीय मंत्री जी से एक मिनटों में एक सहयोग और समर्थन की आशा के साथ मैं अपना विचार–विमर्श रख रहा हूं । माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के लगभग सारे जिले में आपने पथ निर्माण का सड़क पहुंचा दिया है ।

(क्रमशः)

टर्न–28 / यानपति / 10.02.2026

(क्रमशः)

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, सारे जिले पथ निर्माण की सड़कों से आच्छादित हो चुके हैं लेकिन उन जिलों में कहीं न कहीं कुछ परेशानियां आती हैं, सारे जगहों पर आपका रिंग रोड नहीं बन पाया है इसलिए मेरा आग्रह होगा कि उन जिलों में रिंगरोड जरूर बनवाया जाय । उसी के साथ हमारे साहेबगंज में भी एक रिंग रोड की आवश्यकता है इसलिए साहेबगंज के लिए भी आपसे एक रिंग रोड की मांग की है और साथ ही चंपारण और गोपालगंज को जोड़नेवाली डुमरिया घाट का पुल काफी दिनों से पड़ा हुआ है, वह बनना जनहित में अत्यंत ही आवश्यक है और अपनी बात को खत्म करते हुए एक लाइन में कहना चाहूंगा, सड़क की यही दशा थी, हमारे चंपारण के साथी भी यहां बैठे हुए हैं । 2009 में मेरी धर्मपत्नी चंपारण से एम0एल0सी0 हुआ करती थीं और जब वहां घोड़ासाहन से या सीमावर्ती इलाकों से लोग मेरे यहां पहुंचते थे तो रात को बस पकड़ते थे और सुबह मेरे घर पर पहुंच पाते थे जैसा कि आज पटना से दिल्ली जाने के लोग लिए सोचते हैं । आज क्या व्यवस्था है, सुबह चलते हैं यहां पर मिलकर काम करा के फिर शाम को लौट जाते हैं । यही सरकार की सड़क में बदलाव आया है । मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए पक्ष में मैं अपना समर्थन प्रकट करता हूं और अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रेषित करता हूं । जय हिंद, जय बिहार, जय साहेबगंज की जनता ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

आप अलग से लिखकर दे दीजिएगा । हो जायेगा, लिखकर दे दीजिएगा ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वित्तीय वर्ष 2026–27 के आलोक में सम्मिलित अनुदान की मांग में जो माननीय सदस्य ने भाग लिया और अपना बहुमूल्य सुझाव दिया उन सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं । श्री प्रमोद कुमार जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, श्री राजू तिवारी

जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, डॉ0 प्रकाश चंद्र जी, श्रीमती मीना कुमार जी, श्रीमती ज्योति देवी जी, श्रीमती गायत्री देवी जी, श्री माधव आनंद जी , श्री नीतेश कुमार सिंह जी, श्री राजू कुमार सिंह जी और विपक्ष के हमारे साथी श्री सुरेंद्र राम जी, श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्री सतीश कुमार सिंह जी, श्रीमती अनीता जी सभी सदस्यों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं । मो0 कमरूल होदा साहब...

(व्यवधान)

असल, आप दिल में रहते हैं इसीलिए जबान पर नाम नहीं, मो0 मुर्शिद आलम साहब और श्री सतीश कुमार सिंह जी आप सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मिला–जुलाकर पथ निर्माण विभाग के कार्य की सराहना और समर्थन किया । बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए पथ निर्माण विभाग दृढ़संकल्पित है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने के लिए पथ निर्माण विभाग राज्य में आधारभूत संरचना का विकास लगातार कर रही है । मैं साथ ही बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री विजय सिन्हा जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी के साथ कदम में कदम मिलाकर बिहार के विकास की चिंता कर रहे हैं । महोदय, पथ निर्माण विभाग अब राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही राज्य की आम जनता के जीवन को आसान बनाने हेतु राज्य अंतर्गत आवागमन को सुगम बना रही है । इस हेतु पथ निर्माण विभाग एक साथ कई प्रकार की योजनाओं यथा सड़कों के चौड़ीकरण, नदियों पर पुलों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, रेलवे ऊपरी पुल एवं रेलवे अंडर ब्रिज का निर्माण इत्यादि का क्रियान्वयन एक साथ कर रही है । महोदय, श्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के संकल्प के अनुरूप सड़क, आधारभूत संरचना का विकास राज्य के अंदर सुनिश्चित किया जा रहा है । संरचना का विकास राज्य के अंदर सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेवारी है । गत वर्ष सदन को अवगत कराया गया था कि विगत बीस वर्षों से पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य में अनवरत सड़कों एवं पुल–पुलियों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ ही इनके उत्कृष्ट संधारण से राज्य की आम जनता को लगातार लाभ प्राप्त हो रहे हैं । अब इसे और सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निश्चय किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है ताकि राज्य की जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन में न्यूनतम समय लगे तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सके । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के

द्वारा विगत वर्ष की गई प्रगति यात्रा के क्रम में कुल 23974 करोड़ 97 लाख की लागत पर 137 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी । मुझे सदन को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इन स्वीकृत योजनाओं में से 111 योजनाओं का कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है एवं आवंटित सभी योजनाओं का कार्य प्रगति में है । मार्च, 2026 तक शेष योजनाओं का कार्य शीघ्र आवंटित करते हुए इनके कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का लक्ष्य है । इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के चहुंमुखी विकास की गति में और अधिक तेजी आयेगी । इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग द्वारा विगत एक वर्ष में लगभग 14757 करोड़ 57 लाख रुपये की कुल 129 अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है । महोदय, राज्य की अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना जे0पी0 गंगा पथ का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है एवं इस पथ पर आवागमन सुगम है । अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पश्चिम में दीघा–बिहटा–कोईलवर, लंबाई–35.65 कि0मी0 तक एवं पूरब में मुंगेर (सफियाबाद)– बरियारपुर – घोरघट – सुल्तानगंज, लंबाई 42 कि0मी0 एवं सुल्तानगंज–भागलपुर–सबौर, लंबाई–40.80 कि0मी0 तक गंगा पथ को विस्तारित करने के लिए कुल 16465 करोड़ 42 लाख रुपये की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है और काम भी अब शुरू हो रहा है । राज्य में प्रथम बार इन परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) प्रोजेक्ट पर क्रियान्वित कराने का निर्णय लिया गया है । निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया गया है । इस नवाचार से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 5 घंटे में राज्य के सुदूर स्थान से राजधानी पटना पहुंचने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है । साथ ही राज्य के सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, औद्योगिक स्थानों तथा क्षेत्रों का हर जगह से सुलभ संपर्कता सुनिश्चित करने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के अंतर्गत किया जा रहा है । महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य में सड़कों का भी डबल विकास हो रहा है । महोदय, जहां एक ओर केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 4–लेन एवं 6–लेन हाई स्पीड कोरिडोर एवं एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार ने भी राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए अपना लक्ष्य सामने रखा है । इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय–3 ''सुलभ संपर्कता का विस्तार अंतर्गत नये एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण'' के तहत राज्य में इसके निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जा चुका है, जो देश के अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र

एवं उत्तर प्रदेश, जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, का विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करेगा । यह टीम महाराष्ट्र का दौरा कर भी चुकी है। समिति द्वारा भ्रमण कर अध्ययन का कार्य प्रगति पर है । साथ ही राज्य के सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को 4–लेन संपर्कता प्रदान करने की योजना पर भी विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है । महोदय, रेल समपारों पर घंटों यातायात जाम की समस्या बनी रहती थी ।

(क्रमशः)

टर्न–29 / मुकुल / 10.02.2026

क्रमशः

डाॅ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : पूरे बिहार में रेलवे गेट के पास लगातार जब फाटक रेल का गिर जाता था तो जाम की समस्या बनती थी परंतु विगत वर्षों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा राज्य के प्रमुख रेल समपारों पर रेलवे ऊपरी पुल एवं रेलवे अंडरब्रिज की योजना का क्रियान्वयन किया गया है । अब तक राज्य में 44 रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि 56 रेलवे ऊपरी पुल का कार्य प्रगति में है । वर्तमान में राज्य में निर्बाध, सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के अंदर लगभग सभी रेल समपारों पर जहां–जहां भी रेलवे का गेट पास है, समपारों पर रेलवे ऊपरी पुल एवं रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण की योजना का कार्य किया जा रहा है । महोदय, राज्य को सड़क आधारभूत संरचना में समृद्ध बनाने हेतु राज्य सरकार की कोशिश में भारत सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है । केन्द्र सरकार के द्वारा भी राज्य में एक्सप्रेस वे, 4–लेन एवं 6–लेन पथों के निर्माण की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे आने वाले वर्षों में राज्य अन्तर्गत कई हाई स्पीड कोरिडोर उपलब्ध होगी । वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा राज्य में वाराणसी–रांची–कोलकाता एक्सप्रेसवे, कुल 07 पैकेज और 10 हजार 862 करोड़ 63 लाख रुपया में इसका जो है 121.70 कि0मी0 और कार्य प्रगति में तथा शेष पथांशों का भी भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है । दूसरा गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, लम्बाई–416 कि0मी0 23 हजार 434 करोड़ रुपया । अखतरूल भाई हमारे सुन रहे होंगे, हमारे सभी ए0आई0एम0आई0एम0 के जितने भी विधायक हैं उनके गांव–गांव से यह रोड निकलेगा और 23 हजार 434 करोड़ रुपया इसपर खर्च किया जायेगा । पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे, लम्बाई–245 कि0मी0, पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे 245 कि0मी0 और लागत 18 हजार 242 करोड़ । अब अखतरूल भाई को जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी । पटना–पूर्णिया एक्सप्रेसवे 245 कि0मी0, 18 हजार 242 करोड़ रुपया में बनाया जा रहा है । रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे, भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है । बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे, विस्तृत

परियोजना प्रतिवेदन, डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है । अब आप सोचिए जब बक्सर से भागलपुर यह एक्सप्रेस वे चलेगा तो बीच के सभी जिला को इस एक्सप्रेस वे का फायदा मिलेगा । महोदय, राज्य को सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समृद्ध होने से आम जन–जीवन आसान होगा । राज्य के आम जनता को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित होगी तथा राज्य को आर्थिक तरक्की में और भी रफ्तार मिलेगी । कृषि उत्पादों का बाजारों/उपभोक्ताओं तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा रोजगार के सृजन में काफी बढ़ोतरी होगी । महोदय, अब मैं विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों से माननीय सदस्यों को पथ श्रेणीवार तथा योजना प्रक्षेत्रवार अवगत कराना चाहूंगा । राष्ट्रीय उच्च पथ, महोदय, बिहार राज्य के अंतर्गत वर्तमान में कुल 6392 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथ है, जिसमें 3784 कि0मी0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं 2608 कि0मी0 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन है । भारत सरकार के द्वारा राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथों के चौड़ीकरण के साथ–साथ नये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं हाई स्पीड कोरिडोर के निर्माण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा रही है । महोदय, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत लगभग 50 हजार 711 करोड़ की राशि से 75 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से 51 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 21 परियोजना जो प्रधानमंत्री जी का पैकेज था 50 हजार 711 करोड़ का 21 परियोजना का कार्य प्रगति में है तथा 3 परियोजना निविदा एवं भू–अर्जन कार्य विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है । महोदय, राज्य में कुल 1817 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथ 4–लेन एवं 6–लेन में निर्मित है एवं लगभग 1463 कि0मी0 विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथों का 2–लेन, 4–लेन एवं 6–लेन में निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त राज्य में राजधानी पटना से सभी दिशाओं के लिए 4–लेन सम्पर्कता उपलब्ध हो जायेगा । भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय उच्च पथ के महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं के बारे में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा । आमस–दरभंगा, गया के लोग भी होंगे, दरभंगा के लोग भी होंगे । आमस–दरभंगा परियोजना के 4 पैकेज का निर्माण कार्य प्रगति में है और 6 हजार 21 करोड़ 62 लाख रुपया से आमस–दरभंगा रोड बनाया जा रहा है । राष्ट्रीय उच्च पथ के 4–लेनिंग के तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी तक प्राक्कलित राशि 5 हजार 885 करोड़ 58 लाख एवं किशनगंज से बहादुरगंज पथ प्राक्कलित राशि 982 करोड़ 47 लाख रुपये का निर्माण कार्य बहुत ही तेजी से और प्रगति में है तथा बख्तियारपुर–मोकामा पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है । राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–327ई के अररिया–परसरमा पथ जो 1 हजार 547 करोड़ 55 लाख के 2–लेन के साथ पेभ्डसोलजर निर्माण कार्य हेतु निविदा की

कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो हम तुरंत शुरू करने जा रहे हैं, अररिया–परसरमा पथ । वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे के चार पैकेज 10 हजार 862 करोड़ 63 लाख और बिहार के अंदर भू–अर्जन का कार्य प्रगति पर है । राज्य सरकार के विभिन्न स्तर से राष्ट्रीय उच्च पथ के मेगा परियोजना में भू–अर्जन तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित मुद्दों का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है । केन्द्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को भी मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलिए ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : थोड़ा देर और सुन लीजिए, उसके बाद चले जाइयेगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात सब है । केन्द्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजना पटना रिंग रोड, 4 हजार 250 करोड़, मार्गरेखन पर गंगा नदी पर शेरपुर–दीघवारा के बीच 6–लेन सेतु निर्माण कार्य प्रगति में है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति–शांति । शांति बनाए रखें ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : पटना जिलान्तर्गत दानापुर–बिहटा ऐलिवेटेड पथ 2980 करोड़ रुपया का कार्य प्रगति पर है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाए रखें ।

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : मधुबनी जिलान्तर्गत, अगर आप बैठते तो मैं एक–एक बात का जवाब देता । आप अगर जवाब सुनना चाहते हैं तो बैठिए, एक–एक बात का मैं चुन–चुनकर जवाब दूंगा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत भेजा–बकौर के बीच कोशी नदी पर पुल, 1 हजार 199 करोड़ । सिवान जिलान्तर्गत मेहरौना–सीवान पथ एवं सिवान–मशरख पथ, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि मधुबनी जिलान्तर्गत भेजा–बकौर के बीच कोशी नदी पर पुल 1 हजार 199 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है । सिवान जिलान्तर्गत मेहरौना–सीवान पथ एवं सीवान–मशरख पथ (राम जानकी मार्ग) 3 हजार 92 करोड़ 61 लाख का निर्माण कार्य प्रगति पर है । गंगा नदी पर जे0पी0 सेतु के समानान्तर 6–लेन पुल 3 हजार 5 करोड़ 80 लाख रुपये का निर्माण कार्य प्रगति पर है । जे0पी0 सेतु के ऊपर एक समानान्तर 6–लेन पुल और बन रहा है, आपलोग एकदम सीधा निकलेंगे और उस पार चले जायेंगे ।

क्रमशः

टर्न–30 / सुरज / 10.02.2026

(क्रमशः)

डॉ0 दिलीप जायसवाल, मंत्री : महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल, जे0पी0 सेतु के समानान्तर तो 6–लेन पुल और महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल 2 हजार 926 करोड़ का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु के समानान्तर, जो भागलपुर, नवगछिया के लोग होंगे उनको पता होगा कि भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल 01 हजार 110 करोड़ 23 लाख का निर्माण कार्य प्रगति में है ।

माननीय तारकिशोर जी हैं अभी यहां पर । कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी–साहेबगंज के बीच गंगा नदी का पुल 01 हजार 9 सौ करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 पैकेज में कार्य प्रगति पर है जो 10 हजार 862 करोड़ रुपया की लागत से बन रहा है ।

महोदय, राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ का घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफी कम है । पशुपतिनाथ–बैद्यनाथ, जरा ध्यान देंगे गोपाल अग्रवाल जी मुस्कुरा रहे हैं । पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ यानी एकदम नेपाल के बार्डर से बाल्मिकी नगर से और उधर पशुपतिनाथ के रास्ते से सीधा वैद्यनाथ धाम तक हम 4–लेन रोड ले जा रहे हैं और इसका स्पीड कॉरिडोर हम बनाने जा रहे हैं और इसके साथ–साथ करीब 250 कि0मी0 का यह रोड होगा और इससे खगड़िया को, बीच में सहरसा को, आगें सुल्तानगंज को जब ये रोड जायेगा पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ तो आपलोगों को कितना आनंद मिलेगा माननीय सदस्य को माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इसको यहां बता नहीं सकता हूं । उसके बाद नारायणी–गंगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 225 कि0मी0, बगहा एन0एच0–727A से पातर तक भोजपुर जिला तक जायेगा । सीधे नारायणी से गंगा यानी बगहा से लेकर सीधे संजय टाइगर जी होंगे यहां पर, हां हैं और आगे आनंद मिश्रा जी भी हैं बक्सर तक यह ग्रीनफील्ड कोरिडोर जाने वाला है और इस तरह पूरे बिहार को किस तरह से सुगम आवागमन किया जाए इसके लिये 4–लेन और 6–लेन की स्वीकृति सरकार ने दे दी है और इस पर हम आगे बढ़ चुके हैं ।

माननीय सदस्य, पशुपतिनाथ–बैद्यनाथ कोरिडोर–नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से बैद्यनाथ धाम झारखंड तक प्रस्तावित है जो राज्य में पसराहा, अगुवानी घाट, सुल्तानगंज, कटोरिया, चानन से होकर गुजरेगा ।

नारायणी गंगा कोरिडोर बनने से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिला को त्वरित संपर्कता मिल पायेगा ।

अब मैं राज्य उच्च पथ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल भी उठाया था कि राज्य के सभी राज्य उच्च पथों को कम से कम 2–लेन मानक संरचना में उन्नयन करने का लक्ष्य है । इस लक्ष्य के तहत 3617 कि0मी0 राज्य उच्च पथों में से 3100 कि0मी0 का 2–लेन अथवा 4–लेन में उन्नयन किया जा चुका है तथा लगभग 314 कि0मी0 के चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है ।

एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से कुल 1830 कि0मी0 राज्य उच्च पथों का 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है और लगभग 314 कि0मी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

वित्त पोषण अंतर्गत सभी 6 राज्य उच्च पथ मानसी–सिमरी बख्तियारपुर । खगड़िया और मानसी के कोई अगर माननीय सदस्य होंगे और सलखुआ आपका तो जन्म स्थान है माननीय तारकिशोर जी का । मानसी से सिमरी बख्तियारपुर (एस0एच0–95), कटिहार से बलरामपुर । माननीय सदस्य को कितना आनंद का अनुभव हो रहा होगा मैं थोड़ा देखना भी चाहता हूं । सरिता जी का चेहरा कितना खिला है । कटिहार से बलरामपुर पथ, वायसी–बहादुरगंज–दीघलबैंक पथ बेतिया–नरकटियागंज पथ, अम्बा–देव–मदनपुर पथ एवं मंझवे–गोविन्दपुर पथ और कुल लंबाई 266 कि0मी0 का 02 हजार 680 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य प्रगति में है ।

महोदय, फेज–1 के अंतर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से 02 हजार 09 सौ करोड़ 88 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 04 पथ यानी कुल लंबाई–225.48 कि0मी0 और एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निम्नवत है :

नवादा एवं गया जिलान्तर्गत बनगंगा–जेठियन–गहलौत–भिन्डस (एन0एच0–82) पथ (लंबाई–41.256 कि0मी0, लागत–रु0 361.325 करोड़)

बांका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत धोरैया–इंगलिस मोड़–असरगंज पथ (लंबाई–58.473 कि0मी0, लागत–रु0 650.51 करोड़)

सारण एवं सिवान जिलान्तर्गत छपरा–मांझी–दरौली–गुठनी पथ (लंबाई–72.183 कि0मी0, लागत–701.26 करोड़)

भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–एकौना–खैरा–सहार पथ लंबाई–33 कि0मी0, लागत–373.56 करोड़ की लागत से

मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हथौड़ी–औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल का पहुंच पथ का निर्माण कार्य हमलोग 814 करोड़ की लागत से कर रहे हैं ।

इन परियोजनाओं का कार्य संवेदक को आवंटित कर दिया गया है और जल्द ही कार्य शुरू हो रहा है ।

महोदय, वित्त पोषण से कुल 03 हजार 743 करोड़ 65 लाख की अनुमानित लागत से 03 राज्य उच्च पथों एवं 02 वृहद जिला पथों कुल लंबाई–266 कि0मी0 के उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

सुपौल एवं अररिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–92 माननीय सदस्य देवंती जी होंगी गणपतगंज–परवाहा पथ, लंबाई–47 कि0मी0 लागत 703 करोड़ की लागत से ।

आदरणीय बिजेन्द्र बाबू जी को भी धन्यवाद है । सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–52 सीतामढ़ी–पुपरी–बेनीपट्टी पथ, 52 कि0मी0 के आसपास 434 करोड़ की लागत से बनेगा ।

दरभंगा एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–97 जीवेश जी नहीं हैं । अतरबेल–जाले–घोघरचट्टी पथ जो करीब 48 कि0मी0, है 990 करोड़ की लागत से बनेगा । मैं चाहता हूं सभी लोग प्रश्न हों उस ख्याल से मैं बोल रहा हूं ।

अब मैं मधुबनी पर आ रहा हूं । मधुबनी जिला अंतर्गत मधुबनी–राजनगर–बाबू बरही–खुटौना पथ, लंबाई करीब 39 कि0मी0 लागत–632 करोड़ रुपया ।

बक्सर जिला अंतर्गत इटाढ़ी–सरंजा–जलीलपुर पथ तथा इटाढ़ी–बक्सर संपर्क मार्ग एवं उजियारपुर समदा संपर्क मार्ग 80 कि0मी0, 982 करोड़ की लागत से बनेगा ।

(क्रमशः)

टर्न–31 / धिरेन्द्र / 10.02.2026

...क्रमशः...

डॉ॰ दिलीप जायसवाल, मंत्री : महोदय, राज्य अंतर्गत राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई लगभग 3000 कि॰मी॰ नये राज्य उच्च पथों की घोषणा हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है । माननीय सदस्यों की यह मांग रहती है कि आप राज्य उच्च पथ में इसकी घोषणा कर दें तो हमलोग करीब 3000 किलोमीटर नये राज्य पथ स्टेट हाइवे के घोषणा की विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं ।

वृहद जिला पथ, अब मैं जिला में आता हूँ । महोदय, पथ निर्माण विभाग के अधीन वर्तमान में कुल 16784 कि॰मी॰ वृहद जिला पथ है, जिसमें से 5343 किलोमीटर सिंगल लेन है । वर्तमान में लगभग 2000 कि॰मी॰ के उन्नयन कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है ।

सात निश्चय पार्ट–3, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ''सुलभ संपर्कता का विस्तार–ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2–लेन चौड़ीकरण करना'' हमारा लक्ष्य है और इसके तहत ग्रामीण सड़कों का 2–लेन में

चौड़ीकरण का निश्चय किया गया है । महोदय, ग्रामीण सड़कों के 2–लेन में चौड़ीकरण को पूर्ण उपयोगी बनाये जाने हेतु यह आवश्यक है कि पथ निर्माण विभाग की सभी सड़कें कम–से–कम 2–लेन चौड़े अवश्य हों । अतः पथ निर्माण विभाग की सभी सिंगल लेन पथों को 2–लेन में चरणबद्ध तरीके से चौड़ीकरण किया जायेगा ।

सात निश्चय पार्ट–2 में सुलभ सम्पर्कता बाईपास और एलिवेटेड पथ के बारे में मैं बताता हूँ । महोदय, राज्य में सुगम एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु सात निश्चिय पार्ट–2, सुलभ संपर्कता के तहत राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर के निर्माण योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 08 बाईपास 143 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 12 बाईपास 412 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2023–24 में कुल 05 बाईपास 412 करोड़ रुपये, वर्ष 2024–25 में कुल 19 बाईपास 1921 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2025–26 में कुल 06 बाईपास 166 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई । इस प्रकार कुल 50 बाईपास योजनाओं में से अब तक 17 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 18 योजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है । शेष 15 बाईपास योजनाएं निविदा निष्पादन के प्रक्रियाधीन है जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को भेज दी जायेगी ।

नाबार्ड संपोषित–महोदय, राज्य के चहुँमुखी विकास को दृष्टिपथ रखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र एवं सुगम बनाने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड ऋण योजनांतर्गत 106 पथ एवं पुल परियोजनाओं का 3342 करोड़ 54 लाख की लागत से क्रियान्वयन करने हेतु विभिन्न चरणें में हम प्रगतिशील है ।

यू॰आई॰डी॰एफ॰ संपोषित, 07 मिनट बहुत है । महोदय, राज्य अंतर्गत सड़क आधारभूत संरचना की समृद्धि हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा 1973 करोड़ 55 लाख की लागत से क्रियान्वयन विभिन्न चरणें में प्रगतिशील है और उसी तरह 199 कि॰मी॰ पथों का उन्नयन कार्य प्रगति में है और जिसका मैं विस्तृत बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के नजदीक 69 करोड़ रुपये का कार्य प्रगति में है । सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज विशुनपुरा बाईपास पथ 228 करोड़ भू–अर्जन कार्य प्रक्रियाधीन है । सारण जिला अंतर्गत अमनौर बाजार बाईपास पथ 69 करोड़ कार्य प्रगति में है । सारण जिला अंतर्गत गरखा बाईपास पथ 91 करोड़ कार्य प्रगति में है । सारण जिला अंतर्गत परसा बाजार बाईपास पथ 85 करोड़ कार्य प्रगति में है । बिहार–झारखण्ड की सीमा पर रोहतास जिलान्तर्गत पण्डुका के पास सोन नदी पर 210 करोड़ की लागत से 1500 मीटर लम्बे उच्च स्तरीय आर॰सी॰सी॰ पुल

का निर्माण कार्य प्रगति में है और इसके साथ–साथ 15 आर॰ओ॰बी॰ 669 करोड़ की राज्यांश की स्वीकृति प्रदान की गई है और विशेषकर जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर हमलोग राज्य के आठ जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, जमुई, रोहतास, लखीसराय एवं मुजफ्फरपुर में 153 पथ पैकेज कुल 1980 किलोमीटर की लंबाई एवं 82 पुल पैकेज के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इन योजनाओं की पथ संधारण सहित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 3181 करोड़ मात्र है जिसमें केंद्रांश 1390 करोड़ एवं राज्यांश की राशि 1791 करोड़ है । वर्तमान में 130 पथों यानी 1813 किलोमीटर एवं 72 पुलों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसके साथ–साथ 19 पथों की लंबाई 109 किलोमीटर और 06 पुलों का काम प्रगति पर है । भारत–नेपाल सीमा परियोजना अंतर्गत बिहार राज्य में कुल 554 किलोमीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है । यह परियोजना पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज से होकर गुजरता है और पश्चिमी चम्पारण के मदनपुर से आरंभ होकर किशनगंज जिला के गलगलिया में समाप्त होता है और इसके साथ–साथ 132 उच्चस्तरीय पुलों के निर्माण कार्य का भी निधि स्वीकृत किया जा रहा है । वर्तमान में 519 किलोमीटर पथ एवं 121 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । मैं आर॰ओ॰बी॰ के बारे में बताना चाहूँगा कि रेलवे ओवर ब्रिज के बारे में भागलपुर में मिरजान हाट के नजदीक, पटना जिलांतर्गत बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, नालंदा जिलांतर्गत हरनौत रेल फैक्ट्री से निकट, नवादा बाईपास अंतर्गत समपार संख्या–28ए॰/टी॰ पर आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण, हिलसा बाईपास अंतर्गत समपार संख्या–18 एवं 23 पर आर॰ओ॰बी॰ का निर्माण । प्रमुख नदियों पर पुल का निर्माण– बक्सर में गंगा नदी पर 2–लेन पुल, आरा–छपरा के बीच गंगा नदी पर 4–लेन पुल, दीघा–सोनपुर रेल–सह–सड़क पर 2–लेन पुल, महात्मा गांधी सेतु 4–लेन पुल, मोकामा में रेल–सह–सड़क 2–लेन पुल (राजेन्द्र सेतु), मुंगेर में रेल–सह–सड़क सेतु 2–लेन (श्री कृष्ण सेतु), भागलपुर में विक्रमशीला सेतु 2–लेन, औंटा–सिमरिया के बीच 6–लेन पुल । गंगा नदी पर दीघवारा–शेरपुर के बीच 6–लेन पुल, जे॰पी॰ सेतु के समानान्तर 6–लेन पुल, महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4–लेन पुल , कच्चीदरगाह–बिदुपुर के बीच 6–लेन पुल, बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच 4–लेन पुल, अगुवानीघाट–सुल्तानगंज के बीच 4–लेन पुल, विक्रमशीला सेतु के समानांतर 4–लेन पुल, साहेबगंज–मनिहारी के बीच 4–लेन पुल और गंगा नदी पर बक्सर में वर्तमान पुल के समानांतर गंगा नदी पर अतिरिक्त 3–लेन पुल का निर्माण, रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेस–वे के मार्गरेखण पर मटिहानी–साम्हो के बीच 6–लेन पुल का निर्माण और कहलगांव में गंगा नदी पर 4–लेन पुल का निर्माण । सोन नदी, जी॰टी॰ रोड पर बारूण एवं डेहरी–ऑन–सोन के बीच 4–लेन पुल,

दाउदनगर–नासरीगंज के बीच 4–लेन पुल, अरवल–सहार के बीच 2–लेन पुल, कोईलवर 6–लेन नया पुल, कोईलवर में रेल–सह–सड़क पुल...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृपया संक्षेप करें ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, इसके अतिरिक्त सोन नदी पर पाण्डुका में 2–लेन पुल का निर्माण प्रगति में है । वाराणसी–राँची–कोलकाता के पुल का निर्माण, पटना–आरा–सासाराम के पुल का निर्माण भी । गंडक नदी में छितौनी में रेल–सह–सड़क पुल, धनहा–रतवल के बीच 2–लेन पुल, बेतिया–गोपालगंज के बीच 2–लेन पुल, ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर पर डुमरियाघाट पुल, चकिया–केसरिया–सत्तरघाट के बीच 2–लेन पुल, बंगराघाट पर 3–लेन पुल, रेवाघाट पर 2–लेन पुल । इस तरह पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत वाल्मिकी नगर टाईगर रिर्जव....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृपया संक्षेप करें ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : (वी॰टी॰आर॰) बाईपास पर चार 4–लेन पुल, पश्चिम चम्पारण जिला अंतर्गत पतजिरवा में 4–लेन पुल और इसके साथ ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर पर कोसी महासेतु 4–लेन.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शेष पढ़ा हुआ माना जायेगा । आप दे दें प्रोसीडिंग का पार्ट बन जायेगा ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है । महोदय, यह 34 पेज है, अभी हम 14–15 पेज पर ही हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, यह टेलर था ?

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, मैं चाहता हूँ कि आज बिहार का सब रोड और पुल यहाँ बना ही दूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, यह कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा । शेष कार्यवाही का हिस्सा बन जायेगा ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : ठीक है ।

(माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के भाषण का अंश परिशिष्ट–द्रष्टव्य)

टर्न–32 / अंजली / 10.02.2026

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद माननीय सदस्यों को । महोदय, पथ निर्माण विभाग के अधीन क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत विवरणी विभागीय प्रतिवेदन में अंकित कर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रक्षित है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुदान मांग संख्या–41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 74,04,78,53,000 / – (चौहत्तर अरब चार करोड़ अठहत्तर लाख तिरपन हजार रुपए) का अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

डॉ॰ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री : कटौती प्रस्ताव लेने वाले लोग हैं नहीं, तो तीन लोग उधर बैठे हुए हैं, आप ही लोग कटौती प्रस्ताव वापस के लिए हाथ उठा दीजिए, अध्यक्ष महोदय समझ जाएंगे । हाथ उठा दीजिए । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपए से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 8260,16,83,000/– (आठ हजार दो सौ साठ करोड़ सोलह लाख तिरासी हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–10 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–32 (बत्तीस) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–11 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पथ निर्माण विभाग के अनुदान माँग पर

डॉ0 दिलीप कुमार जायसवाल

मंत्री, पथ निर्माण विभाग

का

बजट भाषण 2026–27

माननीय अध्यक्ष महोदय,

बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की रफ्तार को गति प्रदान करने के लिए पथ निर्माण विभाग दृढ़संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के सपनों को साकार करने के लिए पथ निर्माण विभाग राज्य में आधारभूत संरचना का विकास लगातार कर रही है।

महोदय, पथ निर्माण विभाग अब राज्य में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही राज्य के आम जनता के जीवन को आसान बनाने हेतु राज्य अन्तर्गत आवागमन को सुगम बना रही है। इस हेतु पथ निर्माण विभाग एक साथ कई प्रकार के योजनाओं यथा सड़कों के चौड़ीकरण, नदियों पर पुलों का निर्माण, फ्लाईओवर का निर्माण, रेलवे उपरी पुल एवं रेलवे अन्डर ब्रिज का निर्माण इत्यादि का क्रियान्वयन एक साथ कर रही है।

महोदय, श्री नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार के संकल्प के अनुरूप सड़क आधारभूत संरचना का विकास राज्य के अन्दर सुनिश्चित किया जा रहा है। गत वर्ष सदन को अवगत कराया गया था कि विगत बीस वर्षों से पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य में अनवरत सड़कों एवं पुल–पुलियों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण के साथ ही इनके उत्कृष्ट संधारण से राज्य के आम जनता को लगातार लाभ प्राप्त हो

रहे हैं। अब इसे और सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निश्चय किया गया है और इसके क्रियान्वयन हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है ताकि राज्य की जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन में न्यूनतम समय लगे तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत वर्ष की गई प्रगति यात्रा के क्रम में **कुल ₹23974.97 करोड़ (तेईस हजार नौ सौ चौहत्तर करोड़ सनतानवे लाख)** की लागत पर **137** परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुझे सदन को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इन स्वीकृत योजनाओं में से **111 योजनाओं** का कार्य संवेदक को आवंटित किया जा चुका है एवं आवंटित सभी योजनाओं का कार्य प्रगति में है। मार्च, 2026 तक शेष योजनाओं का कार्य शीघ्र आवंटित करते हुए इनके कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने का लक्ष्य है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य के चहुँमुखी विकास की गति में और अधिक तेजी आएगी।

इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग द्वारा विगत एक वर्ष में लगभग **₹14757.57 करोड़ (चौदह हजार सात सौ संतावन करोड सन्तावन लाख) रुपये** की कुल **129 अन्य परियोजनाओं** की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

महोदय, राज्य की अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना **जे0पी0गंगा पथ** का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है एवं इस पथ पर आवागमन सुगम है। अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना को पश्चिम में **दीघा–बिहटा–कोईलवर (लम्बाई– 35.65 कि0मी0)** तक एवं पूरब में **मुंगेर (सफियाबाद)– बरियारपुर– घोरघट– सुल्तानगंज (लम्बाई– 42.00 कि0मी0)** एवं **सुल्तानगंज– भागलपुर–सबौर (लम्बाई – 40.80 कि0मी0)** तक विस्तारित करने हेतु कुल **₹16465. 42 करोड़ (सोलह हजार चार सौ पैंसठ करोड़ बयालीस लाख) रुपये** की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में प्रथम बार इन परियोजनाओं को हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM) पर क्रियान्वित कराने का निर्णय लिया गया है तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण करते हुए संवेदक को कार्य आवंटित कर दिया गया है। इस नवाचार से आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 घंटे में राज्य के सुदूर स्थान से राजधानी पटना पहुँचने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा चुका है। साथ ही राज्य के सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शैक्षणिक, औद्योगिक स्थानों तथा क्षेत्रों का हर जगह से सुलभ सम्पर्कता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के अन्तर्गत किया जा रहा है।

महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य में सड़कों का भी डबल विकास

हो रहा है। महोदय, जहाँ एक ओर केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में 4–लेन एवं 6–लेन हाई स्पीड कोरिडोर एवं एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, वहीं राज्य सरकार ने भी राज्य में एक्सप्रेसवे के निर्माण की ठानी है। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के सात निश्चय–3 ''सुलभ सम्पर्कता का विस्तार अन्तर्गत नये एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण'' के तहत राज्य में इसके निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा एक समिति का गठन किया जा चुका है, जो देश के अन्य राज्यों यथा महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश, जहाँ एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है, का विस्तृत अध्ययन कर प्रतिवेदन समर्पित करेगा। समिति द्वारा भ्रमण कर अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। साथ ही राज्य के सभी धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को 4–लेन सम्पर्कता प्रदान करने की योजना पर भी विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।

महोदय, पहले रेल समपारों पर घंटों यातायात जाम की समस्या बनी रहती थी, परन्तु विगत वर्षों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख रेल समपारों पर रेलवे उपरी पुल एवं रेलवे अन्डर ब्रिज की योजना का क्रियान्वयन किया गया है। अबतक राज्य में 44 रेलवे ऊपरी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा 56 रेलवे ऊपरी पुल का कार्य प्रगति में है। वर्तमान में राज्य में निर्बाध, सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य के अन्दर लगभग सभी रेल समपारों पर रेलवे उपरी पुल एवं रेलवे अन्डर ब्रिज के निर्माण की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।

महोदय, राज्य को सड़क आधारभूत संरचना में समृद्ध बनाने हेतु राज्य सरकार की कोशिश में भारत सरकार से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा भी राज्य में एक्सप्रेसवे, 4–लेन एवं 6–लेन पथों के निर्माण की कई योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही है जिससे आने वाले वर्षों में राज्य अन्तर्गत कई हाई स्पीड कोरिडोर उपलब्ध होगी। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राज्य में

(1) वाराणसी–राँची–कोलकाता एक्सप्रेसवे, कुल 07 पैकेज [प्राक्कलित राशि– ₹10862.63 करोड़ (दस हजार आठ सौ बासठ करोड़ तिरसठ लाख)] में से 04 पैकेज जिसकी कुल लम्बाई –121.70 कि0मी0 तथा है, का कार्य प्रगति में तथा शेष पथांशों के पैकेज में पुनर्मार्गरेखन के उपरांत भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है।

(2) गोरखपुर–सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, लम्बाई–416 कि0मी0, [लागत राशि– ₹23434 करोड़ (तेईस हजार चार सौ चौंतीस करोड़)]

(3) पटना–पूर्णियाँ एक्सप्रेसवे, लम्बाई–245 कि0मी0, [लागत राशि– ₹18242 करोड़ (अठारह हजार दो सौ बयालीस करोड़)]

(4) रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे, भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है एवं

(5) बक्सर–भागलपुर एक्सप्रेसवे, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, DPR तैयार किया जा रहा है।

महोदय राज्य को सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समृद्ध होने से आम जन–जीवन आसान होगा। राज्य के आम जनता को वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित होगी तथा राज्य को आर्थिक तरक्की में और रफ्तार मिलेगी। कृषि उत्पादों का बाजारों/उपभोक्ताओं तक सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा रोजगार के सृजन में काफी बढ़ोत्तरी होगी।

महोदय, अब मैं विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन स्थिति एवं उपलब्धियों से माननीय सदस्यों को पथ श्रेणीवार तथा योजना प्रक्षेत्रवार अवगत कराना चाहूँगा।

1.0 <u>राष्ट्रीय उच्च पथ</u>

महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में कुल **6392 (छः हजार तीन सौ बानवे) कि0मी0** राष्ट्रीय उच्च पथ है, जिसमें **3784 (तीन हजार सात सौ चौरासी)** कि0मी0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं **2608 (दो हजार छः सौ आठ)** कि0मी0 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के अधीन है। भारत सरकार द्वारा राज्य अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथों के चौड़ीकरण के साथ–साथ नये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एवं हाई स्पीड कोरिडोर के निर्माण हेतु योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

महोदय, प्रधान मंत्री पैकेज के तहत लगभग **₹50711 करोड़ (पचास हजार सात सौ ग्यारह करोड़)** की राशि से 75 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें से **51** परियोजनाएँ पूर्ण हो चुकी है, **21** परियोजनाओं का कार्य प्रगति में है तथा 3 परियोजनाओं में निविदा तथा भू–अर्जन कार्य विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

महोदय, राज्य में कुल **1817 (एक हजार आठ सौ सतरह) कि0मी0** राष्ट्रीय उच्च पथ 4–लेन एवं 6–लेन में निर्मित है एवं लगभग **1463 (एक हजार चार सौ तिरसठ) कि0मी0** विभिन्न राष्ट्रीय उच्च पथों का 2–लेन, 4–लेन एवं 6–लेन में निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त राज्य में राजधानी पटना से सभी दिशाओं के लिए 4–लेन सम्पर्कता उपलब्ध हो जायेगा। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय उच्च पथ के महत्वपूर्ण मेगा परियोजनाओं की अद्यतन स्थति निम्नवत् हैः–

1.1 आमस–दरभंगा परियोजना के 4–पैकेज का निर्माण कार्य प्रगति में है – प्राक्कलित राशि – ₹6021.62 करोड़ (छः हजार इक्कीस करोड़ बासठ लाख)

1.2 राष्ट्रीय उच्च पथों के 4–लेनिंग के तहत मुंगेर–मिर्जा चौकी पथ [प्राक्कलित राशि – ₹5885.58 करोड़ (पाँच हजार आठ सौ पचासी करोड़ अंठावन लाख)] एवं किशनगंज– बहादुरगंज पथ

(प्राक्कलित राशि – ₹982.47 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा बख्तियारपुर –मोकामा पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है।

1.3 राष्ट्रीय उच्च पथ सं0–327ई के अररिया–परसरमा पथ [प्राक्कलित राशि – ₹1547.55 करोड़ (एक हजार पाँच सौ सैंतालीस करोड़ पच्चपन लाख)] के 2–लेन के साथ पेभ्डसोलजर निर्माण कार्य हेतु निविदा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

1.4 वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे के चार पैकेजों [प्राक्कलित राशि– ₹10862.63 करोड़ (दस हजार आठ सौ बासठ करोड़ तिरसठ लाख)] में कार्य प्रगति में है शेष पथांशों में पुनर्मार्गरेखन के उपरांत भू–अर्जन का कार्य प्रगति में है)।

1.5 राज्य सरकार के विभिन्न स्तर से राष्ट्रीय उच्च पथ के मेगा परियोजनाओं में भू–अर्जन तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन विभाग से संबंधित मुद्दों का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। फलस्वरूप कई परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं विभिन्न परियोजनाओं का कार्य प्रगति में है।

1.6 केन्द्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ :–

- पटना रिंग रोड [प्राक्कलित राशि– ₹4250.00 करोड़ (चार हजार दो सौ पचास करोड़)] के मार्गरेखन पर गंगा नदी पर शेरपुर–दीघवारा के बीच 6–लेन सेतु निर्माण कार्य प्रगति में।
- पटना जिलान्तर्गत दानापुर–बिहटा ऐलिवेटेड पथ [प्राक्कलित राशि– ₹2980.00 करोड़ (दो हजार नौ सौ अस्सी करोड़)] का निर्माण कार्य प्रगति में।

- मधुबनी जिलान्तर्गत भेजा–बकौर के बीच कोशी नदी पर पुल [प्राक्कलित राशि– ₹1199.00 करोड़ (एक हजार एक सौ निन्यानवे करोड़)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- सिवान जिलान्तर्गत मेहरौना–सीवान पथ एवं सिवान– मशरख पथ (राम जानकी मार्ग) [प्राक्कलित राशि– ₹3092.61 करोड़ (तीन हजार बानवे करोड़ इकसठ लाख)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- गंगा नदी पर जे0पी0 सेतु के समानान्तर 6–लेन पुल [प्राक्कलित राशि– ₹3005.80 करोड़ (तीन हजार पाँच करोड़ अस्सी लाख)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल [प्राक्कलित राशि– ₹2926.42 करोड़ (दो हजार नौ सौ छब्बीस करोड़ बयालीस लाख)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशीला सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल [प्राक्कलित राशि– ₹1110.23 करोड़ (एक हजार एक सौ दस करोड़ तेईस लाख)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी – साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर पुल [प्राक्कलित राशि– ₹1900.08 करोड़ (एक हजार नौ सौ करोड़)] का निर्माण कार्य प्रगति में।
- वाराणसी–कोलकाता एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 पैकेज में कार्य प्रगति में [प्राक्कलित राशि– ₹10862.63 करोड़ (दस हजार आठ सौ बासठ करोड़ तिरसठ लाख)]।

महोदय, राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। **पशुपतिनाथ–बैद्यनाथ हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एलाईगमेंट भीमनगर से चानन (लगभग 250 कि0मी0)** एवं **नारायणी–गंगा हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर (लगभग 225 कि0मी0) बगहा NH-727A से पातर तक** (भोजपुर जिला) की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ताकि सुगम आवागमन के साथ ही राज्य में राष्ट्रीय उच्च पथ की लम्बाई में वृद्धि हो सके।

- पशुपतिनाथ–बैद्यनाथ कोरिडोर– नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से बैद्यनाथ धाम झारखण्ड तक प्रस्तावित है जो राज्य में पसराहा, अगुवानी घाट, सुलतानगंज, कटोरिया, चानन से होकर गुजरेगा।
- नारायणी गंगा कोरिडोर बनने से भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिला को त्वरित सम्पर्कता मिलेगी।

2.0 राज्य उच्च पथ

2.1 महोदय, राज्य के सभी राज्य उच्च पथों को कम से कम 2–लेन मानक संरचना में उन्नयन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के तहत **3617 कि0मी0** राज्य उच्च पथों में से लगभग **3100 कि0मी0** का 2–लेन अथवा 4–लेन में उन्नयन किया जा चुका है तथा लगभग

314 कि0मी0 के चौड़ीकरण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

2.2 एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के वित्त पोषण से कुल **1830** कि0मी0 राज्य उच्च पथों का 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग **314** कि0मी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2.3 एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के वित्त पोषण से BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत सभी 6 राज्य उच्च पथों (i) मानसी–सिमरी बख्तियारपुर पथ (SH-95) (ii) कटिहार–बलरामपुर पथ (SH-98) (iii) वायसी–बहादुरगंज– दीघलबैंक पथ (SH-99) (iv) बेतिया–नरकटियागंज पथ (SH-105) (v) अम्बा–देव–मदनपुर पथ (SH-101) एवं (vi) मंझवे–गोविन्दपुर पथ (SH-103) कुल लम्बाई 266.55 **कि०मी०** का **₹2680.35 करोड़ (दो हजार छः सौ अस्सी करोड़ पैंतीस लाख)** की लागत से 2 लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य प्रगति में है।

2.4 महोदय, BSHP-IV (Phase-I) के अन्तर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के वित्त पोषण से कुल **₹2900.88 करोड़ (दो हजार नौ सौ करोड़ अठासी लाख)** की अनुमानित लागत से 04 पथों (कुल लम्बाई–225.48 कि0मी0) एवं एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो निम्नवत् हैः–

- नवादा एवं गया जिलान्तर्गत बनगंगा– जेठियन–गहलौत–भिन्डस (NH-82) पथ (लम्बाई–41.256 कि0मी0, लागत–**₹361.325 करोड़**)
- बांका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत धोरैया–इंगलिस मोड़–असरगंज पथ (लम्बाई–58.473 कि0मी0, लागत–**₹650.51 करोड़**),
- सारण एवं सिवान जिलान्तर्गत छपरा– मांझी– दरौली–गुठनी पथ (लम्बाई–72.183 कि0मी0, लागत–**₹701.26 करोड़**),
- भोजपुर जिलान्तर्गत आरा–एकौना–खैरा–सहार पथ (लम्बाई–32.263 कि0मी0, लागत–**₹373.56 करोड़**),
- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हथौड़ी–औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल का पहुँच पथ सहित निर्माण कार्य (लागत–**₹814.22 करोड़**)

इन परियोजनाओं का कार्य संवेदक को आवंटित कर दिया गया है।

2.5 महोदय, BSHP-IV (Phase-II) के अन्तर्गत एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के वित्त पोषण से कुल **₹3743.65 करोड़ (तीन हजार सात सौ तैंतालीस करोड़ पैंसठ लाख)** की अनुमानित लागत से 03 राज्य उच्च पथों एवं 02 वृहद् जिला पथों (कुल लम्बाई–**266.17 कि0मी0**) के उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है एवं प्रशासनिक स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जो निम्नवत् है:–

- सुपौल एवं अररिया जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–92 (गणपतगंज – परवाहा पथ, लम्बाई–47.432 कि0मी0, लागत–**₹703.95 करोड़**)
- सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–52 (सीतामढ़ी – पुपरी – बेनीपट्टी पथ, लम्बाई–51.261 कि0मी0, लागत–**₹434.37 करोड़**),
- दरभंगा एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत राज्य उच्च पथ सं0–97 (अतरबेल– जाले–घोघरचट्टी पथ, लम्बाई–47.875 कि0मी0, लागत–**₹990.03 करोड़**),
- मधुबनी जिला अन्तर्गत मधुबनी–राजनगर–बाबू बरही–खुटौना पथ, लम्बाई– 38.872 कि0मी0 लागत– 632.72 करोड़
- बक्सर जिला अन्तर्गत इटाढ़ी–सरंजा–जलीलपुर पथ तथा इटाढ़ी–बक्सर सम्पर्क मार्ग एवं उजियारपुर समदा सम्पर्क मार्ग, लम्बाई– 80.728 कि0मी0, लागत– 982.58 करोड़

2.6 महोदय, राज्य अन्तर्गत राज्य उच्च पथों की कुल लम्बाई अपेक्षाकृत बढ़ाने हेतु लगभग **3000 कि0मी0 नये राज्य उच्च पथों** की घोषणा हेतु विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

3.0 <u>वृहद जिला पथ</u>

महोदय, पथ निर्माण विभाग के अधीन वर्तमान में कुल **16784 कि0मी0 (सोलह हजार सात सौ चौरासी कि0मी0)** वृहद जिला पथ है, जिसमें से **5343 कि0मी0** सिंगल लेन है। वर्तमान में लगभग **2000 कि0मी0** के उन्नयन कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है।

सात निश्चय–3 **"सुलभ सम्पर्कता का विस्तार – ग्रामीण सड़कों का चरणबद्ध ढंग से 2–लेन चौड़ीकरण करना"** के तहत ग्रामीण सड़कों का 2–लेन में चौड़ीकरण का निश्चय किया गया है। महोदय, ग्रामीण सड़कों के 2–लेन में चौड़ीकरण को पूर्ण उपयोगी बनाये जाने हेतु यह आवश्यक है कि पथ निर्माण विभाग की सभी सड़कें कम से कम 2–लेन चौड़े हों। अतः पथ निर्माण विभाग की सभी सिंगल लेन पथों को 2–लेन में चरणबद्ध तरीके से चौड़ीकरण की योजना है।

<u>सात निश्चय पार्ट–।।: सुलभ सम्पर्कता (बाईपास/एलिवेटेड पथ)</u>

3.1 महोदय, राज्य में सुगम एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित करने हेतु सात निश्चय पार्ट–।। : सुलभ सम्पर्कता के तहत राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाईपास एवं फ्लाईओवर के निर्माण योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

3.2 इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल **8** बाईपास (**₹143.16 करोड़**), वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल **12** बाईपास (**₹412.98 करोड़**) एवं 2023–24 में कुल **05** बाईपास (**₹412.98 करोड़**), वर्ष 2024–25 में कुल **19** बाईपास (**₹1921.62 करोड़**) तथा वर्ष 2025–26 में कुल **06** बाईपास (**₹166.70 करोड़**) की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। इस प्रकार कुल 50 बाईपास योजनाओं में से अबतक **17** योजनाएँ पूर्ण की

जा चुकी है तथा 18 योजनाएँ विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है। शेष 15 बाईपास योजनाएँ निविदा निष्पादन के प्रक्रियाधीन है।

नाबार्ड (NABARD) सम्पोषित

3.3 महोदय, राज्य के चहुँमुखी विकास को दृष्टिपथ रखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की गति को तीव्र एवं सुगम बनाने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड ऋण योजनान्तर्गत 106 पथ एवं पुल परियोजनाओं का **₹3342.54 करोड़ (तीन हजार तीन सौ बयालीस करोड़ चौवन लाख)** की लागत से क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है।

शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) सम्पोषित

3.4 महोदय, राज्य अन्तर्गत सड़क आधारभूत संरचना की समृद्धि हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा UIDF योजनान्तर्गत 39 पथ एवं पुल परियोजनाओं का **₹1973.55 करोड़ (एक हजार नौ सौ तिहतर करोड़ पच्चपन लाख)** की लागत से क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में प्रगतिशील है।

केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF)

3.5 महोदय, केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत राज्य में कुल 199.40 कि0मी0 पथों का उन्नयन कार्य प्रगति में है। केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के अन्तर्गत प्रगतिशील महत्वपूर्ण परियोजनाएँ निम्नवत् है:–

- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के नजदीक उच्चस्तरीय पुल (**₹69.58** करोड़) – **कार्य प्रगति में।**
- सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज विशुनपुरा बाईपास पथ (**₹228.53** करोड़)– **भू–अर्जन कार्य प्रक्रियाधीन।**
- सारण जिला अन्तर्गत अमनौर बाजार बाईपास पथ (**₹69.23** करोड़) – **कार्य प्रगति में।**
- सारण जिला अन्तर्गत गरखा बाईपास पथ (**₹91.87** करोड़) – **कार्य प्रगति में।**
- सारण जिला अन्तर्गत परसा बाजार बाईपास पथ (**₹85.24** करोड़) – **कार्य प्रगति में।**

- बिहार–झारखण्ड की सीमा पर रोहतास जिलान्तर्गत पण्डुका के पास सोन नदी पर **₹210.13 करोड़** की लागत से 1500 मीटर लम्बे उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण **कार्य प्रगति में** है।
- केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) से सेतु बंधन (2022–23) अन्तर्गत राज्य के 15 ROB में राज्यांश हेतु ₹669.29 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जो क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना (RCPLWEA) :

3.6 राज्य के अति वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में संचार एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण ''वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क योजना (RCPLWEA)" को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत Separate vertical के रूप में अनुमोदित किया गया है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा RCPLWEA योजना के तहत् वर्ष 2017–18 से 2022–23 तक राज्य के आठ जिले – औरंगाबाद, गया, नवादा, बांका, जमुई, रोहतास, लखीसराय एवं मुजफ्फरपुर में **153 अद्द पथ** पैकेज (कुल लम्बाई **1980.80 कि0मी**) एवं **82 पुल** पैकेज की निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन योजनाओं की पथ संधारण सहित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि **₹3181.18 करोड़** मात्र है, जिसमें केन्द्रांश की राशि **₹1390.14 करोड़** एवं राज्यांश की राशि **₹1791.04 करोड़** है।

वर्तमान में 130 पथों (**1813.89 कि0मी0** लम्बाई) एवं 72 पुलों में निर्माण कार्य पूर्ण है। पूर्ण हो चुके पथों एवं पुलों का 05 वर्षीय अनुरक्षण कार्य राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से कुल 19 पथों, लम्बाई 109.79 कि0मी0 एवं 6 पुलों को foreclose/ drop कर

दिया गया है। बचे हुए योजनाओं यथा 04 पथों एवं 04 पुलों का निर्माण कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजनाः

3.7 भारत–नेपाल सीमा परियोजना अन्तर्गत बिहार राज्य में कुल **554.08 कि०मी०** में निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना सीमावर्त्ती सात जिलों यथा पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज से गुजरता है जो पश्चिमी चम्पारण के मदनपुर से आरंभ होकर किशनगंज जिला के गलगलिया में समाप्त होता है।

इस पथ के निर्माण से सीमा पार शस्त्र एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के साथ–साथ सीमावर्त्ती इलाकों में सुगम यातायात की सुविधा प्रदान होगी जिससे इस क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

इस परियोजना में निर्माण कार्य का वित्तीय वहन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जा रही है। भू–अर्जन, Utility Shifting एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस में आने वाले व्यय सहित इस मार्गरेखण पर कुल **132 उच्चस्तरीय पुलों** का निर्माण राज्य सरकार के निधि से किया जा रहा है।

वर्तमान में 519 **कि०मी०** पथ एवं 121 **उच्चस्तरीय** पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के शेष कार्य को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4.0 रेलवे ओवर ब्रिज (ROB)

महोदय, राज्य में निर्बाध, सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार से कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण किया जा रहा है।

4.1 वर्तमान MOU से पूर्व कुल 16 ROB का निर्माण स्वीकृत था जिसमें से अबतक 11 अदद ROB का कार्य पूर्ण है एवं 5 अदद् ROB का निर्माण कार्य प्रगति में है।

4.2 वर्तमान MOU के अन्तर्गत 41 ROB का निर्माण कार्य स्वीकृत है जिसमें 38 अदद् का कार्य आवंटित है तथा 3 अदद् का निविदा प्रक्रियाधीन है।

4.3 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निम्न ROB का कार्य प्रगति पर हैः–

- भागलपुर में मिरजान हाट के नजदीक पुल संख्या 152
- पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास
- नालन्दा जिलान्तर्गत हरनौत रेल फैक्ट्री के निकट समपार सं0 10/सी
- नवादा बाईपास अन्तर्गत समपार संख्या–28A/T पर ROB का निर्माण

➢हिलसा बाईपास अन्तर्गत समपार संख्या–18 एवं 23 पर ROB का निर्माण

5.0 प्रमुख नदियों पर पुलों का निर्माण

महोदय, राज्य अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य की प्रमुख नदियों पर पर्याप्त पुलों का निर्माण अतिआवश्यक है। विगत वर्षों में राज्य एवं केन्द्र सरकार के प्रयास से राज्य की प्रमुख नदियों पर कई मेगा पुलों के निर्माण के साथ ही अन्य नदियों पर भी भारी संख्या में पुल एवं पुलियों का निर्माण कार्य किया गया है तथा वर्तमान में भी कई परियोजनाएँ प्रगतिशील है।

महोदय, अब मैं राज्य के प्रमुख नदियों पर निर्मित/निर्माणाधीन पुलों की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहूँगा।

5.1 गंगा नदी

राज्य में गंगा पर पूर्व से निर्मित पुलः–

(1) बक्सर में गंगा नदी पर 2–लेन पुल
(2) आरा – छपरा के बीच गंगा नदी पर 4–लेन पुल
(3) दीघा–सोनपुर रेल–सह–सड़क पर 2–लेन पुल
(4) महात्मा गाँधी सेतु 4–लेन पुल
(5) मोकामा में रेल–सह–सड़क 2–लेन पुल (राजेन्द्र सेतु)
(6) मुंगेर में रेल–सह–सड़क सेतु 2–लेन (श्री कृष्ण सेतु)
(7) भागलपुर में विक्रमशीला सेतु 2–लेन
(8) औंटा – सिमरिया के बीच 6–लेन पुल

गंगा नदी पर निम्नलिखित पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है:–

(1) दीघवारा–शेरपुर के बीच 6–लेन पुल
(2) जे0पी0 सेतु के समानान्तर 6–लेन पुल
(3) महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल
(4) कच्चीदरगाह – बिदुपुर के बीच 6–लेन पुल
(5) बख्तियारपुर – ताजपुर के बीच 4–लेन पुल
(6) अगुवानीघाट – सुल्तानगंज के बीच 4–लेन पुल
(7) विक्रमशीला सेतु के समानान्तर 4–लेन पुल
(8) साहेबगंज – मनिहारी के बीच 4–लेन पुल

गंगा नदी पर निम्नलिखित पुलों का निर्माण प्रस्तावित है:–

(1) बक्सर में वर्तमान पुल के समानान्तर गंगा नदी पर अतिरिक्त 3–लेन पुल का निर्माण।
(2) रक्सौल–हल्दिया एक्सप्रेसवे के मार्गरेखण पर मटिहानी – सामो के बीच 6–लेन पुल का निर्माण।
(3) कहलगाँव में गंगा नदी पर 4–लेन पुल के निर्माण

5.2 सोन नदी

राज्य के अन्तर्गत बहने वाली अन्य महत्वपूर्ण नदियों में सोन नदी के ऊपर निम्नलिखित पुल पूर्व से निर्मित है:–

(1) जी0टी0 रोड पर बारूण एवं डेहरी–ऑन–सोन के बीच 4–लेन पुल
(2) दाउदनगर – नासरीगंज के बीच 4–लेन पुल
(3) अरवल – सहार के बीच 2–लेन पुल
(4) कोईलवर 6–लेन नया पुल
(5) कोईलवर में रेल–सह–सड़क पुल

इसके अतिरिक्त सोन नदी पर पाण्डुका में 2–लेन पुल का निर्माण प्रगति में है तथा निम्नलिखित पुलों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगाः–

(1) वाराणसी – राँची – कोलकाता के मार्गरेखण पर पुल निर्माण

(2) पटना – आरा – सासाराम के मार्गरेखण पर पुल का निर्माण

5.3 <u>गंडक नदी</u>

<u>राज्य के अन्तर्गत बहने वाली गंडक नदी के ऊपर निम्नलिखित पुल पूर्व से निर्मित है</u>:–

(1) छितौनी में रेल–सह–सड़क पुल
(2) धनहा – रतवल के बीच 2–लेन पुल
(3) बेतिया–गोपालगंज की बीच 2–लेन पुल
(4) ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर पर डुमरियाघाट पुल
(5) चकिया – केसरिया – सत्तरघाट के बीच 2–लेन पुल
(6) बंगराघाट पर 3–लेन पुल
(7) रेवाघाट 2–लेन पुल

इसके अतिरिक्त गंडक नदी पर हाजीपुर में 4–लेन पुल, एन0एच0–139डब्लू के मार्गरेखण पर कोन्हवाघाट में 4–लेन पुल एवं डुमरियाघाट में वर्तमान पुल के समानान्तर 2–लेन पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा निम्नलिखित पुलों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगाः–

(1) पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत बाल्मिकी टाईगर रिर्जव (वी0टी0आर0) बाईपास पर नये 4–लेन पुल का निर्माण

(2) पश्चिमी चम्पारण जिला अन्तर्गत पतजिरवा में एन0एच0–727AA के मार्गरेखण पर 4–लेन पुल का निर्माण

(3) गोरखपुर–सिलीगुड़ी के मार्गरेखण पर 6–लेन पुल का निर्माण

(4) रामजानकी मार्ग के मार्गरेखण पर सत्तरघाट में 4–लेन पुल का निर्माण

5.4 कोसी नदी

राज्य के अन्तर्गत बहने वाली कोसी नदी के ऊपर निम्नलिखित पुल पूर्व से निर्मित हैः–

(1) ईस्ट–वेस्ट कोरिडोर पर कोसी महासेतु 4–लेन

(2) गंडौल–बिरौल के बीच बलुआहा घाट पुल 2–लेन

(3) डुमरीघाट में बी0पी0 मंडल सेतु 2–लेन

(4) विजय घाट पुल 4–लेन

(5) कुरसेला में रा0उ0प0–31 पर अतिरिक्त 2–लेन

इसके अतिरिक्त कोसी नदी पर भेजा – बकौर में एन0एच0–527ए एवं फुलौत में एन0एच0–106 के मार्गरेखण पर थाना बीहपुर के पास पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है तथा निम्नलिखित पुलों का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जाएगाः–

(1) गोरखपुर – सिलीगुड़ी के मार्गरेखण पर 6–लेन पुल का निर्माण

(2) पटना–पूर्णियाँ के मार्गरेखण पर सिमरी–बख्तियारपुर के पास 6–लेन पुल

(3) कुरसेला में अतिरिक्त 2–लेन पुल

5.5 इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न नदियों पर अनेकों पुल का निर्माण कराकर राज्य में निर्बाध आवागमन की सुविधा सुनिश्चित किया जा रहा है।

6.0 अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँ :–

6.1 जे0पी0 गंगा पथ

- कुल **₹4119.06 करोड़** (चार हजार एक सौ उन्नीस करोड़ छः लाख) की लागत से **20.50 कि0मी0** लम्बाई में निर्माणाधीन इस परियोजना के तहत **दीघा से दीदारगंज तक (20.5 कि0मी0)** का लोकार्पण किया जा चुका है एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित हो रहा है।
- **पटना साहिब रेलवे स्टेशन से पटना घाट तक रेलवे लाईन के स्थान पर 4–लेन सम्पर्क पथ का निर्माण कार्य** जून 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है।

6.2 कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच 6–लेन नया गंगा पुल

- एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के वित्त पोषण से **राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 30 स्थित कच्ची दरगाह से राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 103 स्थित बिदुपुर के बीच**

गंगा नदी पर 6–लेन ग्रीनफिल्ड पुल परियोजना (₹4988.40 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसमें पुल की लम्बाई 9.76 कि0मी0 एवं पहुँच पथ की लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। इस परियोजना को अप्रैल, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6.3 बख्तियारपुर–ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ पुल परियोजना–

जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–31 के प्रस्तावित बाईपास में करजान गाँव से राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या –28 में ताजपुर को जोड़नेवाली गंगा नदी पर कुल **₹3923.00 करोड़** की लागत से 5.55 कि0मी0 लम्बाई के 4–लेन पुल एवं 45.393 कि0मी0 4–लेन पहुँच पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं इसे जून 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

6.4 मीठापुर से रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट तक पथ का निर्माण–

मीठापुर से रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट तक 8.86 कि0मी0 लंबे 4–लेन एलीवेटेड पथ **₹1030.59 करोड़** रू0 की लागत से कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त **मीठापुर–सिपारा– महुली–पुनपुन तक रेलवे लाईन के पूरब में मीठापुर से सिपारा (सिपारा में 2**

Way ROB सहित) 4–लेन एलिभेटेड पथ (लंबाई–2.100 कि॰मी॰) एवं रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट से पुनपुन (लक्ष्मण झूला) तक 4–लेन एट ग्रेड पथ (लंबाई 2.200 कि॰मी॰), कुल लंबाई 4.3 कि॰मी॰ का ₹437.15 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य प्रगति में है। महुली हॉल्ट से पुनपुन अंश का कार्य कर लोकार्पित कर दिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति में है।

6.5 **कारगिल चौक से साईन्स कॉलेज तक डबल डेकर एलिवेटेड कोरिडोरः**

कुल **₹422.00 करोड़** की लागत से गाँधी मैदान के कारगिल चौक से साईन्स कॉलेज, पटना तक कुल 2.20 कि0मी0 में डबल डेकर एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य पूर्ण कर इसे लोकार्पित किया जा चुका है।

7.0 दीर्घकालीन पथ प्रबंधन एवं अनुरक्षण नीति

7.1 पथ निर्माण विभाग पथों के निर्माण के साथ उनके उत्कृष्ट संधारण हेतु कृत संकल्पित है। विभाग द्वारा अभिनव प्रयोग के अन्तर्गत OPRMC प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् OPRMC द्वितीय चरण में **13064 कि0मी0 (तेरह हजार चौंसठ कि0मी0)** पथों का संधारण किया जा रहा है जो अब अंतिम चरण में है।

7.2 सात निश्चय–3 अन्तर्गत पथों के दीर्घकालिक प्रभावी अनुरक्षण एवं रख–रखाव के तहत वर्ष 2026 से 2033 तक कुल 19353 कि0मी0 राज्य उच्च पथों एवं वृहद जिला पथों के सतत् उत्कृष्ट संधारण हेतु प्राक्कलन एवं निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत 7 वर्षों तक सतत् उत्कृष्ट रख–रखाव हेतु लगभग **22 हजार करोड़ रुपये** की लागत अनुमानित है।

7.3 पथों के संधारण के लिए साक्ष्य आधारित आधुनिक तकनीक Artificial Intelligence and Manchine Learning (AIML) का उपयोग करते हुए मोबाइल ऐप तथा वेब ऐप के माध्यम से पथों का सतत् अनुश्रवण किया जायेगा। वास्तविक काल (Real Time) अनुश्रवण के लिए मुख्यालय में **कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर** (Control and Command Centre) कार्यरत है। इसके माध्यम से क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण चक्र सुनिश्चित करते हुए पथों में पाये जा रहे त्रुटियों का विश्लेषण कर मजबूतीकरण की कारवाई सुनिश्चित की जा रही है।

8.0 <u>पुल संधारण</u>

राज्य में बढ़ती पुलों की संख्या को देखते हुए पुलों के उत्कृष्ट संधारण एवं रख–रखाव हेतु पुल अनुरक्षण प्रबंधन मार्गदर्शिका क्षेत्रीय पदाधिकारियों को उपलब्ध है। इसके साथ ही विभाग द्वारा बिहार राज्य

पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति, 2025 लागू की जा चुकी है। वर्तमान में 250 मीटर से अधिक लम्बाई वाले 85 पुलों का Audit का कार्य IIT पटना से कराने हेतु MOU किया गया है। 60 मीटर से 250 मीटर तक के पुलों का Audit राज्य स्थित Engineering College से एवं 6 मीटर से 60 मीटर तक के पुलों का Audit बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0 द्वारा कराया जा रहा है।

9.0 सड़क सुरक्षा

9.1 वर्तमान में सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से पथ निर्माण विभाग द्वारा पैदलयात्रियों की सुविधा हेतु पटना में सेंट कैरंस स्कूल, खगौल के निकट फुट ओभर ब्रीज (FOB) का निर्माण कार्य किया गया है एवं चालु अवस्था में है। कंकड़बाग रोड में बापू परीक्षा परिसर के निक़ट फुट ओभर ब्रीज के निर्माण हेतु निविदा की प्रक्रिया की गयी है। पैदलयात्रियों की सुविधा हेतु नेहरू पथ पर जेब्रा क्रांसिग रिपेंटिंग का कार्य किया गया है। पैदलयात्रियों एवं वाहनों की सुविधा हेतु PUP (People Under Pass) एवं VUP (Vehicle Under Pass) का प्रावधान एवं निर्माण किया जा रहा है।

9.2 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में आवारा कुत्तों/ पशुओं (Stray Animals) से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करने हेतु पथ निर्माण विभाग द्वारा राष्ट्रीय

उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं वृहत जिला पथों पर आवारा कुत्तो/पशुओं के सतत् निगरानी हेतु प्रत्येक प्रमंडल में पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है तथा आवारा कुत्तो/पशुओं से प्रभावित जगहों को चिन्हित किया गया है। पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है तथा संबंधित पदाधिकारी से संपर्क कर आवारा कुत्तो/पशुओं को नजदीक के Designated शेल्टर में ले जाने की कार्रवाई जा रही है।

9.3 पथ निर्माण विभाग द्वारा दुर्घटनाओं के रोक–थाम के लिए पथों का सड़क सुरक्षा अकेंक्षण (Road Safety Audit) का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा अंकेक्षण के सभी सुझावों यथा– जंक्शन उन्नयन, दुर्घटना प्रवण स्थानों पर यातायात शांत करने के उपाय, रोड साईनेज, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिन्ह एवं रम्बल स्ट्रीप इत्यादि का कार्य नई संविदा प्रणाली OPRMC के अंतर्गत किया जाना है, ताकि दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके। वर्त्तमान में अटल पथ एवं गंगा पथ पर अधिकतम गति सीमा 80 कि0मी प्रति घंटा से 60 कि0मी0 प्रति घंटा किया गया है ताकि दुर्घटना में कमी लायी जा सके।

9.4 राज्य सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉट एवं अन्य दुर्घटना प्रवण स्थलों के संरचनात्मक सुधार एवं सड़क सुरक्षा उपाय लगातार किया जाता है। पथ निर्माण विभाग द्वारा इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस

(iRAD) में दुर्घटना प्रवण स्थलों पर सड़क सुरक्षा अभियांत्रिकी उपाय कर परिमार्जन कार्य किया जा रहा है।

10.0 <u>नई नियुक्तियाँ</u>

10.1 सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसके अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के सीधी भर्ती योग्य कुल रिक्ति–123 पदों तथा सहायक अभियंता (यांत्रिक) के सीधी भर्त्ती योग्य कुल रिक्ति–12 पदों के रोस्टर क्लीयरेंस के उपरांत सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

10.2 विभाग द्वारा कुल 414 कनीय अभियंता (असैनिक), 9 कनीय अभियंता (यॉत्रिक) एवं 01 कनीय अभियंता (विद्युत) अर्थात् कुल 424 कनीय अभियंताओं के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है।

10.3 मुख्यालय स्थापना अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के पद हेतु कुल 48 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से की गई है। मुख्यालय अन्तर्गत कार्यालय परिचारी कोटि– IV के कुल 33 पदों (खिलाड़ी कोटा का 07 पद सहित) की भी अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से की गई है।

10.4 विभाग के क्षेत्रीय स्थापना अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के कुल–177 पद, अमीन के कुल–62 पद एवं कार्यालय परिचारी के लिए कुल–338 पद की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित है। इसके अतिरिक्त शोध सहायक के 83 पद के रोस्टर क्लीयरेंस के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

11.0 तकनीकी प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता

11.1 विभागीय अभियंताओं को नवीनतम तकनीक से लैश कर उन्हें कार्यकुशलता में दक्ष बनाने हेतु कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण यथा– Induction Course, Orientation Course एवं Refresher Course का नियमित आयोजन वाल्मी, पटना में किया जाता है। साथ ही देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों यथा– केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, ASCI, हैदराबाद; IAHE, नोएडा; NICMAR, पुणे एवं IIT जैसे संस्थानों में लगातार कई वर्षों से विभाग के अभियंताओं को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है एवं Webinar के माध्यम से अभियंताओं को नवीन तकनीक से अवगत कराया जा रहा है। विगत वर्ष जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक कुल 25 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल 1310

अभियंताओं का प्रशिक्षण कराया गया है। साथ ही अभियंत्रण एवं पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत कुल 443 छात्र/छात्राओं को इन्टर्नशिप / इन–प्लान्ट ट्रेनिंग / इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग / वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत पथ निर्माण विभाग के विभिन्न प्रमंडलों, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0 एवं परीक्षण एवं शोध संस्थान में प्रशिक्षण कराया गया है।

11.2 मुख्यालय में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक राज्य स्तरीय गुण नियंत्रण जाँच प्रयोगशाला स्थापित है, जिसमें जाँच एवं शोध की सुविधा उपलब्ध है। इस गुणवत्ता प्रबंधन के अतिरिक्त गुणवत्ता क्रियान्वयन से संबंधित प्रमंडल एवं अंचल स्तर पर गुण नियंत्रण इकाई भी कार्यरत है। माह जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक कुल 382 बिटुमिनस एवं 587 नन बिटुमिनस नमूनों का जाँच सम्पादित किया गया है।

12.0 सात निश्चय–3 (2025–2030)

12.1 सात निश्चय–3, वर्ष– 2025 से 2030 अन्तर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं नीति लागू की गई है। इस नीति के घटक मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार के तहत् नये एक्सप्रेस–वे सड़कों का निर्माण किया जाना है।

महोदय, पथ निर्माण विभाग के अधीन क्रियान्वित की जा रही सभी परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत विवरणी विभागीय प्रतिवेदन में अंकित कर माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रक्षित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए अनुदान माँग संख्या–41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का **₹74,04,78,53,000/- (चौहत्तर अरब चार करोड़ अठहत्तर लाख तिरपन हजार रूपये)** का अनुदान माँग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।